सच को झुठलाना न केवल खुदकुशी करने जैसा है, बल्कि समाज की पीठ में छुरा घोंपना भी है। -राल्फ वाल्डो इमर्सन

स्पेसएक्स और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क का ट्रंप प्रशासन के डीओजीई से अलग होने का एलान कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे संकेत मिल रहे थे, उनके मद्देनजर यह कदम स्वाभाविक है और इसका यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि वह ट्रंप समर्थक समूह से बाहर हो गए।

मस्क और ट्रंप

स्पेसएक्स और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क का ट्रंप प्रशासन के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (डीओजीई) यानी खर्च कटौती विभाग से अलग होने का एलान कुछ लोगों के लिए आश्चर्यजनक हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे संकेत मिल रहे थे, उनके मद्देनजर यह स्वाभाविक ही है। दरअसल, मस्क ऐसे समय में पद छोड़ रहे हैं, जब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप प्रशासन के अंदरूनी लोगों में उन्हें लेकर निराशा है। लेकिन दूसरी ओर ऐसी खबरें भी हैं, जो कहती हैं कि ट्रंप मस्क की डीओजीई पहल और इसकी गतिविधियों से काफी खुश हैं और अगर किसी को लगता है कि मस्क ट्रंप की कक्षा से गायब होने वाले हैं, तो यह खुद को मूर्ख बनाने जैसा ही होगा। सच कुछ भी हो, लेकिन तथ्य यह है कि मस्क का यह निर्णय विशेष सरकारी कर्मचारी की उनकी स्थिति के नियमों के ही अधीन है, जो उन्हें केवल 130 दिनों तक सेवा की अनुमति देता है। पिछले ही महीने ट्रंप ने इस बात के संकेत दिए थे कि मस्क जल्द ही अपनी वर्तमान भूमिका से अलग होंगे, वहीं मस्क ने भी कहा था कि अब वह अपने धंधों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। लिहाजा एक उद्यमी की तरह उठाया गया उनका यह कदम ट्रंप के साथ उनकी साझेदारी के अंत को नहीं, बल्कि यह अपनी ऊर्जा को निजी व्यवसायों में पुनर्निर्देशित करने की उनकी इच्छा को ही अधिक दर्शाता है। गौरतलब है कि जब फेसबुक और तत्कालीन ट्विटर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन की सेवा में रत थे, तब ट्रंप के बारे में मस्क के विचार भी अधिक सकारात्मक नहीं थे। लेकिन ट्रंप के 2024 के राष्ट्रपति अभियान के दौरान मस्क ने करोड़ों डॉलर का योगदान देने के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिये भी ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। डीओजीई का नेतृत्व सौंपे जाने पर मस्क ने कई ऐसे कदम उठाए, जो ट्रंप के सुधारवादी एजेंडे के अनुरूप थे और मस्क की व्यावसायिक दक्षता को सरकारी क्षेत्र में लागू करने की ट्रंप की मंशा को उजागर करते थे। ट्रंप के टैरिफ और एक अन्य प्रस्तावित विधेयक पर मस्क के रुख को उनके रिश्तों में कथित तनाव का कारण बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ट्रंप, मस्क के योगदान की सराहना करते रहे हैं और मस्क ने भी डीओजीई की नींव को मजबूत करने का श्रेय ट्रंप को दिया है, उसे देखते हुए मस्क के निर्णय को इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि वह ट्रंप समर्थक समूह से बाहर हो गए हैं।

जीवन धारा

एडम ग्रांट

हमें हमेशा बताया जाता है कि काम को जल्द शुरू करना चाहिए। लेकिन टालमटोल करना जितना अवगुण है, उतना ही सद्गुण भी हो सकता है। बस समझने की जरूरत है कि काम को टालने का हमारा उद्देश्य क्या है?

काम को टालना भी सफलता की कुंजी है

काम या जिंदगी की बात हो, तो हमें हमेशा बताया जाता है कि काम को जल्द शुरू करना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन मैं यहां टालमटोल की चर्चा करूंगा। टालमटोल करना जितना अवगुण है, उतना ही सद्गुण भी हो सकता है। हालांकि, देरी करना जोखिम का काम हो सकता है, आप देखेंगे कि इंतजार आपको अपना सबकुछ दांव पर लगाने से रोक भी सकता है। यहां समझा देना चाहता हूं कि काम तो समय पर ही करना चाहिए, लेकिन कई बार जल्दबाजी या नामसझी में काम को पहले निपटाने के चक्कर में हम गड़बड़ी कर बैठते हैं। निराश होने के लिए आपका सबसे पहले पहल करना जरूरी नहीं होता। आप जब टालमटोल कर रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि आप जानबूझकर उस काम को टरका रहे हैं। 28 अगस्त, 1963 को मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया 'आई हेव ए ड्रीम' भाषण इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, लेकिन यकीन मानिए इस भाषण को तैयार करने के लिए उन्होंने बहुत टालमटोल की थी। किंग की पत्नी कोरेटा के मुताबिक, किंग अपनी सभा के लिए पूरी रात काम करते रहे और उन्होंने पलकें तक नहीं झपकाईं। अंतिम भाषण उन्हें देना था और उनके शब्द अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लाखों लोगों तक पहुंचने वाले थे। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण हो चुका था कि उनका भाषण न केवल प्रेरक, बल्कि बुद्धिमानी भरा भी हो।' मोर्चे की जानकारी मीडिया को दो माह पहले दी जा चुकी थी।

किंग को भी पता था कि यह आयोजन ऐतिहासिक होगा। यहां तकरीबन एक लाख लोगों की मौजूदगी की उम्मीद थी और किंग का समर्थन करने के लिए नागरिक अधिकारों के अग्रदूत रोजा पार्क, जैकी रॉबिनसन, अभिनेता मार्लोन ब्रांडो, सिडनी पोइटियर, गायक हैरी बेलाफोंटे और बॉब डायलान जैसी हस्तियां मौजूद रहने वाली थीं, लेकिन मोर्चे से पहले की रात दस बजे तक किंग ने अपना भाषण लिखना ही शुरू नहीं किया था। लेकिन किंग का जब भाषण हुआ, तो वह अमरत्व प्राप्त कर गया। अमेरिका के इतिहास में किंग के भाषण की तरह विख्यात शायद केवल एक और भाषण है : अब्राहम लिंकन का गेटिसबर्ग का संबोधन। केवल 272 शब्दों में लिंकन ने गृहयुद्ध को स्वतंत्रता की घोषणा में किए गए वादे के अनुरूप आजादी और समानता के लिए जंग के तौर पर निरूपित किया था। गेटिसबर्ग रवाना होने से पहले लिंकन आधा भाषण ही तैयार कर सके थे। एक वैज्ञानिक के अनुसार, 'अक्सर जब मैं आलस्य करता था, तो वास्तविकता में मेरे दिमाग में कुछ उथल-पुथल मची रहती थी और काम को पूरा करने के लिए वक्त चाहिए होता था।' राष्ट्रपति विल्सन के मुताबिक, 'अगर दस मिनट का भाषण है, तो उसे तैयार करने में मुझे दो सप्ताह का वक्त लग जाता है। यदि लंबा भाषण देना हो, तो फिर उसे तैयार करने की जरूरत नहीं।' कई महान लोग टालमटोल करने वाले भी होते हैं, लेकिन वे अपनी योजना को कभी नहीं छोड़ते। जैसे-लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा जैसी महान पेंटिंग को बनाने में करीब डेढ़ दशक का समय लगाया था। -'ओरिजिनल्स' के अनूदित अंश

सूत्र

जल्दबाजी में न लें निर्णय

टालमटोल खास तौर पर तब ज्यादा रचनात्मक हो जाती है, जब हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित न हो। नई जिम्मेदारी मिलने पर अक्सर लोग ताबड़-तोड़ फैसले कर डालते हैं, लेकिन बाद में उन्हें दिक्कत होती है। इसलिए टालमटोल का सूत्र यह है कि अहम निर्णय लेने में जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ा रुकें, सोचें, विचार करें और फिर उसको अमल में लाएं।

खतरनाक चौराहे पर पाकिस्तान

पाकिस्तान आज एक खतरनाक चौराहे पर खड़ा है। फील्ड मार्शल के रूप में आसिम मुनीर की नियुक्ति न केवल पाकिस्तान के नागरिकों, बल्कि वहां के राजनेताओं के लिए भी संकेत है कि सेना फिर से सत्ता में आ रही है और यह मार्शल लॉ लागू करने की प्रस्तावना है।

एक ऐसे मुल्क में जहां सैन्य सत्ता चुने हुए नेताओं पर भारी पड़ती है, पाकिस्तान की सेना ने छवि प्रबंधन में महारत हासिल कर ली है। हर राष्ट्रीय संकट या सैन्य गतिरोध के बाद वास्तविक या कथित तौर पर सैन्य प्रतिष्ठान कमजोर के बजाय किसी न किसी तरह रक्षक के रूप में उभरता है। इस तमाशे के ताजा अध्याय के केंद्र में जनरल आसिम मुनीर हैं, जो अब कहने के लिए फील्ड मार्शल हैं, जिन्हें योग्यता के आधार पर कम मिथक के आधार पर पदोन्नति मिली है।

पाकिस्तान के इतिहास में जनरल अयूब खान के बाद भारत के साथ तनाव के बीच जनरल मुनीर को पदोन्नत करना एक रणनीतिक जरूरत से अधिक सावधानीपूर्वक तैयार किया गया जनसंपर्क अभियान है। यह पाकिस्तानी पैटर्न के अनुरूप है, जब आलोचना का समय आता है, तो वीरता की नई कहानी गढ़ी जाती है।

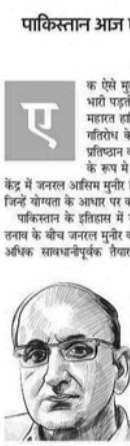

केएस तोमर
राजनीतिक विश्लेषक

इस बार पाकिस्तान द्वारा ड्रोन, मिसाइल क्षमताओं और साइबर युद्ध के माध्यम से भारत को 'चतुराई से मात' देने की कहानी गढ़ी गई है। पाकिस्तानी सरकारी मीडिया इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है, ट्रोल तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, और नकली जीत को राष्ट्रीय जीत के रूप में पेश किया जाता है।

इस भ्रामक सफलता ने पाकिस्तान जैसे गैर-लोकतांत्रिक देश में खासा प्रभाव डाला है। आर्थिक बदहाली, राजनीतिक अराजकता और सामाजिक अशांति से भरे मुल्क में सेना की इस जीत का मिथक अफीम का काम कर रहा है। अशिक्षित और बेरोजगार युवाओं की राय एक बार फिर सेना के पक्ष में झुक गई है। एक ऐसा मुल्क, जिसे अपने गिरते रुपये, बिजली की कमी और मुद्रास्फीति पर सवाल उठाना चाहिए, काल्पनिक हवाई हमलों और तकनीकी वर्चस्व के लिए ताली बजा रहा है।

लेकिन यह वाहवाही खोखली है। सच्चाई, जो कहीं ज्यादा गहरी है, इस छद्म आवरण के नीचे छिपी हुई है। तथ्यों की जांच करने पर झूठ की दीवारें ढहने लगती हैं। जो पाकिस्तानी सेना भारतीय आक्रामकता और ड्रोन खतरों का मुकाबला करने का दावा करती है, वहीं 11 एयरबेसों के नुकसान और नौ प्रमुख आतंकी शिविरों के प्रसार को रोकने में विफल रही, जो उसकी सुरक्षा में संदिग्ध रूप से चल रहे थे। वे व्यवस्थागत सड़न, कमान की विफलता और सेना की अपनी धरती को सुरक्षित रखने में असमर्थता के प्रतीक थे।

जनरल मुनीर को जिस प्रशंसनीय प्रदर्शन का इनाम मिला है, वह जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग है। खुद को राष्ट्र की ढाल के रूप में पेश करने वाली सेना के लिए प्रमुख संपत्तियों पर नियंत्रण खोना निंदनीय से कम नहीं है। लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता के बजाय असाधारण प्रचार हो रहा है। इससे भी बुरी बात यह है कि सैन्य शक्ति का यह महिमामंडन लोकतांत्रिक संस्थाओं की कीमत पर हो रहा है। किसी भी लोकतंत्र में, ऐसी विफलताओं के कारण संसदीय जांच होगी, शायद इस्तीफे भी देने पड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान में वे पदक का कारण बनते हैं।

नागरिक जीवन पर सेना की पकड़, जो आतंकी हमलों और घुसपैठ के कारण ढीली पड़ गई थी, एक बार फिर मजबूत हो रही है। फील्ड मार्शल के रूप में मुनीर की नियुक्ति न केवल पाकिस्तान के नागरिकों, बल्कि वहां के राजनेताओं के लिए भी संकेत है कि सेना फिर से सत्ता में आ रही है और यह मार्शल लॉ लागू करने की प्रस्तावना है।

इससे पाकिस्तान में लोकतंत्र की नींव कमजोर हो गई है, जो सतही तौर पर सैन्य जनरलों की बैसाखियों पर टिका हुआ है। इमरान खान जैसे निर्वाचित और सबसे लोकप्रिय नेता ने रावलपिंडी की सर्वशक्तिमत्ता को चुनौती देने की हिम्मत की, तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। यह अब हर महत्वाकांक्षी नागरिक नेता के लिए एक सबक है। पाकिस्तान में निर्वाचित नेता को सेना की कठपुतली की तरह काम करना पड़ता है।

जिस तरह रूसी राष्ट्रपति पुतिन असहमति को दबाने और अपनी तानाशाही को सही ठहराने के लिए संघर्ष की कहानियों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह मुनीर और शरीफ झूठ का किला बना रहे हैं। यह रणनीति न केवल अलोकतांत्रिक है, बल्कि खतरनाक भी है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा को नाटक में बदल देती है, मतदाताओं को दर्शक बना देती है और गरीबी, अस्थिरता और उग्रवाद जैसे वास्तविक मुद्दों को दरकिनार कर देती है।

पाकिस्तानी सेना को शह भू-राजनीतिक रियायतों से मिलती है, खास तौर पर अमेरिका जैसी पश्चिमी ताकतों से। ट्रंप प्रशासन ने अपने कार्यकाल में रणनीतिक रूप से इस्लामाबाद के साथ सैन्य कूटनीति को ओर रुख किया। ट्रंप के लेन-देन संबंधी विश्व-दृष्टिकोण में, पाकिस्तान की सेना वहां की अशांत नागरिक सरकारों की तुलना में अधिक विश्वसनीय भागीदार थी।

इससे जनरलों का हौसला और बढ़ गया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग मजबूत हुआ, रक्षा निधि में फिर से वृद्धि हुई और लोकतांत्रिक संस्थाओं को दरकिनार करते हुए रणनीतिक वार्ता फिर से शुरू हुई। कश्मीर पर ट्रंप की कुख्यात मध्यस्थता संबंधी टिप्पणी ने इस मुद्दे को फिर से अंतरराष्ट्रीय चर्चा में ला दिया। हालांकि इसका उद्देश्य क्षेत्रीय कूटनीति था, लेकिन पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी और सेना ने चतुराई से खुद को एक बार फिर वैश्विक खिलाड़ी के रूप में पेश किया। उनका उद्देश्य कश्मीर समस्या का समाधान नहीं था, बल्कि अपनी प्रासंगिकता को पुनर्जीवित करना था। पाकिस्तान आज एक खतरनाक चौराहे पर खड़ा है। पदकों और मिसाइलों के दावों के चमकदार मुखौटे के पीछे एक खोखला मुल्क छिपा है, जहां लोकतंत्र औपचारिकता तक सीमित हो गया है और असली सत्ता सेना के पास है। जनरल मुनीर की पदोन्नति जीत का इनाम नहीं, बल्कि भ्रम की रणनीति है।

पाकिस्तानी सेना ने भले ही घरेलू स्तर पर दुष्प्रचार युद्ध जीत लिया हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह बेनकाब हो चुकी है। एक ऐसी संस्था, जो प्रासंगिकता के लिए बेताब है, वाहवाही के लिए जवाबदेही का सौदा कर रही है और राष्ट्रीय सुरक्षा को तमाशा बना रही है। जब तक पाकिस्तान अपनी विफलताओं को जीत के रूप में पेश करता रहेगा और देशभक्ति के नाम पर असहमति को दबाता रहेगा, तब तक सच्ची प्रगति मृगतृष्णा ही बनी रहेगी। फील्ड मार्शल का डंडा कुछ समय के लिए जनता की धारणा को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह वास्तविक नेतृत्व, संस्थागत सुधारों और लोकतांत्रिक ताकत का स्थान नहीं ले सकता, जिनकी पाकिस्तान को अत्यंत आवश्यकता है। edit@amarujala.com

दूसरा पहलू

गांव सोरम में बाबर, अकबर, शाहजहां और बहादुर शाह जफर आए थे। यहां एक भवन है, जो इतिहासकारों को आकर्षित करता है।

चौपाल, जिसका अस्तित्व खिलजी भी न मिटा सका

मुजफ्फरनगर के गांव सोरम पहुंचते ही मुख्य मार्ग पर बना विशाल भवन अपनी ओर ध्यान खींच लेता है। इस भवन के बाहर ऐतिहासिक सोरम चौपाल का बोर्ड लगा है और सामने ही मुख्य दीवार पर भगत सिंह और विस्मिल जैसे क्रांतिवीरों की तस्वीरें लगी हैं। यह कोई आम भवन नहीं, बल्कि सर्वखाप पंचायतों का मुख्यालय है। एक ऐसा केंद्र, जहां पर देश की खुशहाली और समाज के सुधार के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं।

पिछले दिनों जब पाकिस्तान से युद्ध की बात हुई, तो सोरम में चौपाल पर सर्वखाप की आकस्मिक पंचायत बुलाई गई और निर्णय लिया गया कि देश को जरूरत पड़ने पर अन्न और खून की कमी नहीं होने दी जाएगी। युवा रक्तदान कर सैनिकों तक मदद पहुंचाएंगे। जरूरत पड़ने पर लड़ने भी जाएंगे। माना जाता है कि यह गांव छठी शताब्दी में पंचायतों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। इतिहासकारों का कहना है कि गुलाम वंश के दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के सिपहसालार बख्तियार खिलजी ने सोरम को काफी नुकसान पहुंचाया। गांव लगभग उजड़ गया था। 1305 में राभरार राणा ने इस गांव का नए सिरे से निर्माण किया। पुराने जमाने में यह चक्रव्यूह जैसा था, जिसे बाद में भवन का आकार दिया गया। माना जाता है कि वर्तमान भवन भी ढाई सौ साल से ज्यादा पुराना है। चौधरी गन्नत सिंह और करम सिंह ने इसे बनवाया था। बाद में कबूल सिंह ने इस परंपरा को मजबूती से आगे बढ़ाया। सर्वखाप पंचायत के मंत्री सुभाष बालियान बताते हैं कि गांव में बाबर, अकबर, शाहजहां और बहादुर शाह जफर जैसे शासकों का भी लगातार आना रहता था। अकबर की ओर से तो सवा सौ रुपये और पगड़ी भेंट की जाती थी। इन शासकों से जुड़े ताम्रपत्र आज भी मौजूद हैं।

नितिन यादव

इतिहासकारों का कहना है कि गुलाम वंश के दौर में कुतुबुद्दीन ऐबक के सिपहसालार बख्तियार खिलजी ने सोरम को काफी नुकसान पहुंचाया।

सर्वखाप ने नई लामजिक सुधारों की पहल की है। अब गांव सोरम की इस चौपाल की देखरेख का जिम्मा पर्यटन मंत्रालय ने लिया है और कई नेताओं ने अपनी निधि भी भवन के लिए दी है।

पंचायत के फैसलों पर किताब लिख चुके अमित बालियान बताते हैं कि सर्वखाप ने आजादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था। इतना ही नहीं, देश आजाद हुआ, तो दहेज प्रथा के खिलाफ एलान करते हुए 1950 में कहा कि पांच बर्तन, साड़ी और पांच बरातियों के साथ ही विवाह कराए जाने चाहिए। मौलाओं के भारी पापरे जैसे पहनावे पर सर्वखाप पंचायत ने ही छूट देने की पहल की थी। इसके बाद गांवों में स्कूल खोलने की पैरवी की। इसके साथ ही बेटियों की संख्या कम होने पर भ्रूण हत्या के खिलाफ भी सर्वखाप की पंचायत में एलान किया गया। अब गांव सोरम की इस चौपाल की देखरेख का जिम्मा पर्यटन मंत्रालय ने लिया है और कई नेताओं ने अपनी निधि भी भवन के लिए दी है। दुनिया के अनेक इतिहासकार यहां पर अब तक आ चुके हैं।

आंकड़े

महिला श्रमिक

चेन्नई देश का ऐसा महानगर है, जहां अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिला श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा है।

चेन्नई	33%
बंगलूरू	30%
हैदराबाद	28%
पुणे	21%
कोलकाता	20%

आंकड़े महिला श्रमिकों के प्रतिशत के | स्रोत : WeAreCity

स्वामी निगमानंद पहले लोक-परलोक की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक दिन उन्हें अपनी मृत पत्नी की छाया दिखी, जिसके बाद उनका जीवन ही बदल गया।

नास्तिक से आस्तिक बने निगमानंद

अंतर्यात्रा संक्षिप्त

स्वामी निगमानंद जी के बचपन का नाम नीलनीकांत भट्टाचार्य था। वह पहले नास्तिक थे। आत्मा-परमात्मा, जीवन-मृत्यु, लोक-परलोक जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वह कहते थे, मृत्यु के साथ ही जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन ईश्वरीय प्रेरणा और पूर्वजन्म के संस्कारों ने उनके मन पर पड़े नास्तिकता के परदे को हटाने में देर नहीं लगाई।

वह नारायणपुर कैंप में काम कर रहे थे। अचानक देखा कि उनकी पत्नी, जिनका निधन हो चुका था, उनके सामने खड़ी हुई हैं। बार-बार देखने पर वह अचल मूर्ति की तरह खड़ी रहीं। इस घटना ने उनके जीवन को ही बदल दिया। वह प्रेतात्माओं से बात करने के लिए विचेसपैकिस सोसाइटी से जुड़ गए। वह कलकत्ता लौटकर आए, जहां उनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई। उनकी अवस्था को देखकर स्वामी पूर्णानंद ने कहा, 'यदि तुम अपनी मृत पत्नी से मिलना चाहते हो, तो तुम्हें महामाया की साधना करनी होगी।' निगमानंद जी ने तारापीठ के सिद्ध योगी वामापेक्षा से दीक्षा ग्रहण कर साधना की। इससे न केवल वह अपनी पत्नी की आत्मा से वार्तालाप कर सके, बल्कि मां तारा के दर्शन भी हुए। इसके बाद उनकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। स्वप्न में उन्हें एक योगी के दर्शन हुए। उनकी खोज में वह निकल पड़े। पुष्करतीर्थ में पहुंचने पर, स्वप्न में जो योगी दिखे थे। वह उनके सामने खड़े थे। वह महात्मा थे स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती परमहंसदेव।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 29 मई, 1960

पाकिस्तान की सेना में व्यापक अशांति

पाकिस्तान की सेना में व्यापक अशांति
अयूब अस्थगत परेशान

तुर्किये की सैनिक क्रांति से यदि कोई देश अत्यंत बेचैन है, तो वह पाकिस्तान है, जहां के तानाशाह फील्ड मार्शल अयूब तुर्किये की घटनाओं से अपनी कुर्सी मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं।

सत्य, साहस और समाचार

199 वर्ष पहले शुक्ल जी ने *उदंत मार्तंड* के रूप में अखबार प्रकाशन की जो आदर्श योजना बनाई थी, उसकी झलक आज भी हिंदी अखबारों में देखने को मिलती है।

डॉ. किंशुक पाठक — **हिंदी पत्रकारिता दिवस**

हिंदी के पहले समाचार पत्र *उदंत मार्तंड* की प्रकाशन तिथि 30 मई नई पीढ़ी को भारतीय पत्रकारिता की ऐतिहासिक मिशनरी परंपरा से रूबरू कराती है। उस वक्त आज की तरह संचार के अनेक माध्यम नहीं थे। छापाखानों का आविष्कार मीडिया की 'मैजिक मल्टीप्लायर' भूमिका का आधार बना। 1780 में भारत के पहले अंग्रेजी अखबार *हिक्कीज बंगाल गजट* का प्रकाशन हिंदी के जज्बाती संचारकों के लिए चुनौती था, जिसे स्वीकार कर आज ही के दिन 1826 में कलकत्ता (अब कोलकाता) से *उदंत मार्तंड* की शुरुआत हुई।

यह वर्ष हिंदी पत्रकारिता का द्विशताब्दी वर्ष है। दो सदी पहले पत्रकारिता के उद्देश्य कुछ और थे। आज 'फेक न्यूज' के तूफानी दौर में 'सत्य समाचार' के लिए समर्पित हिंदी के पहले समाचार पत्र *उदंत मार्तंड* की स्मृतियां और इसका योगदान प्रेरणास्रोत है। 'सत्य' को पत्रकारिता की आत्मा मानने वाले मिशनरी पत्रकार-संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल ने अपने बलबूते हिंदी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित कर हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। यह दिवस पत्रकारिता का 'संकल्प पर्व' है।

कलकत्ता की कोलूटोला-आमड़ातल्ला की गली से *उदंत मार्तंड* के रूप में शुरू हुई हिंदी पत्रकारिता आज हिंदी में समाचार, विचार और प्रचार-विज्ञापन का माध्यम सिर्फ छापाखाने से निकलने वाले अखबारों-पत्रिकाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया तक फैल चुकी है। 30 मई, 1826 से 11 दिसंबर, 1827 तक कुल 79 अंक प्रकाशित होकर भले ही *उदंत मार्तंड* अपनी यात्रा आगे जारी न रख सका हो, पर 199 साल पहले शुक्ल जी ने अखबार प्रकाशन की जो आदर्श योजना बनाई, उसकी झलक आज भी हिंदी समाचार पत्रों में देखने को मिलती है। हिंदी पत्रकारिता उनके योगदान की सदैव ऋणी रहेगी।

उन्होंने स्पष्ट मत व्यक्त किया, 'अंग्रेजी, फारसी और बंगला भाषा के पत्र तो निकलते हैं, लेकिन हिंदी का कोई भी स्वतंत्र पत्र नहीं निकलता, यह चिंतनीय है।' हिंदी का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे शुक्ल जी का संकल्प और उद्देश्य था-'हिंदी भाषी अपनी निज भाषा में ही सत्य समाचार पढ़कर उसका आनंद लें।' वस्तुतः *उदंत मार्तंड* का अर्थ है-समाचार सूर्य। यह पत्र समाचार रूपी सूर्य था, जिसके प्रकाशन का उद्देश्य पाठकों को सूचनाओं और समाचारों के प्रकाश से युक्त करना रहा। शुरू से ही इसके दो संकल्प स्पष्ट थे, 'सत्य समाचार' और 'साहस'। 'सत्य को समाचारों की आत्मा मानने के संकल्प के साथ *उदंत मार्तंड* का प्रकाशन शुरू हुआ।

इतिहास साक्षी है कि अखबार के संपादन और प्रकाशन में जोखिम हमेशा रहा है। हिंदी के इस प्रथम पत्र में भी बाजार भाव तथा अन्य आर्थिक समाचारों को पूरा महत्व दिया गया था। हर मंगलवार को प्रकाशित *उदंत मार्तंड* में व्यापारिक जहाजों के आने-जाने की सूचनाएं भी प्रकाशित होती थीं। समाचार और विचार भी पूरे तथ्य और इनकी सत्यता के प्रमाण सहित प्रकाशित किए जाते थे। *उदंत मार्तंड* के प्रकाशन पर्व का यह दिवस हिंदी पत्रकारिता के गौरवशाली अतीत और वर्तमान के स्मरण तथा आत्मनिरीक्षण का अवसर है।

'फेक न्यूज' जैसे भंवर में फंसे और भटकते पत्रकारिता के जहाज को आज भी *उदंत मार्तंड* के आदर्श 'सत्य समाचार' की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। विद्वान, मनीषी चाणक्य की यह मान्यता 'जब चारों ओर अंधकार हो और कुछ साफ दिखाई न पड़े, तो 'गुरु, शिक्षक की ओर देखो, रास्ता अवश्य मिलेगा', मीडिया और पत्रकारिता के लिए बिल्कुल सटीक है। मीडिया या पत्रकारिता, पत्रकार और संपादक की ऐतिहासिक भूमिका, कार्य और उद्देश्य में आए तेजी से बदलाव ने संपूर्ण विश्व की पत्रकारिता, उसके मूल उद्देश्यों तथा पत्रकार-संपादक की भूमिका के समक्ष अनेक ज्वलंत प्रश्न उपस्थित किए हैं।

साख को बट्टा लगाने के लिए पत्रकारिता की आड़ में बाजार में आज कई असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। विश्वसनीयता, जो पत्रकारिता की मूलभूत पूंजी है, के सामने कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक दौर था, जब पत्रकारिता या मीडियाकर्म और मीडियाकर्मी का कोई भी कार्य 'पेड' नहीं था। अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जज्बाती लोग पहले पत्रकारिता में आते थे। *उदंत मार्तंड* के वक्त की चुनौतियां अलग थीं और आज की बिल्कुल अलग हैं, लेकिन पत्रकारिता के आदर्श तब भी समाज हित थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसी अनेक चुनौतियों के बावजूद भारतीय पत्रकारिता, खासकर हिंदी पत्रकारिता की भूमिका समाज में कमजोर नहीं हुई है।

दैनिक जागरण
पुरुषार्थ की पूंजी ही समृद्धि की नींव रखती है

वायु सेनाध्यक्ष की खरी बात

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भारतीय उद्योग परिसंघ के शिखर सम्मेलन में रक्षा सौदों और रक्षा सामग्री के निर्माण की परियोजनाओं में देरी को लेकर जैसी खरी बात कही, वह वैसी ही बातें करने के लिए जाने जाते हैं। वह अच्छा भी है, क्योंकि रक्षा के मोर्चे पर किसी भी तरह की देरी स्वीकार्य नहीं। इसके पहले उन्होंने लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण में देरी पर भी अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी। अब उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि हथियारों एवं रक्षा उपकरणों के निर्माण की कोई परियोजना समय पर पूरी नहीं होती। उनकी यह बात भी सही है कि दूसरे देशों से रक्षा सामग्री की खरीद के जो सौदे होते हैं, उनके तहत मिलने वाली सामग्री की आपूर्ति में भी विलंब होता है। इसके कई उदाहरण हैं। पहले तो रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने में ही अच्छा-खासा समय लग जाता था। इसके चलते जरूरी रक्षा सामग्री मिलने में और विलंब होता था। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मनमोहन सरकार लंबे समय तक राफेल या इस जैसे अन्य विमान की खरीद का फैसला ही नहीं कर पाई। निःसंदेह मोदी सरकार ने रक्षा सौदे तत्परता से करने के साथ देश में ही सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से रक्षा सामग्री के निर्माण की ओर अतिरिक्त ध्यान दिया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं, लेकिन इस मोर्चे पर और सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है। शायद इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ी घोषणा की कि पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा।

चूंकि बीते कुछ वर्षों में रक्षा सामग्री बनाने वाली हमारी कंपनियों ने अपनी क्षमता साबित कर दी है, इसलिए उन्हें और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसलिए और भी, क्योंकि आपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध किया कि भारतीय सेना उन्नत हथियारों से लैस होने के साथ ही उनके उपयोग में भी पारंगत है। इसी कारण वायु सेनाध्यक्ष ने पाकिस्तान को बेदम करने और चीन की पोल खोलने वाले इस सैन्य अभियान को राष्ट्रीय विजय की संज्ञा दी। यह ध्यान रहे कि जनरल बिपिन रावत यह कहा करते थे कि भारत को अपनी जरूरत के हथियार खुद बनाने चाहिए, क्योंकि धीरे-धीरे वे उन्नत होते जाएंगे और हम रक्षा सामग्री के मामले आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस तथ्य पर भी गौर किया जाना चाहिए कि जैसे हमारा डीआरडीओ है, वैसे ही अमेरिका का डारपा। उसने समय के साथ उन्नत हथियारों के अलावा उद्योग-धंधों के काम आने वाले ऐसे उपकरण भी बनाए, जो अमेरिका की प्रगति में सहायक बने। वही काम रक्षा क्षेत्र में उतरीं हमारी निजी कंपनियां भी कर सकती हैं।

वित्त आयोग से उम्मीदें

झारखंड के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार के लिए 16वें वित्त आयोग के सदस्य राज्य के दौरे पर हैं। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार ने अपना पक्ष पिछले दिनों रखा है। वित्त आयोग के साथ बैठक के दौरान इसपर चर्चा होने की उम्मीद है। विभागीय मंत्रियों के साथ बैठक में उनकी आवश्यकताओं पर चर्चा होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य समेत आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए राज्य को केंद्रीय सहायता चाहिए। इसमें वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य सरकार ने आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण के लिए कई योजनाओं का प्रारंभ किया है। इसके लिए पर्याप्त धन चाहिए। वित्तीय संसाधन के लिए राज्य की अपनी संरचना सभी योजनाओं का संचालन नहीं कर पाती है। ऐसे में वित्त आयोग से उम्मीद रहती है कि राज्य की जरूरतों से केंद्र सरकार को अवगत कराए और संसाधन उपलब्ध कराए। वित्त आयोग की तरफ से राज्य में विकास योजनाओं के लिए सुझाव भी दिए जाते हैं। झारखंड में युवा आबादी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दोनों सरकारों ने योजना बनाई है। आदिवासी समाज को भी विकास के पथ पर लाने के लिए वित्त आयोग ने कई सिफारिश समय-समय पर की है। ऐसे में अधिकारियों के सामने विकास का रोडमैप तैयार करने का अच्छा अवसर है।

> वित्त आयोग के झारखंड दौरे को लेकर उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, केंद्रीय सहायता समेत कई मुद्दों पर इससे समन्वय भी बनेगा

आपरेशन सिंदूर के बाद की चुनौती

संदीप घोष

बड़े देशों को यह सब पच नहीं रहा कि यदि भारत आर्थिक के साथ सैन्य मोर्चे पर भी सशक्त होता है तो उसे रोकना संभव नहीं होगा

अवधेश राजपूत

मशरूम क्लाउड्स का संबंध सामान्य तौर पर परमाणु विस्फोट से होता है। बीते दिनों आपरेशन सिंदूर के दौरान परमाणु प्रतिष्ठान को निशाना बनाने की अटकलें भी लगाई गईं। इन अटकलों के बीच फर्जी सूचनाओं, प्रोपेगंडा और यहां तक कि मीडिया के एक हिस्से द्वारा फैलाई गई अफवाहों का विस्फोट जरूर देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव थमने को आए चाहे जो नाम दें, लेकिन उसके एक पखवाड़े बाद भी तरह-तरह की कहानियां तैर रही हैं। अपनी-अपनी कहानियों को सच बताने की मुहिम जारी है। लोग भी अपनी रुचि एवं झुकाव के लिहाज से उन्हें मान्यता दे रहे हैं। जब सीमा के दोनों ओर जहां एक के बाद एक बार-पलटवार हो रहे थे, उसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एकाएक पोस्ट प्रकट हुई कि उन्होंने दोनों देशों के बीच जारी टकराव को बंद करा दिया है। इसे लेकर भी अटकलें-अनुमान चरम पर रहे कि पर्दे के पीछे आखिर क्या हुआ, जो यकायक ऐसी स्थिति बन गई। ऐसे दावों-प्रतिदावों के बीच संभव है कि सच्चाई कभी बाहर न आ पाए। इसके बावजूद अपना-अपना नैरेटिव बनाने का उन्मादी दौर देखने को मिला। इस दौरान अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने स्वाभाविक रूप से अपनी 'सुविधाजनक' वैचारिक मंशा ज़िहाई। इस 'सुविधाजनक' को भारत-विरोधी पढ़ा-समझा जाए।

देखा जाए तो संचार के मोर्चे पर पाकिस्तान की चुनौतियां भारत की तुलना में कहीं आसान थीं। चूंकि वहां हर पहलू की तरह विमर्श की रूपरेखा तय करने पर भी सेना का ही नियंत्रण है इसलिए उसके लिए जीत की घोषणा करना ही बाकी थी। फिर चाहे इसके लिए राफेल को मार गिराने की फर्जी कहानी ही क्यों न गढ़नी पड़ी। यह उसने गढ़ी भी और उसे अपनी मतांध जनता और दुनिया भर में फैले ऐसे ही लोगों को परोसा भी गया। इसे दौरान सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल की पदवी देकर अपने कपोल-कल्पित आख्यान को मान्यता देने का प्रयास किया। यहां तक कि इस 'जीत' का जश्न मनाने के लिए समारोह और भोज भी आयोजित किए गए, जिसमें प्रयुक्त तस्वीरें भी झूठी ही निकलीं। इस मामले में भारत का काम कहीं ज्यादा जटिल था। पहले तीन दिनों तक सूचनाओं के प्रवाह को अनुकरणीय धैर्य एवं कुशल प्रबंधन के जरिये संभाला गया। फिर अचानक अमेरिका के मनमौजी राष्ट्रपति की संघर्ष विराम की घोषणा और मध्यस्थता में अमेरिकी भूमिका का दावा हैरत में डाल गया। इसने भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को हतप्रभ कर दिया, क्योंकि उसे सफाई देनी पड़ी कि इसमें तीसरे पक्ष का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। पाकिस्तान के संदर्भ में दशकों से भारत की यही नीति रही है कि तीसरे पक्ष के दखल के लिए कोई स्थान नहीं। आम भारतीय भी युद्ध की दुंदुभि के शांत पड़ने से अवाक रह गए, जो यह मान चुके थे कि सीमा पार आतंकवाद को इस बार ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वह फिर सिर उठाने का दुस्साहस न करे। जनता दीर्घकालिक समाधान की आस लगाए थी। स्पष्ट है सरकार धारणा के मोर्चे पर कुछ मात खा गई। सट्टि की प्रकृति भारतीयों के डीएनए में समाई हुई है और उन्हें इसकी कहीं ज्यादा फिक्र होती है कि बाकी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय छवि को लेकर भारतीय खासे आग्रही हैं। इसमें औपनिवेशिक अतीत की भी भूमिका है। जब सट्टि विपक्षी दलों और उनके इकोसिस्टम द्वारा बढ़ाए जाते हैं तो जनता के मन पर कहीं न कहीं उसकी गूंज होती है। इसे भांपते हुए सरकार ने सांसदों-विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में भेजने का फैसला किया ताकि वे वैश्विक स्तर पर भारत का पक्ष रखें। इसे साफ समझा जा सकता है कि सर्जिकल स्ट्राइक -एयर स्ट्राइक की तुलना में आपरेशन सिंदूर कहीं बड़ी सैन्य कार्रवाई रही। इसमें भारत ने न केवल पाकिस्तान के भीतर तक हमले किए, बल्कि बचाव के मामले में भी अद्भुत मिसाल कायम की।

जब तक कथित संघर्ष विराम के पीछे का घटनाक्रम सामने नहीं आएगा, तब तक कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाए जाते रहेंगे। यह भी अटकलों के केंद्र में रहेगा कि क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु जखीरे को कोई नुकसान पहुंचाया या उसके आस्थास कोई हमला किया। जो भी हो, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि आपरेशन सिंदूर के दौरान भारत वैश्विक जनमत को अपेक्षित रूप से अपने पक्ष में नहीं मोड़ पाया। कोई बड़ी महाशक्ति भारत के साथ खुलकर खड़ी नहीं दिखी, जबकि पाकिस्तान के पीछे चीन, तुर्किये के अलावा अजरबैजान का समर्थन साफ दिखा। ट्रंप के इस दावे कि 'शांति कराने के लिए उन्होंने व्यापार को आधार बनाया' पर इसलिए यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत ने अतीत में भी अमेरिकी प्रतिबंधों की परवाह नहीं की है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं कि वह व्यापार की चिंता करे। पाकिस्तान के लिए आइएमएफ से ऋण मंजूर हो जाना भी यही संकेत करता है कि पश्चिम की हमदर्दी किसके साथ रही।

पाकिस्तान सहित अमेरिका, चीन के अलावा अन्य देश इससे तो अवगत रहे ही होंगे कि भारत ने कैसी सामरिक क्षमताएं हासिल कर ली हैं, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि वह उनके उपयोग में भी कितना सक्षम है। अगर पाकिस्तान के साथ तनातनी कुछ दिन और खिंचती तो भारत की शक्ति एवं श्रेष्ठता और मुखरता से स्थापित हो जाती, जिससे क्षेत्रीय भू-राजनीतिक समीकरण बदल जाते। स्वाभाविक है कि कुछ महाशक्तियों को यह गवारा नहीं होता। यहां असल मुद्दा एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उभार से जुड़ा है। इसके साथ ही यदि वह सैन्य रूप से सशक्त होकर उभर आता है तो उसे रोकना संभव नहीं होगा। विकसित देश अभी इस सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं। देखना है कि मोदी इस सबसे बड़ी चुनौती से कैसे निपटते हैं। संभव है कि विकसित भारत के दूरगामी लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही उन्होंने तात्कालिक रूप से संघर्ष विराम का विकल्प चुना हो। उन्होंने वीरता पर विवेक को वरीयता दी। आखिर बड़ा युद्ध जीतने के लिए कुछ छोटी लड़ाइयों को अनदेखा जो करना होता है।

(लेखक आर्थिक एवं राजनीतिक मामलों के विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

मुर्शिदाबाद हिंसा का डरावना सच

अवधेश कुमार

मुर्शिदाबाद की हिंसा पर हाई कोर्ट समिति की रिपोर्ट बंगाल पुलिस-प्रशासन का सिर शर्म से नीचा करने वाली ही है

वक्फ कानून के विरोध के बहाने हुई थी ऐसी हिंसा। फाइल

सकता हाई कोर्ट की ओर से गठित तथ्य-खोजी समिति की मुर्शिदाबाद हिंसा संबंधी रिपोर्ट किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त है। इस रिपोर्ट के बाद सारे आरोपों की पुष्टि हो गई। इस रिपोर्ट के पहले बंगाल पुलिस ने भी उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसमें कुछ ऐसा लिखा था, '11 अप्रैल को लगभग 4.25 बजे भीड़ अनियंत्रित हो गई..पुलिस पर ईंट, पत्थर के साथ घातक हथियारों से हमला कर दिया गया। उपद्रवियों ने एसडीपीओ जंगीपुर की पिस्तौल छीन ली और उनके वाहन के साथ सार्वजनिक संपत्तियों में आग लगा दी।' यह ध्यान देने की बात है कि हाई कोर्ट समिति की रिपोर्ट में पुलिस को ही सबसे ज्यादा कठघरे में खड़ा किया गया है। हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक-एक सदस्य वाली तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। इसी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंसा हिंदुओं के विरुद्ध और सुनियोजित थी। तृणमूल के मुस्लिम नेता और पार्षद ने हिंसा का नेतृत्व किया। लोगों ने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उसने न हिंसा रोकने की कोशिश की और न लोगों को सुरक्षा देने की।

यदि तीन दशक पहले किसी राज्य में एक समुदाय के खिलाफ ऐसी भयानक हिंसा होती तो वहां की सरकार बर्खास्त हो जाती। अब ऐसा इसलिए कठिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने को असंवैधानिक ठहरा सकता है। शायद इसीलिए बंगाल के राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र से संवैधानिक विकल्पों पर विचार करने का सुझाव तो दिया था, लेकिन हालात बिगड़ने पर अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) को विकल्प बताते हुए लिखा था कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। भयानक हिंसा के शिकार महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक आपबीती के बावजूद ममता बनर्जी ने आरंभ में सहानुभूति का एक शब्द नहीं बोला था। वह, उनके मंत्री, प्रवक्ता आदि सब इसे भाजपा का षड्यंत्र बताते हुए बीएसएफ पर भी आरोप लगा रहे थे। कायदे से तो बीएसएफ की ओर से भी हाई कोर्ट में अपील दायर होनी चाहिए थी। आखिर किस आधार पर इतना संगीन आरोप मुख्यमंत्री ने लगा दिया?

हाई कोर्ट समिति की रिपोर्ट के अनुसार नए वक्फ संशोधन कानून के विरुद्ध प्रदर्शन की आड़ में हिंदुओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया। बेतबोना गांव में 113 घर जला दिए गए। रिपोर्ट में लिखा है, 'एक उपद्रवी गांव में यह देखने भी आया कि किन घरों पर हमला नहीं हुआ और फिर भीड़ ने उन घरों में भी आग लगा दी।' गांव जला दिया गया, लेकिन पुलिस-प्रशासन निष्क्रिय बना रहा। हिंसक भीड़ ने पानी का कनेक्शन काटा, ताकि आग बुझाई न जा सके। सबसे खौफनाक यह रहा कि महिलाओं के वस्त्र जला दिए गए, ताकि उनके पास पहनने को कपड़े न बचें। रिपोर्ट में यह भी लिखा है, 'हिंसा के शिकार गांव के लोगों ने लगातार दो दिन पुलिस को फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठाया गया।' भाग कर मालदा शरण लेने गए पीड़ितों को पुलिस ने लौटने को विवश किया। साफ है कि सरकार की ओर से पुलिस-प्रशासन पर दबाव रहा होगा कि जान बचाकर भागे लोगों की जबरन बुलाया जाए, क्योंकि सरकार की थू-थू हो रही है। रिपोर्ट ने जिस तरह पुलिस-प्रशासन को कठघरे में खड़ा किया है, उससे वह सिर उठाने लायक भी नहीं। रिपोर्ट यह भी कहती है कि प्रशासन की तरफ से हिंसाग्रस्त इलाकों में किसी की मदद नहीं की गई। रिपोर्ट में लिखा है कि 'हमले स्थानीय पार्षद की तरफ से निर्देशित किए गए।

हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि बंगाल में इसके पहले भी हिंदू त्योहारों पर हमले हुए हैं। विधानसभा चुनाव बाद की हिंसा में भी तृणमूल के विरुद्ध वोट देने वालों को हिंसक भीड़ से बचकर असम पलायन करना पड़ा था। हाई कोर्ट समिति के अनुसार बंगाल में गैर-मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा करने वालों को पुलिस का साथ मिलता है। मुर्शिदाबाद में भी पुलिस ने घटना से आंखें मूंदकर हिंसक भीड़ को एक प्रकार से खुली छूट दी। हाई कोर्ट समिति की रिपोर्ट में जाफराबाद इलाके में हरगोबिंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या का जिक्र करते हुए कहा गया है ' हिंसा पर उतारू भीड़ ने उनके घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और पिता-पुत्र को ले गए और उनकी पीठ पर कुल्हाड़ी से वार किया। एक हत्यारा तब तक वहां इंतजार करता रहा, जब तक वे मर नहीं गए।' पिता-पुत्र का दोष यह था कि वे देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। यह कैसा खतरनाक सोच है कि मूर्तियां बनाने वाला दुश्मन हो गया।

मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद वहां गए राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बांग्लादेश से सटे मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में दहेश खतरा है, क्योंकि वहां हिंदू आबादी अल्पसंख्यक है। उन्होंने उत्तरी दिनाजपुर को भी हिंदुओं के लिए असुरक्षित बताया था। एक तरह से बंगाल के कुछ इलाकों के हालात वैसे ही होते जा रहे हैं, जैसे बांग्लादेश में हो गए हैं और जहां हिंदुओं का जीना दूभर है। बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए तो हमारे पास सीमित विकल्प हैं, लेकिन बंगाल में तो केंद्र सरकार को कुछ करना ही चाहिए। इस पर भी गौर करें कि मुर्शिदाबाद की भयावह हिंसा पर कथित सेक्युलर दलों ने न तो तब कुछ कहा था और न ही हाई कोर्ट की रिपोर्ट आने के बाद।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

स्वप्न और यथार्थ

निद्रा मनुष्य के लिए परमात्मा का महान वरदान है। इस दौरान प्रत्येक मनुष्य सुखद और दुखद दोनों ही प्रकार के स्वप्न देखता है। इसमें चयन की कोई संभावना नहीं होती कि आज सुखद स्वप्न ही देखना है या कभी भी दुखद स्वप्न नहीं देखना है। कभी-कभी मनुष्य ऐसे स्वप्न देखता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। कभी स्वप्न में वह रंक से राजा और राजा से रंक बना होता है। स्वप्न में जो भी देखा जाता है, उसकी आयु स्वप्न देखे जाने तक ही रहती है। फिर भी स्वप्न और यथार्थ में एक निश्चित संबंध है, जो ईश्वर कदाचित उस समय मनुष्य को समझाना चाहता है जब वह माया के प्रभाव से मुक्त होता है और विकार निष्क्रिय होते हैं। ऐसा बस उसी समय होता है जब वह निद्रा में होता है।

स्वप्न एक तरह से जीवन के पाठ हैं, जो उसे सच से जोड़ते हैं। जैसे स्वप्न मनुष्य के चयन से बाहर हैं, वैसे ही मनुष्य के जीवन में आने वाले सुखों-दुखों पर कोई जोर नहीं है। जैसे निद्रा टूटते ही दुखद स्वप्न से मुक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही अज्ञानता की निद्रा से मुक्त होने पर सुखद अहसास होता है। जैसे मनुष्य कभी कल्पनातीत स्वप्न देखता है, वैसे ही जीवन में कभी अकस्मात कुछ ऐसा घटित हो जाता है, जिसकी कल्पना भी नहीं की होती है। सुख और दुख स्वप्न के साथ ही विदा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आयु स्वप्न की अवधि तक ही सीमित होती है। यथार्थ जीवन में भी ऐसा ही है। प्रत्येक सुख और दुख की अपनी आयु है। उसे अपनी आयु पूरी करनी ही है। इसे न समझ कर मनुष्य अपने जीवन में असंतुलन उत्पन्न करता है। मनुष्य स्वप्न में ही हर्षित और व्यथित होता है, क्योंकि वह स्वप्न को ही सच मान रहा होता है। यथार्थ में भी उसके मन के सुख और दुख इसीलिए हैं, क्योंकि उसने नाशवान संसार और अपने तन को सच माना हुआ है। वह यह मान ले कि संसार एक स्वप्न है तो सुख-दुख से उबर जाएगा।

डा. सत्येंद्र पाल सिंह

घटती स्मरण शक्ति चिंतनीय

डा. मोनिका शर्मा

> तकनीकी दौर में जीवनशैली में बदलाव के बिना स्मरण शक्ति में गिरावट की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता

हाल में एप के माध्यम से टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी 'उबर' द्वारा देश के पांच शहरों में किए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि लोगों की स्मरण शक्ति में गिरावट आ रही है। इस सर्वे में मुंबई शहर पहले स्थान पर है, जहां लोगों की याददाश्त सबसे कमजोर पाई गई है। 'उबर' का कहना है कि उनकी टैक्सी में लोग अक्सर अपना सामान भूलकर चले जाते हैं। यह सर्वेक्षण सामान्य परिस्थितियों में स्वस्थ लोगों की स्मृति के क्षरण को लेकर चिंताजनक है, जो कि घर, दफ्तर और आम जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है।

यह विचारणीय है कि इंसानों के लिए याद रखने का अर्थ केवल अतीत की स्मृतियों तक सीमित नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई महत्वपूर्ण चीजों को याद रखना आवश्यक होता है। मन-मस्तिष्क की सजगता के बिना संवाद और दैनिक कार्यों को पूरा करना कठिन हो जाता है। ऐसे में सामान्य गतिविधियों और सामानों को भूल जाना एक बड़ा खतरा बन गया है। कमजोर स्मरण शक्ति दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। बच्चे हों या बड़े, लोग पलभर में भूल जाते हैं कि उन्हें क्या करना था। अब तो अपना फोन नंबर या पता याद रखना भी मुश्किल हो गया है। रास्ते और सीमा चिह्न भी याद नहीं रहते, जिससे जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पहले बुजुर्गों की समस्या मानी जाने वाली यह स्थिति अब हर आयुवर्ग को प्रभावित कर रही है।

हाल के वर्षों में स्मार्ट गैजेट्स के अत्यधिक उपयोग ने भी याद रखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। तकनीकी प्रगति ने विजुअल माध्यमों की भूमिका को बढ़ा दिया है। हर मुट्ठी में मौजूद जानकारियों की स्क्रीन ने दिमाग पर जोर डालकर सोचने और याद रखने की आवश्यकता को कम कर दिया है। क्लिक भर में मिलती या खोजी जाने वाली हर सूचना, विवरण और तस्वीर दिमाग को सुस्त बनाने वाली गतिविधि साबित हो रही है। स्क्रीन स्क्रालिंग में व्यस्त लोग अपने-अपने निजी कोनों में सिमट गए हैं, जिससे सामाजिकता का दायरा घटा है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक गतिविधियों में कमी भी स्मृति कम होने के जोखिम को बढ़ा रही है।

इस तकनीकी विस्तार के दौर में जीवनशैली में बदलाव के बिना स्मरण शक्ति में गिरावट की समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। सामाजिक और शारीरिक सक्रियता, कुछ नया सीखने की मानसिक कसरत, स्मार्ट गैजेट्स के उपयोग में अनुशासन और प्रकृति से जुड़ाव इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्मरण शक्ति में गिरावट एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें अपनी जीवनशैली में सुधार लाने की आवश्यकता है, ताकि हम इस समस्या का सामना कर सकें और अपनी याददाश्त को बेहतर बना सकें।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जरूरी पहलू की अनदेखी

'बड़ा खतरा बन रहे हैं माओवाद समर्थक' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने माओवादियों के देसी-विदेशी समर्थकों को अच्छे से बेनकाब किया है, लेकिन उन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए था कि सरकार उन कारणों को भी दूर करे, जिनकी सच्ची-झूठी आड़ लेकर माओवादी आदिवासियों और अन्य गरीब ग्रामीणों को बरगलाते हैं। लेखक को पता होना चाहिए कि माओवादी वही प्रचार करते हैं कि सरकार वन संपदा का दोहन करती है, आदिवासियों को उनके हाल पर छोड़ देती है और विकास पर ध्यान नहीं देती है। अब सरकार को चाहिए कि वह उन इलाकों में विकास पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान दे, जहां माओवादी और उनके समर्थक सक्रिय हैं। लेखक इस जरूरी पहलू की भी अनदेखी कर गए कि माओवाद एक विचारधारा है और सरकार को विचार की लड़ाई विचार के स्तर पर भी लड़नी चाहिए। नहीं तो आज जो माओवादी कमजोर दिख रहे हैं, वे फिर सिर उठा लेंगे। इस समस्या को समग्रता में समझा जाए।

मनीष कश्यप, नई दिल्ली

देशहित में निर्णय जरूरी

'रूस को समझने से इन्कार करता अमेरिका' शीर्षक आलेख में शंकर शरण ने रूसियों के चरित्र और उनके इतिहास का सटीक वर्णन किया है। मास्को में विजय के बाद नया जोड़ा सबसे पहले अनाम सैनिक के स्मारक पर जाकर फूल चढ़ाता है। यह अपनेआप में रूस की एक विशेष संस्कृति, संस्कार को बयां करता है। रूस-यूक्रेन युद्ध का मूल कारण अमेरिका ही है। भारतीयों को भी अपना इतिहास याद रखना चाहिए। सदियों से बर्बर आक्रांताओं के द्वारा रौंद जाने के बावजूद भारत अपने ऋषियों और मनीषियों के द्वारा शिक्षित चरित्र के बल पर ही आज भी खड़ा हुआ है। पर अब भारत बदल चुका है और नया भारत घर में घुसकर मारना जानता है। भारत को अब गीता के अनुसार ही अहिंसा के अर्थ समझने होंगे और अपनी रक्षा के लिए शत्रु का संहार करना होगा। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा एक नकारात्मक शब्द है और हिंसा एक सकारात्मक शब्द है। और राष्ट्र की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने को विरोधी हिंसा माना गया है। जो शास्त्रों के अनुसार मान्य है, यह हिंसा में नहीं आता है। अहिंसा वीरों का शस्त्र है कायरों का नहीं। धर्म और राष्ट्र की स्थापना और रक्षा के लिए ही शस्त्र उठाने की बात गीता में भी कही गई है। हमें यह सदा याद रखना होगा। हमें ट्रंप और पुतिन के चक्कर में न पड़कर अपने देशहित के अनुसार निर्णय लेने होंगे।

इंजी. अतिवीर जैन पराग, कंकर खेड़ा, मेरठ कैंट

मेलबाक्स

मोदी सरकार की उपलब्धियां

'11 वर्ष का लेखा-जोखा' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में मोदी सरकार की उपलब्धियां और अपेक्षाओं का बखान किया गया है। उपलब्धियों के अलावा ही अपेक्षाएं भी मोदी सरकार से ही हैं। यह खुद में विपक्ष की सबसे बड़ी नाकामी है। सुधार में निचले स्तर की नौकरशाही और पुलिसिंग व्यवस्था प्रमुख हैं। वहीं कुछ योजनाएं एवं कार्यक्रम अपने अभीष्ट की प्राप्ति के बाट जोह रहे हैं जिनमें स्मार्ट सिटी योजना प्रमुख है, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है। शहर को विकास का इंजन माना जाता है वहीं स्मार्ट सिटी और आदर्श ग्राम योजना का पर्यावरण से भी संबंध है, क्योंकि इसमें स्वच्छ ऊर्जा को महत्व मिलना है। दूसरी अहम बात है जिसका उल्लेख संपादकीय में नहीं किया गया है। वह है, कारगर और विवाद रहित जनसंख्या नीति। यह वैसे ही विचार से परे होंगे जैसे तीन तलाक, अनुच्छेद 370 का हटना, महिला आरक्षण कानून, वक्फ कानून में संशोधन सरीखे कानून रहे। यद्यपि तीन तलाक की तरह वक्फ को लेकर थोड़े बहुत विवाद हैं जो राजनीति से प्रेरित है। वहीं न्यायिक सुधार का मामला थोड़ा जटिल है। इस जटिलता को दूर करने में न्यायपालिका से सहयोग की अपेक्षा है। यद्यपि हमारा देश बड़ा ही नहीं, विविध भी है और अतिशय लोकतांत्रिक और उदारता भी है। जिसका लाभ भ्रष्ट तत्व उठाते हैं। नतीजतन निचले स्तर पर भ्रष्टाचार बदस्तूर जारी है। बड़े देश की आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति नेकनीयत वाली मजबूत सरकार से ही होगी।

मुकेश कुमार मनन, पटना

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

225 अरब डालर तक पहुंच सकता है वैश्विक शिक्षा का बाजार इस वर्ष के अंत तक, लेकिन भारत का हिस्सा अभी इसमें एक प्रतिशत से भी कम है।

उच्च शिक्षा

भारत में भी बढ़ेंगे विदेशी छात्र

भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने और विदेशी छात्रों को आकर्षित करने की दिशा में यूजीसी निरंतर प्रयासरत है। वर्ष 2022 में यूजीसी द्वारा जारी दिशा के अनुसार, विश्वविद्यालयों को विदेशी विद्यार्थियों के लिए वर्तमान सीटों में 25 प्रतिशत विस्तार करना था। परंतु अब तक इस दिशा में कम ही काम हो पाया है। संबंधित बुनियादी ढांचे में यदि पर्याप्त सुधार किया जाए तो इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की जा सकती है

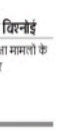

कैलाश विश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

भारतवर्ष की उच्च शिक्षा को विश्व मंच पर स्थापित करने का संकल्प आज एक सुदृढ़ स्वप्न बन चला है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और केंद्र सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं, जिनका लक्ष्य केवल भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता को उन्नत करना ही नहीं, अपितु विदेशी छात्रों को इस देश के शैक्षिक परिसरों की ओर आकर्षित करना भी है। यूजीसी ने 2023 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत विश्व के शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। आस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी और यूके की साउथैंप्टन यूनिवर्सिटी इसके उदाहरण हैं, जो अब भारतीय धरती पर अपनी शाखाएं खोल रही हैं। यह कदम भारतीय छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा का लाभ देगा और विदेशी छात्रों को भी भारत की शिक्षा प्रणाली से जोड़ेगा।

विदेशी छात्रों के लिए भारतीय संस्थानों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें सृजित करने का निर्देश यूजीसी ने दिया है। ये सीटें विदेशी छात्रों को प्रवेश के अधिक अवसर प्रदान करेंगी और भारतीय शिक्षा को विश्व पटल पर प्रचारित करने में सहायक होंगी। यह प्रयास भारतीय संस्थानों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक ठोस कदम है। यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों को मेधा और आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया है। यह व्यवस्था विदेशी छात्रों को आर्थिक संबल देगी और उन्हें भारतीय संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रेरित करेगी। धन की कमी से जो बाधाएं उत्पन्न होती थीं, वे इस कदम से बहुत हद तक दूर होंगी।

वर्ष 2022 में यूजीसी ने भारतीय और विदेशी संस्थानों के मध्य संयुक्त डिग्री और ट्विनिंग प्रोग्राम को शुरुआत की। यह सहयोग छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा का अवसर देगा और भारतीय संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान करेगा। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक सेतु का कार्य करेगा। आमलाइन मंच 'स्वयं' पर यूजीसी ने हजार से अधिक पाठ्यक्रम विकसित किए हैं, जो विश्व भर के छात्रों के लिए सुलभ हैं। यह प्रयास भारतीय शिक्षा को वैश्विक स्तर पर ले जाएगा और विदेशी छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित कराएगा।

विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय मामलों और पूर्व छात्रों से जुड़े सेल स्थापित करने का निर्देश भी यूजीसी ने दिया है। यह व्यवस्था विदेशी छात्रों को भारतीय संस्थानों से जोड़ेगी और उन्हें यहां की शिक्षा के प्रति आकर्षित करेगी। गौरतलब है कि 2016 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा (एनआइआइआरएफ) की शुरुआत हुई, जो भारतीय संस्थानों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है। यह रैंकिंग विदेशी छात्रों को भारतीय संस्थानों की गुणवत्ता पर भरोसा दिलाएगी और उन्हें यहां अध्ययन के लिए प्रेरित करेगी।

चुनौतियां : विदेशी छात्रों को भारत की शैक्षणिक भूमि पर आमंत्रित करने की प्रक्रिया में कुछ ऐसे कांटे बिछे हैं, जिन्हें समय रहते हटाना होगा। विदेशी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की लागत और पर्याप्त छात्रवृत्तियों का अभाव एक प्रमुख बाधा है। वित्तीय सहायता का अभाव विशेष रूप से शैक्षिक स्तरों और क्षेत्रों में भिन्न होता है, जो छात्रों को अन्य देशों की ओर आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए, यूके और कनाडा जैसे देश छात्रवृत्तियों और वित्तीय सहायता के साथ आकर्षक पैकेज प्रदान करते हैं, जिससे भारत प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाता है। इसके अलावा, भारतीय विधि की वैश्विक रैंकिंग और पहचान में कमी, अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा को कठिन बनाती है।

जटिल और समय लेने वाली वीजा प्रक्रियाएं छात्रों को हतोत्साहित करती हैं। ऐसे में भारत को वीजा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य देश जैसे आस्ट्रेलिया और कनाडा ने वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाकर छात्रों को आकर्षित किया है। विदेशी छात्रों के लिए विशेष वीजा श्रेणी बनाई जानी चाहिए, जिसमें आमलाइन आवेदन और त्वरित स्वीकृति की सुविधा हो। उच्च शिक्षा में बुनियादी ढांचे की कमी भारत को अन्य देशों जैसे मलेशिया और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने से रोकती है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी माडल के जरिए बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी जा सकती है।

आगे की राह : छात्रों के लिए बेहतर जीवनशैली और शैक्षिक अनुभव सुनिश्चित करने हेतु कैंपस सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। साथ ही, सरकार को विदेशी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने चाहिए, जो ट्यूशन फीस और रहने के खर्च को कवर करें। शिक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाकर और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके आकर्षक वित्तीय पैकेज तैयार किए जा सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की निम्न रैंकिंग गुणवत्ता के प्रति नकारात्मक धारणा बनाती है। ऐसे में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों में निवेश करना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाना, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना और विदेशी प्रोफेसरों को भारत में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इसके अलावा, शिक्षकों और छात्रों को वैश्विक मंचों पर भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जानी चाहिए। इन सुझावों को लागू करने से भारत न केवल विदेशी छात्रों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन सकता है, बल्कि वैश्विक शिक्षा बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता भी बढ़ा सकता है। इसके लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, जो नीतिगत सुधारों और संस्थागत सहयोग से संभव हो सकेगा।

वैश्विक मानकों के अनुरूप शैक्षिक व्यवस्था होने पर भारत में भी बड़ी संख्या में आ सकते हैं विदेशी छात्र। फाइल

विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन

रोहित प्रियदर्शी
लोक नीति विश्लेषक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने 2023 के दिशा-निर्देशों के तहत पहली बार भारत में विदेशी शैक्षणिक परिसरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय में अमेरिका के इलिनायस इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी और आस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सहित कुल पांच प्रख्यात विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है, जो 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से भारत में अपने कैंपस शुरू करने की योजना बना रहे हैं। उच्च शिक्षा के लिए वर्षों से विदेश की राह पकड़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों के लिए यह राहत की खबर साबित होगी, क्योंकि अब वे वैश्विक गुणवत्ता की शिक्षण सुविधाएं अपनी मातृभूमि की सीमाओं के भीतर ही पा सकेंगे।

भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य में एक नया अध्याय तब जुड़ा, जब यूजीसी ने 2023 में विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति दी। यह निर्णय केवल एक स्थापित नियम नहीं था, बल्कि शिक्षा के वैश्विक मानचित्र पर भारत की स्थिति को मजबूती से स्थापित करने का स्पष्ट इरादा दर्शाता है। यूजीसी के नए दिशा-निर्देशों के तहत केवल वैश्विक शीर्ष 500 में शामिल उन विश्वविद्यालयों को ही भारत में शाखा खोलने की पात्रता मिली, जिससे इस पहल की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। इन विश्वविद्यालयों को संस्थागत स्वायत्तता का पूर्ण अधिकार दिया गया है, यानी वे प्रवेश नीति, शुल्क संरचना और पाठ्यक्रम निर्धारण संबंधी निर्णय अपने विवेक से ले सकेंगे। इससे वे अपने बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार कर सकेंगे।

इस निर्णय के पीछे भारत को एक ग्लोबल शिक्षा हब बनाने का लक्ष्य निहित है। इस पहल से विद्यार्थियों को स्थानीय परिवेश में ही अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक माहौल का अनुभव मिलेगा, जहां भारतीय और विदेशी दोनों तरह के छात्र मिल-जुलकर अध्ययन करेंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत आने से हमारे शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जब गुणवत्तापूर्ण विकल्प उपलब्ध होंगे, तो भारतीय विश्वविद्यालय भी अपनी पाठ्यक्रम संरचना, शिक्षण पद्धतियों और शोध गतिविधियों को मजबूत करने के लिए प्रेरित होंगे। परिणामस्वरूप संपूर्ण शिक्षा गुणवत्ता में सुधार आएगा, जिससे समग्र शिक्षण-शिक्षण अनुभव ही नहीं, बल्कि रोजगार के अवसर भी व्यापक होंगे।

इस पहल का आर्थिक पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश प्रवाह से भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। नए परिसरों के निर्माण, संकाय नियुक्ति, समग्री खरीदारी और स्थानीय सेवाओं के लिए खर्च से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी तरह विदेशी छात्रों के आगमन से आवास, भोजन, परिवहन और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी अर्थव्यवस्था को भी भरपूर प्रोत्साहन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भारत का शिक्षा बाजार 2025 में 225 अरब डालर तक पहुंचने की संभावना है, जो वैश्विक शिक्षा बाजार के 7.6 लाख करोड़ डालर के आकार की तुलना में केवल तीन प्रतिशत हिस्सा ही है।

वहीं दूसरी ओर, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने से शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होगा। विदेशी निवेश और स्थानीय रूप से उत्पन्न रोजगार अवसर अर्थव्यवस्था को स्थिरता और मजबूती प्रदान करेंगे। अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त डिग्रियां छात्रों के करियर को नए आयाम देंगी तथा वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएंगी। अनुसंधान एवं नवाचार के क्षेत्रों में सहयोगी प्रयासों से नई खोजों और तकनीकी प्रगति को गति मिलेगी, जिससे न केवल शिक्षा, बल्कि उद्योग जगत को भी लाभ होगा। वहीं, छात्रों को विदेशी संस्कृतियों, भाषाओं और विचारधाराओं का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा, जो उनके व्यक्तित्व विकास और वैश्विक दृष्टिकोण को व्यापक बनाएगा।

खरी-खरी

अंधेर नगरी और चौपट राजा

इरम सत्मा

कटौती किए जाने के कारण लंबे समय से उस नगर की बिजली नहीं आ रही थी। अंधेरे के जीव अंधेरे का फायदा उठाकर अपने कारनामों को अंजाम दे रहे थे। चोर, उचक्के और बदमाश अपनी-अपनी कलाओं में सफाई ला रहे थे। उस नगरी का राजा भी गहरी नींद में सो गया था और बच्चा कोतवाल, तो उसकी आंखों में भला नींद कहां? वह भी अंधेरे के कारण से नहीं पा रहा था। चोर, उचक्के और बदमाश सक्रिय हों तो उसकी आंखें नींद कैसे ले सकती थीं। वह सबकी खबर लेकर अपनी जेब गर्म कर रहा था। गलती से मैं जा फंसा उस अंधेर नगरी में। किसी ने मेरे ऊपर टार्च का उजाला फेंका और बोला- 'रुक जाओ। कौन हो तुम?' मैंने मतदाता पहचान पत्र निकाला और बोला- 'मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक मुसव्वि लाल हूं।' इस बार उसने पूछा- 'जानते हो, मैं कौन हूं।' मैंने कहा- 'नहीं सर, मैं शहर में नया हूं। आपको नहीं पहचानता। आप अपना परिचय दीजिए। आपका परिचय पाकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी।' मैंने अंधेरे में उसे गौर से देखा, घनी मूंछों में अटा उसका चेहरा रौबीला तथा हाथ में डंडा था। वह बड़े रौब से बोला- 'मुझे पहचानो, मैं इस शहर का कोतवाल, घासीराम कोतवाल हूं।'

मैंने कहा- 'नाम तो जाना-पहचाना लगता है। लेकिन सर आप इस रात में कहां भटक रहे हैं?' घासीराम कोतवाल बोला- 'मैं मुसव्वि लाल की तलाश में निकला था और वह मिल गया। मैं भटक नहीं रहा मुखे, मैं शहर की रक्षा में आंखों की नींद उड़ा कर महाराज चौपट सिंह का राज-काज संभाल रहा हूं।' मैं डर गया- 'सर, मैं यहां ठहरने के लिए किसी धर्मशाला की तलाश में हूं।' कोतवाल हंसकर बोला- 'तुम पहले थाने चलो। तुम इस अंधेरी रात में निकले कहां से हो?' मैं बोला- 'सर, मैं तो पास के गांव से आया था। आते-आते रात हो गई। मैं एक सज्जन और ईमानदार आदमी हूं। आप मुझ पर शक कर रहे हैं।'

'हम ठहरे पुलिस वाले, हम शक के आधार पर अपराधी तक पहुंचते हैं, चलो थाने तुम्हारा मतदाता पहचान पत्र मुझे नहीं, चौपट सिंह महाराज को बताना।

पोस्ट

जापान के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना पर दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय का हवाला देने वाले लोग इसे अनदेखा क्यों कर देते हैं कि जहां जापान की जीडीपी 0.6 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है वहीं भारत की जी डीपी लगातार छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज कर रही है।
मिहाज मर्चंट@MinhazMerchant

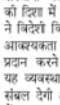

ब्राजील में गुरुकुल चलाने वाले ब्राजीली नागरिक जीनस मसेटटी को पद्मश्री पुरस्कार मिलत देखकर बहुत खुशी हुई। एक समय कुलीन और दरबारी लोगों तक सीमित रहे हमारे योग पुरस्कार अब सुपात्रों को मिलने लगे है। इस मौर्य पर भी देश ने बड़ी ऊंची छलांग लगाई है।
मोनिका वर्मा@TrulyMonica

तो ट्रंप की सीजफायर वाली नौटंकी और उसके लिए टैरिफ ढील का लालच भारत-पाकिस्तान को देने की कहानी अमेरिकी कोर्ट में अमान्य-सनाया टैरिफ लगाने के फैसलों पर चल रहे केस के लिए रची गई थी। यह कहानी भी अमेरिकी कोर्ट ने खारिज कर दी।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया ही जाना चाहिए?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ताऊ जी से मस्क का मोह हो गया भंग,
साफ-साफ है कह दिया नहीं रहेंगे संग।
नहीं रहेंगे संग खत्म अब समझी यारी,
कैसे ही व्यापार संग दोनों व्यापारी!
बनना चाहे ट्रंपहर जगह बड़का भाऊ,
रख कर ये व्यवहार चलेगा कैसे ताऊ!!
- ओमप्रकाश तिवारी

झारखंड डायरी

झारखंड तक पहुंची शराब घोटाले की आंच

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

शराब घोटाले को लेकर झारखंड एक बार फिर से चर्चा में है। इससे पहले झारखंड में अवैध खनन घोटाले और जमीन घोटाले की ईडी जांच के दौरान राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक की गिरफ्तारी का मामला सुर्खियों में रह चुका है। झारखंड के शराब घोटाले में भी अब ईडी और सीबीआइ की जांच की आंच छत्तीसगढ़ से होते हुए धीरे-धीरे यहां तक पहुंच रही है।

वर्तमान में राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी ही इस मामले में पूरे एक्शन में है। राज्य के पूर्व उत्पाद सचिव, उत्पाद विभाग (आबकारी विभाग) के महाप्रबंधक, पूर्व महाप्रबंधक समेत पांच लोग अब तक इस मामले में एसीबी के हाथों गिरफ्तार हो चुके हैं और मैन पावर सप्लाई एजेंसियों के निदेशकों और अफसरों के करीबियों समेत दर्जनभर लोगों को एसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। मामला भी 18 करोड़ रुपये की गड़बड़ी की जांच पर टिका है, लेकिन स्वयं एसीबी भी मान रही है कि यह घोटाला 100 करोड़ रुपये से ऊपर का है। वहीं दूसरी ओर, प्रदेश में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसे दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला बताया है। भाजपा इसी कारण सीबीआइ जांच की आवश्यक बता रही है।

शराब के कारण दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में पहले ही भूचाल आ चुका है। अब छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में शराब घोटाले का जिन्न सामने आया है। यहां के शराब घोटाले की पटकथा भी छत्तीसगढ़ में ही लिखी गई थी। यहां भी शराब की बिक्री में छत्तीसगढ़ का ही माडल अपनाया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के अधिकारी ही यहां की आबकारी नीति के परामर्शी थे। शराब के एक खास सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के लिए उससे जुड़ी शराब कंपनियों और बिक्री एजेंसियों की पूंजी कराई गई, जिससे कमीशन अफसरों की जेब में पहुंचा, लेकिन सरकारी राजस्व को भारी चूना लगा। इस मामले में रांची के ही एक व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जाकर वहां प्राथमिकी दर्ज कराई और झारखंड के शराब घोटाले के तार छत्तीसगढ़ से जुड़े होने का आरोप लगाया। अब इस मामले की सीबीआइ टेकओवर कर चुकी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के क्रम में भी ईडी ने झारखंड के अफसरों से पूछताछ की थी।

राजस्व को क्षति पहुंचाने का आरोप। प्रतीकात्मक

नकली होलोग्राम, मनमाने दर में शराब की बिक्री से लेकर कई गड़बड़ियां अब तक की जांच में उजागर हो चुकी हैं। एसीबी की जांच में भी यह स्पष्ट हुआ है कि नियमों को ताक पर रखकर उन प्लेसमेंट एजेंसियों को काम दिया गया, जिन्होंने विभाग से लेकर कोर्ट तक में बैंक गारंटी के फर्जी कागजात जमा किए थे और विभाग में शराब की बिक्री के पैसे तक जमा नहीं किए थे। घोटाला होने की आशंका इन तथ्यों के आधार पर ही जताई जा रही है।

एसीबी की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल : शराब घोटाले में एसीबी की अचानक तेज हुई जांच को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि बड़े लोगों को बचाने के लिए एसीबी छोटी मछलियों तक ही जांच को केंद्रित कर मामला रफा-दफा कर देना चाहती है। वहीं, भाजपा के वरिष्ठ नेता और झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष विधायक सीपी सिंह ने भी एसीबी के इस मामले में आइएएस अधिकारी विनय चौबे व अन्य की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा है कि एक ही दिन में प्राथमिकी और उसी दिन पूछताछ से लेकर गिरफ्तारी तक, इसमें कहीं न कहीं कोई रणनीति है या फिर राजनीति। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया है कि यदि वास्तविक में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टालरेंस है तो इसकी जांच सीबीआइ से करानी चाहिए।

कभी मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हुआ करते थे चौबे : एसीबी को लेकर भाजपा हमलावर इसलिए भी है, क्योंकि एक समय था जब विनय चौबे मुख्यमंत्री के खासा हुआ करते थे। वह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। वर्ष 2022 की आबकारी नीति लागू हुई तो विनय चौबे उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव थे। दरअसल विनय चौबे पर आरोप है कि उन्होंने नीति में बदलाव कर एक सिंडिकेट को फायदा पहुंचाया, जिसमें शराब की आपूर्ति और मैनपावर सप्लाई के टेंडर में हेराफेरी की गई। अचानक चौबे के कार्रवाई की जद में आने से लोग चौंकि हैं। चौंकने की बड़ी वजह यह भी है कि कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से ही हुई है। हालांकि इस मामले को ईडी ने भी टेकओवर कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि जांच की आंच कहां तक पहुंचती है।

स्मरण

कुशल एवं मजबूत प्रशासक अहिल्याबाई

कल रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती है। देश के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में उनका व्यापक योगदान रहा है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने तीन सौ वर्ष पहले थे। उनके निर्णय समय से आगे के प्रतीत होते हैं

डा. गुंजन राजपूत
रजिस्ट्रार, ऋषिकुल विवि, सोनीपत, हरियाणा

किसी भी देश की मजबूती वहां पर सुदृढ़ व्यवस्था के निर्माण से होती है जिसमें समाज एवं उसके निर्णय भविष्य की दिशा एवं दशा तय करते हैं। इसका बेहतर होना एक अच्छे शासक और शासन पर बहुत हद तक निर्भर करता है। एक शासक में मानसिक एवं वैचारिक मजबूती, दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता एवं भावनात्मकता होना अनिवार्य है। किसी एक के भी अभाव में निर्णयों की गंभीरता चरमरा जाती है। भारत की आज की मजबूती के पीछे आज का सफल शासनकाल एवं उसकी मजबूत नीतियां हैं, परंतु भारत जिन हित से परे, धर्म की राह पर चलने वाले, जन एवं राष्ट्र सेवक जैसे आदर्शवादी शासकों की संतानों की भूमि रहा है जिसका एक उदाहरण थीं- अहिल्याबाई होलकर।

''न्याय वह नींव है जिस पर एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण होता है''- इस कथन से उनका राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण भलीभांति समझा जा सकता है। उनके द्वारा लिए गए निर्णय अपने समय से बहुत आगे के सोच को दर्शाते हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सामान्य परिवार की बालिका से एक असाधारण शासक तक की उनकी जीवनयात्रा आसान नहीं थी या कह सकते हैं कि जटिलताओं से भरी थी। भारत की आज जहां महिलाओं के पिछड़ेपन के लिए विश्वस्तर पर नकारात्मक छवि के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वहीं हमारा इतिहास ऐसी शासिकाओं का है जो आज के संदर्भ में न केवल महिलाओं, बल्कि हर शासक के लिए बहुत ही सटीक उदाहरण हैं।

कम उम्र में बड़ी जिम्मेदारी : अहिल्याबाई ने अपना जीवन अपने परिवार की देखरेख और समर्पण से शुरू किया। जब तक उनके पति राजकुमार खांडे राव जीवित थे, तब तक अहिल्याबाई ने अपनी उम्र के किसी भी अन्य युवा मराठा महिला की तरह ही एक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया, परिवार और घरेलू मामलों की देखभाल की। परंतु परिवार के सुख की अवधि लंबी नहीं थी। वर्ष 1754 में जाट किले कुंभेर की घेराबंदी के दौरान उनके पति की अचानक मृत्यु हो गई जिससे वह महज 29 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गईं। इसके बाद उन्हें वे सभी जिम्मेदारियां उठानी पड़ीं जो आमतौर पर परिवार के पुरुष सदस्यों पर होती हैं। उनकी बेटी मुक्ताबाई ने अपने पति के निधन के बाद सती होने का निर्णय लिया और सती प्रथा के लिए लड़ने वाली अहिल्याबाई अपनी ही बेटी को सती होने से रोकने में सफल नहीं हुईं। ऐसे में मन का विचलित होना एक कुशल शासक के धैर्य एवं उसके निर्णय को क्षमता को प्रभावित करता है। परंतु निजी जीवन में सबकुछ खो देने के बाद भी अहिल्याबाई एक निडर योद्धा की तरह अंत तक लड़ती रहीं। जहां आज काम में एकाग्रता के लिए लोग परिवार को अहमियत नहीं दे पाते, वहां परिवार, उसकी जिम्मेदारियों, उसके दुखों-सुखों के साथ समाज के लिए सही निर्णायक बनना अहिल्याबाई से सीखना आवश्यक है। धीरे-धीरे वह एक ऐसी शासक बनकर उभरीं, जो लोगों से प्यार एवं सहानुभूति रखने लगी।

प्रजा की शिकायतों को दूर करने के लिए रोजाना सार्वजनिक बैठकें करती थीं। जैसा कि ब्रिटिश शासक जान मैल्कम लिखते हैं, 'उन्होंने प्रत्येक शिकायत को व्यक्तिगत रूप से सुना, उन्होंने सबसे अल्पतम अवधि के दौरान मध्य भारत के एक बड़े हिस्से को शांति और अच्छा प्रशासन दिया और उनके 30 वर्षों के शासन को उदार और प्रभावी सरकार का एक माडल माना जाता है।' उनसे सीख जा सकता है कि अगर आपको समाज के हर व्यक्ति के अनुरूप फैसले लेने हैं तो समाज के हर अंग को समझना अत्यंत आवश्यक है। शासक के हर फैसले में सामाजिकता तभी आएगी, जब उसे समाज की समझ होगी। अन्यथा फैसले बदलेंगे और बदलाव नहीं ला पाएंगे। समाज की हर समस्या के लिए उत्तरदायित्व लेना साथ में करुणामय होना एक प्रयत्नशील नेतृत्व के लिए अत्यंत आवश्यक है।

भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन : समाज एवं संस्कार का उद्भव केवल समस्याओं के समाधान से नहीं, अपितु उनके उत्कर्ष से संभव है। और यह एक गूढ़ शासक के समझ की भी निशानी है। आज का 'मेक इन इंडिया' उसका उदाहरण है जिसके बारे में अहिल्याबाई अपने शासनकाल में सोच चुकी थीं। आज भारतीय परिधान-महेश्वरी साड़ियां जहां विश्वस्तरीय रूप से भारतीय संस्कृति को दर्शाती हैं, उसको जीवंत रखने का श्रेय भी रानी को ही जाता है। देवी अहिल्याबाई ने बुनकरों को संरक्षण दिया और उनके काम और कल्याण में व्यक्तिगत रुचि ली। समय के साथ, इन बुनकरों द्वारा उत्पादित महेश्वरी साड़ियां प्रसिद्ध हो गईं। इन साड़ियों को बुनने और छापने को कला इन बुनकरों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। उन्होंने उद्योग स्थापित किए थे, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और उन्हें इतना मजबूत बनाया कि महेश्वर का कपड़ा उद्योग आज भी चल रहा है और कई लोगों को रोजगार दे रहा है।

महारानी अहिल्याबाई होलकर।

अहिल्याबाई ने परिवारवाद को कभी बढ़ावा भी नहीं दिया जिसे उनके अपने ही पुत्र के संबंध में लिए गए कड़े निर्णयों के संबंध में देखा जा सकता है। अर्थात शासन की कला विरासत में मिले यह जरूरी नहीं और आप अपनी गुणवत्ता विरासत में दें यह भी आवश्यक नहीं। वह हर उस योग्य को मिलनी चाहिए जिसके गुण एक शासक के हों। आज के किसी भी शासक को अहिल्याबाई के सेवा के कामों को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वह सती प्रथा के समापन, चाहे महेश्वर की साड़ियां, चाहे महिलाओं की शस्त्र विद्या, चाहे परिवार के लिए त्याग, चाहे सटीक युद्ध नीति हो।

कल्पमेधा

यही सबसे जरूरी समय है जब मां-बाप अपने बच्चों को यह सिखाएं कि विविधता में ही वास्तविक सौंदर्य और शक्ति है।

- माया एंजिलो

सत्ता और शांति

मणिपुर में लंबे समय से शांति बहाली के प्रयास चल रहे हैं। वहां करीब दो वर्ष पहले मैतेई और कुकी समुदायों के बीच टकराव की शुरुआत के बाद हालात इस कदर बिगड़ गए कि उसे संभाल पाना राज्य की तत्कालीन सरकार के लिए संभव नहीं हुआ और इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री एस बीरेन सिंह को आखिर इस्तीफा देना पड़ा। पिछले तीन महीने से वहां राष्ट्रपति शासन लागू है। यों हिंसा और संघर्ष पर काबू पाने में नाकामी की वजह से पहले से ही वहां राष्ट्रपति शासन की मांग हो रही थी। विडंबना यह है कि आज भी मैतेई और कुकी समुदायों के बीच टकराव को खत्म करना और सर्वसम्मति से समाधान तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो सका है। ऐसे में यह सवाल लाजिमी है कि नई सरकार के गठन के लिए जो कवायद शुरू हुई है और किन्हीं हालात में यह संभव हो पाता है, तो क्या इससे मणिपुर की मौजूदा समस्या का कोई ठोस हल निकल सकेगा और क्या वहां हिंसा और टकराव का दौर खत्म हो पाएगा।

गौरतलब है कि मणिपुर में राजग के दस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर चौवालीस विधायकों के समर्थन का हवाला देते हुए सरकार गठन की मांग की है। विधायकों के इस समूह ने सरकार गठन को जनता की इच्छा बताया। लेकिन अगर इन विधायकों के साथ कुकी समुदाय के दस विधायक नहीं हैं, तो ऐसे में इस समूह के पास राज्य की सबसे मुख्य समस्या से पार पाने के लिए क्या योजना और दृष्टि है। राज्य में नई सरकार बनाने के पक्ष में भाजपा सहित राजग के कई विधायक जरूर हैं, लेकिन भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व अब भी सरकार के बनाने के दावों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से मणिपुर में निकट भविष्य में राष्ट्रपति शासन नहीं हटाने की भी खबर आई है। ऐसे में नई सरकार के गठन की मांग के धरातल पर उतरने की उम्मीद फिलहाल आगे की बात लगती है। इसके बावजूद यह सच है कि मणिपुर में शांति बहाली और सामुदायिक टकराव के कारणों को दूर कर दूरगामी हल निकलना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए ही संभव है।

हालांकि मणिपुर में नई सरकार के गठन को लेकर चाहे जो भी कोशिशें चल रही हों, लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी यह है कि वहां आम जनजीवन जिस अस्थिरता और आए दिन हिंसक सामुदायिक टकराव से दो-चार है, उसका कोई ठोस समाधान निकाला जाए। मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के सवाल पर दो वर्ष पहले जिस हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसमें अब तक ढाई सौ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। आज भी आए दिन गोलीबारी या हिंसक घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। हैरानी की बात यह है कि राज्य से लेकर केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच ऐसी खाई बन गई है, जिसे पाटे बिना किसी दीर्घकालिक हल तक नहीं पहुंचा जा सकता। मगर दोनों समुदायों में परस्पर विश्वास बहाली को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जो संवाद का कोई सार्थक पुल तैयार करे और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालने की कोशिश हो। आज भी अगर मणिपुर का आम जनजीवन अस्थिर है, तो इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? जाहिर है, नई सरकार के गठन के प्रयासों के समांतर जरूरत इस बात की है कि वहां संघर्षरत समुदायों के बीच विश्वास और संवाद कायम किया जाए।

जिम्मेदारी के बजाय

संसदीय समितियों की बैठकों में सांसदों की कम भागीदारी वास्तव में चिंता का विषय है। लोग इस उम्मीद के साथ अपने प्रतिनिधि संसद में भेजते हैं कि उनके बुनियादी हितों की बात वहां सही तरीके से रखी जाएगी। मगर लोकसभा की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों से पता चलता है कि निचले सदन की सोलह स्थायी समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति औसतन महज साठ फीसद रही है। संसदीय समितियों की बैठकों में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है और जरूरी सुधारों का खाका तैयार किया जाता है। इसका मकसद सरकारी योजनाओं और नीतियों को बेहतर ढंग से लागू करना और सभी पात्र लोगों तक इनका लाभ पहुंचाना होता है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि कई सांसदों के भीतर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अहसास क्यों नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई अवसरों पर संसदीय समिति और संसद की कार्यवाही में सांसदों की सहभागिता के महत्त्व को रेखांकित कर चुके हैं। मगर संसद की स्थायी समितियों में सांसदों के गैरहाजिर रहने का सिलसिला हैरान करने वाला है।

गौरतलब है कि संसद में विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अलग-अलग स्थायी समितियां होती हैं। कई बार सरकार की ओर से तैयार की गई योजनाओं और नई नीतियों व कानूनों का मसविदा इन समितियों के पास विचार के लिए आता है। आमतौर पर विपक्षी दलों की यह मांग रहती है कि कोई भी विधेयक सदन में पेश किए जाने से पहले विचार-विमर्श के लिए संबंधित स्थायी समिति के पास भेजा जाए। अफसोस की बात है कि इन समितियों की बैठकों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी का अहसास सांसदों में कम ही नजर आता है। अंदाजा इस बात से लगाया सकता है कि इस वर्ष बीस मई को विदेश मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति की बैठक में केवल तेरह सदस्य उपस्थित थे, जबकि 16 मई को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विषय पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय से संबद्ध समिति की बैठक में केवल बारह सदस्य मौजूद थे। ऐसे में सांसदों से यह उम्मीद स्वाभाविक है कि वे संसद में तय किए जाने वाले नियम-कायदों या बनने वाली व्यवस्था में जनता के हित में संसदीय समितियों में होने वाले विमर्श के तहत सक्रिय भागीदारी करें।

बदलाव का वाहक बनती मधुमक्खियां

मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है, जिसमें रोजगार, पर्यावरण संतुलन, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संभावनाएं घुली हुई हैं। ये संभावनाएं केवल शहद बेचने तक सीमित नहीं, बल्कि एक पूरी मूल्य शृंखला का निर्माण करती है जो भारत को 'मीठी क्रांति' की ओर ले जा सकती है।

सोनम लववंशी

गांव की किसी पगडंडी पर चलते हुए दूर से आती भनभनाहट और रंग-बिरंगी मधुमक्खियों की कतार देख कर बहुत से लोग शायद यही सोचें कि यह प्रकृति का कोई सामान्य दृश्य है। मगर यही मधुमक्खियां अब ग्रामीण भारत में बदलाव की नई तस्वीर बना रही हैं। मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है, जिसमें रोजगार, पर्यावरण संतुलन, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संभावनाएं घुली हुई हैं। ये संभावनाएं केवल शहद बेचने तक सीमित नहीं, बल्कि एक पूरी मूल्य शृंखला का निर्माण करती हैं जो भारत को 'मीठी क्रांति' की ओर ले जा सकती है। भारत में मधुमक्खी पालन की परंपरा कोई नई नहीं है, लेकिन जिस रूप में अब यह वैज्ञानिक, संगठित और व्यवसायिक स्तर पर सामने आ रही है, वह पिछले कुछ दशकों की मेहनत और जागरूकता का परिणाम है।

देश में शहद का उत्पादन 1.33 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। यही नहीं, भारत से शहद का निर्यात भी अब 50 से अधिक देशों में हो रहा है, जिससे 750 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। आंकड़े केवल व्यापार की कहानी नहीं सुनाते, ये एक नई आजीविका, आत्मनिर्भरता और जैव विविधता की संभावनाओं का द्वार खोलते हैं।

मधुमक्खी पालन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बहुत कम निवेश में शुरू हो सकता है। किसी भी उम्र, वर्ग और शिक्षा स्तर का व्यक्ति इसे सीख कर अपना काम शुरू कर सकता है। देश के कई हिस्सों में इस व्यवसाय ने बेरोजगार युवाओं, छोटे किसानों, महिलाओं और आदिवासियों को एक स्थायी और सम्मानजनक आय का माध्यम दिया है। झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में अब यह एक मजबूत ग्रामीण उद्यम बन कर उभरा है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) जैसी योजनाएं भी इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई हैं। वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसके लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया गया। इससे प्रशिक्षण, उपकरण, कालोनी वितरण, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन के लिए सुदृढ़ संरचना विकसित की जा रही है।

मधुमक्खी पालन का एक बड़ा वैज्ञानिक पहलू यह भी है कि यह केवल शहद के लिए नहीं, बल्कि परागण के लिए भी अत्यंत जरूरी है। शोध बताते हैं कि जिन खेतों में मधुमक्खियों की उपस्थिति होती है, वहां फसलों की उत्पादकता में 15 से 40 फीसद तक की वृद्धि देखी जाती है। इसका सीधा लाभ किसानों को होता है, क्योंकि बिना किसी अतिरिक्त लागत के उसकी फसल अधिक फलने-फूलने लगती है। सरसों, सूरजमुखी, तिल, सेब, अमरूद, मूंगफली और खीरा जैसी कई फसलें ऐसी हैं जो मधुमक्खियों की मदद के बिना बेहतर उपज नहीं दे सकतीं। यानी मधुमक्खी न केवल शहद देती है, बल्कि किसान की जमीन भी उपजाऊ बना देती है। इतना ही नहीं, मधुमक्खी पालन से मोम, जेली और मधु पराग जैसे उच्च मूल्य वाले उत्पाद भी मिलते हैं, जिनका उपयोग औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पूरक और आयुर्वेदिक दवाओं में होता है। मोम से बनी मोमबत्तियां, साबुन और क्रीम अब शहरी बाजारों में उच्च मांग वाले उत्पाद बन चुके हैं।

भारत में शहद की मांग लगातार बढ़ रही है, विशेषकर कोविड के बाद जब लोग प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए प्राकृतिक विकल्पों की ओर मुड़े। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में शहद को 'योगवाहि' कहा गया है, जो अन्य औषधियों को शरीर में पहुंचाने में सहायक होता है। यही नहीं, 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथारिटी आफ इंडिया' यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भी शुद्ध शहद के लिए नए मानक तय कर दिए हैं, जिससे बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की मांग और बढ़ी है। इस बदलाव ने प्रशिक्षित मधुमक्खी पालकों के लिए बड़ा बाजार खोल दिया है। हालांकि, यह राह पूरी तरह फूलों से नहीं भरी है। जलवायु परिवर्तन, कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल, जैव विविधता का ह्रास और शुद्ध चारागाहों की कमी मधुमक्खियों के लिए खतरे की घंटी हैं। भारत में पांच प्रमुख मधुमक्खी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कई प्रजातियां आज घटती जा रही हैं। शोध बताते हैं कि यदि मधुमक्खियां विलुप्त हो जाएं, तो केवल चार वर्षों के भीतर पूरी खाद्य शृंखला अस्तोलित हो सकती है। इसलिए यह न केवल एक व्यवसाय है, बल्कि प्रकृति संरक्षण की भी एक जिम्मेदारी है।

भारत में मधुमक्खी पालन उद्योग ने पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास किया है। आंकड़े बताते हैं कि शहद उत्पादन और निर्यात में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच भारत का घरेलू शहद उत्पादन 72 फीसद बढ़ कर 77,000 टन से 1,33,000 टन तक पहुंच गया, जबकि निर्यात 86 फीसद की बढ़ोतरी के साथ 43,000 टन से लगभग 80,000 टन तक जा पहुंचा। आज भारत वैश्विक शहद बाजार में छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। हालांकि, निर्यात का अधिकांश हिस्सा, लगभग 80 फीसद, अमेरिका तक सीमित है, जबकि यूरोपीय संघ और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे नए बाजारों में प्रवेश कर भारत इस उद्योग को और अधिक विस्तार दे सकता है। सरकार भी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है।

भविष्य की दृष्टि से देखें तो भारत में मधुमक्खी पालन को एक संगठित कृषि सहयोगी व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकता है। कृषि, बागवानी और मधुमक्खी पालन को एकीकृत करने की योजनाओं और डिजिटल विपणन मंच की उपलब्धता ने इस क्षेत्र को नई उड़ान दी है। आज कुछ ग्रामीण युवा न केवल अपने गांव में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, बल्कि ई-कामर्स वेबसाइटों और सोशल मीडिया के माध्यम से देशभर में अपना नामी शहद बेच रहे हैं। युवा किसानों को इस ओर आकर्षित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और विज्ञान केंद्रों की ओर से चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक ओर जहां मधुमक्खी पालन किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक है, वहीं यह महिला सशक्तीकरण का भी माध्यम बन रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, झारखंड के गुमला और राजस्थान के बांसवाड़ा जैसे क्षेत्रों में सैकड़ों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों की मदद से मधुमक्खी पालन कर आत्मनिर्भर हो चुकी हैं।

> **पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी यह एक हरित व्यवसाय है। न तो इसमें बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता होती है, न ही भारी मशीनरी की और न ही कार्बन उत्सर्जन होता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो प्रकृति से सीधे जुड़ता है और टिकाऊ विकास की अवधारणा को साकार करता है। जिस समय दुनिया जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ आजीविका की बात कर रही है, भारत का मधुमक्खी पालन एक प्रेरणा बन सकता है। इस पूरे परिदृश्य में एक बात स्पष्ट है कि मधुमक्खी पालन अब केवल एक ग्रामीण कारीगरी नहीं रहा, यह आधुनिक कृषि विज्ञान, उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक बाजार की संभावनाओं से जुड़ चुका है।**

पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की दृष्टि से भी यह एक हरित व्यवसाय है। न तो इसमें बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता होती है, न ही भारी मशीनरी की और न ही कार्बन उत्सर्जन होता है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जो प्रकृति से सीधे जुड़ता है और टिकाऊ विकास की अवधारणा को साकार करता है। जिस समय दुनिया जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ आजीविका की बात कर रही है, भारत का मधुमक्खी पालन एक प्रेरणा बन सकता है। इस पूरे परिदृश्य में एक बात स्पष्ट है कि मधुमक्खी पालन अब केवल एक ग्रामीण कारीगरी नहीं रहा, यह आधुनिक कृषि विज्ञान, उद्यमिता, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक बाजार की संभावनाओं से जुड़ चुका है। यह शहद से आगे की कहानी है, फूलों से शुरू होकर खेतों तक और खेतों से होकर आर्थिक स्वतंत्रता तक पहुंचने वाली।

आज जब भारत आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है, तब हर गांव में गूंजती मधुमक्खियों की भनभनाहट हमें यह याद दिला रही है कि असली शक्ति हमारे खेतों, फूलों और हाथों में है। शहद की मिठास न केवल स्वाद है, यह ग्रामीण भारत की संभावनाओं का एक सुवासित प्रतीक भी है। एक उड़ान, जो आत्मनिर्भरता, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की ओर जाती है।

प्रसन्नता के प्रतीक

अशोक कुमार

मानव सभ्यता के आरंभ से ही दुख-सुख जीवन के साथी रहे हैं। यह प्राकृतिक स्थिति है कि हम खुशी के अनेक पलों को बखूबी जीते हैं, लेकिन दुख की हल्की छाया से भी हम असहज और चिंतित हो जाते हैं। सुख और दुख एक ऐसा अस्थायी चक्र है, जिससे संसार का कोई भी प्राणी मुक्त नहीं है। कई शोध प्रबंधों ने यह सिद्ध किया है कि खुशी वह भाव तरंग है जिससे व्यक्ति चिंता, तनाव एवं बीमारियों से बहुत हद तक मुक्त रहता है। व्यक्ति की दिनचर्या में यह साक्षात रूप में देखा गया है कि खुश रहना भागदौड़ भरी जिंदगी और एक दूसरे से आगे बढ़ने की अस्वस्थ प्रतियोगिता ने लोगों के चेहरे पर खुशी कम कर दी है। भौतिक व्यामोह ने जीवन के सबसे अहम पहलुओं में से खुशी के पल को नजरअंदाज किया है। मनोचिकित्सकों का कथन है कि प्रसन्न व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी होती है, ये अपने निर्धारित दायित्व पालन में सफल होते हैं, परिवार और समाज के कार्यों में वे अच्छी तरह हाथ बंटाते हैं और कई शारीरिक व्याधियों से वे बचे भी रहते हैं। वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक के ताजा आंकड़े के मुताबिक, 147 देशों में भारत का स्थान 118 वां है, जबकि वर्ष 2022 में हम 92 वें स्थान पर थे। तो क्या खुशियों का पैमाना क्षरण की ओर अग्रसर है? इसके क्या कारण हैं? खुशी हमारे चिंतन स्वभाव का एक सांयोगिक हिस्सा है, जिसे हम महसूस करते हैं। दुखी होने के कई कारणों में वैसी घटनाएं मानी जाती हैं जो हमारे वैचारिक भूमि से मेल नहीं खातीं, जबकि खुश रहने की स्थितियों में हमारे मन की अनुकूलता की अनुभूति से तारतम्य बनाए रखता है।

अक्सर हम दैनिक जीवन में होने वाली मामूली बातों से अपनी खुशी खो देते हैं। उस समय थोड़े धैर्य से हम यह नहीं विचार करते कि किसी अचानक उपजी स्थिति की गहराई में क्या मर्म है। जब हम खुशी खोते हैं, उस समय हमारे मानसिक प्रवाह की दिशा में उदासी, चिड़चिड़ापन और निष्क्रियता के तरंग उत्पन्न होने लगते हैं, जिसे सामान्य होने में अधिक समय लगता है। ऐसा ही मन का स्वभाव है, जो छोटी-मोटी बातों को बढ़ा-चढ़कर जीवन के अनुभूति आंगन में प्रवेश कर जाता है, जबकि जो खुशी अंतर्चेतना में मौजूद है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हालांकि खुशी सिर्फ एक व्यक्ति के आनंदित होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक संचारी गुण है। पारिवारिक आंगन में यह आमतौर पर देखने को मिलता है कि अगर घर का एक सदस्य खुश है और शेष कई सदस्य दुखी हैं, तो एक की निजी खुशी में स्थायीपन नहीं हो सकता।

हमारे आसपास के लोगों का सुख-दुख हमारी स्वयं की प्रसन्नता को निश्चित तौर पर प्रभावित करता है। इसी परिप्रेक्ष्य में सभी के सुखी और आनंदित रहने के लिए 'सर्वे भवंतु सुखिनः' के पुनीत संदेश लोक जीवन में एक अमूल्य स्थान रखे हुए है। कभी-कभी परिवार या समाज में कोई अप्रिय घटना के कारण अधिकांश लोग दुखी हो जाते हैं, जिसमें हमारी आंतरिक स्थिरता और साहस पीड़ित के लिए सहारा और संबल बन जाती है। ऐसे पल में खुशी के भाव निश्चित रूप में प्रकट नहीं होते, बल्कि यह अचेतन आवरण का तात्कालिक हिस्सा हो जाता है। हमारी खुशी अन्य पर आश्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह उनके उत्थान और सहचरता का कारण होना चाहिए।

लोक मान्यता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही सुख या दुख का भागीदार बनता है। शायद इस तर्क के पीछे यह उद्देश्य रहा हो कि व्यक्ति अच्छे व्यवहार और आचरण का प्रदर्शन करना अपनी दैनंदिनी में शामिल करे। कुछ ऐसे भी दृष्टांत देखे जाते हैं जब किसी को खुश करने के लिए कुछ भी चेष्टा करें, वे दुखी ही बने रहते हैं और वाद भी कह देते हैं कि दुख मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। यह हालत वाद में मानसिक अवसाद के रूप में प्रकट होने लगता है। अनेक दार्शनिकों ने कहा है कि खुशी बिल्कुल निजूल्क है जो हम सभी के अंतर्मन में छिपा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि खुशी धन, दौलत और भौतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। कई लोग नियमित रूप से पर्यटन प्रकल्प से जुड़कर अपने को तरोताजा रखते हैं जो खुशी का मनोहारी बिंदु है। हमारा मन एक कामना की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा की पूर्ति के लिए सचेष्ट हो जाता है। इसकी तीव्रता हमें कई ऐसे उपसर्ग से घेर लेती है, जब हम अपनी आंतरिक प्रसन्नता को विचलन की दिशा प्रदान कर देते हैं।

आमतौर पर किसी के कटु या अप्रिय बोल हमें असहज करते हुए क्रोध पैदा करते हैं। बौद्ध दर्शन का एक कथन है कि व्यक्ति को नकारात्मक वाक्यों को तुरंत नजरअंदाज कर देना चाहिए। नवजात शिशु के मन भी सुख-दुख की कसौटी पर परखे गए हैं। कोई बात उसके मनानुकूल न होने पर वह रोने लगता है, लेकिन ज्यों ही उसे मन के अनुसार कोई खिलौने दिए जाते हैं, वह खुश होकर मुस्कुरा देता है।

जीवन की जटिलता के वर्तमान दौर में खुश रहना आसान भले नहीं लगता, लेकिन यह असंभव नहीं है। हमारी दिनचर्या में अनेक प्रसंग उपस्थित होते हैं जो हमारी प्रसन्नता के पर्याय बन सकते हैं। खुशी अपने भीतर भी होती है। जरूरत है कि हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहजता और सरलता लाएं। छोटी-मोटी प्रतिकूल स्थितियों में घबराएं नहीं। हिम्मत बनाए रखें, यह सोचकर कि जरा भी धैर्य खोने से हमारी मानसिक सक्रियता बाधित हो सकती है और उसके कारण आगे के दायित्व पालन में हम शिथिल हो सकते हैं। अपने स्वजनों, मित्रों और पड़ोसियों के साथ मिल कर उनके प्रति करुणा और दयालुता के भाव प्रदर्शन से खुशी के भंडार में वृद्धि हो सकती है। पशु पक्षी को पूरे दिन में जितने आहार मिलते हैं, वे उसी में मगन रहते हैं और दूसरे दिन के लिए कुछ संग्रह नहीं करते। हमें कुछ दिनों तक प्रयोग कर यह मीमांसा करनी चाहिए कि खुशी का पैमाना क्या है।

दुनिया मेरे आगे

> **जीवन की जटिलता के वर्तमान दौर में खुश रहना आसान भले नहीं लगता, लेकिन यह असंभव नहीं है। हमारी दिनचर्या में अनेक प्रसंग उपस्थित होते हैं जो हमारी प्रसन्नता के पर्याय बन सकते हैं। खुशी अपने भीतर भी होती है। जरूरत है कि हम अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहजता और सरलता लाएं।**

टूटते सपने

'खुदकुशी के परिसर' (संपादकीय, 26 मई) पढ़ा। राजस्थान का कोटा शहर इंजीनियरिंग और चिकित्सा की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों का केंद्र है। यह भी सच है कि यहां के कोचिंग केंद्रों से कई युवा देश के आइआइटी और विभिन्न चिकित्सा विद्यालयों में प्रवेश के लिए तैयारी करते हैं। मगर एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि कोटा में तैयारी कर रहे यही प्रतिभाशाली छात्र पढ़ाई के दबाव में और असफलता के डर से आत्महत्या का रास्ता अपना लेते हैं और अपने परिवारों के सपने चकनाचूर कर देते हैं। यह एक गंभीर स्थिति है। इस पर सभी को सोचना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं, लेकिन इस सबके बावजूद कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की आत्महत्या पर प्रभावी लगाम नहीं लगाई जा सकी है। असफलता का अर्थ यही होता है कि हमारे प्रयासों में ही जायद कुछ कमी रही होगी। निश्चित सफलता पाने के लिए अब फिर से कदम उठाने होंगे। खुदकुशी की समस्या की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास करने की जरूरत है।

- इशरत अली कादरी, भोपाल

चीन का चेहरा

हाल ही में चीन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकारों के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। इसका उद्देश्य भारत को यह संदेश देना था कि तालिबान भारत विरोधी है। इस बैठक में चीन और पाकिस्तान ने 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे' को अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमति जताई। इसके अलावा चीन पाकिस्तान की सेना को भी मजबूत करने में जुटा हुआ है। हाल ही में 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान के नौ वायुसेना प्रणाली को तबाह कर दिया गया, जिन पर चीन के राडार थे। तब से चीन बौखलाया हुआ है। वह पाकिस्तान को आगे कर भारत को अस्थिर करने की नई योजनाएं बना रहा है। इससे भारत में चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। हालांकि सीपीईसी पर कोई प्रगति नहीं हुई है और न ही निकट भविष्य में कोई प्रगति होने की उम्मीद है। हमें ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे दोनों देश पड़ोसी धर्म निभाने के लिए भारत के आगे गिड़गिड़ाएं।

- वेद प्रकाश, गुरुग्राम

अर्थव्यवस्था की रफ्तार

कहा जा रहा है कि चार हजार अरब डालर की जीडीपी के साथ भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने यह बड़ी उपलब्धि जापान को पीछे छोड़ कर हासिल की है। अब भारत से आगे अमेरिका, चीन और जर्मनी जैसी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश रह गए हैं। भारत जैसे विकासशील देश जिस पर हमेशा पिछड़ेपन का आरोप लगता रहा है, यह उपलब्धि सामान्य बात नहीं है। यह सरकार की दूरदर्शी नीति का परिचायक है। तमाम चुनौतियों के बीच दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले हमारे देश की आर्थिकी तेजी से विकसित हुई है, तो निस्संदेह आम जनता सरकार और नीति निर्माताओं पर गर्व कर सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए यह गति आगे भी बरकरार रहेगी। भारत निकट भविष्य में जर्मनी को पीछे छोड़ कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बने, ऐसा हर कोई भारतीय चाहेगा।

- मिथिलेश कुमार, भागलपुर

पड़ोस के जोखिम

बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के भारत विरोधी रुख के कारण पाकिस्तान, अमेरिका और चीन सभी अपने-अपने तरीके से उसे अपने पाले में खींचना चाहते हैं। खासतौर पर पाकिस्तान की नजर अब बांग्लादेश पर है, जहां से वह हमारे देश को अस्थिर करने के लिए अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे सकता है। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के इस एहसान को शायद सूद सहित लौटाएं। इसके लिए वे बांग्लादेश को आतंकियों का नया गढ़ बनाने में उसकी मदद करें, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। पाकिस्तान में आतंकियों के लगभग सभी प्रमुख अड्डे भारत ने नष्ट कर दिए हैं। भारत बार-बार चेता रहा है कि पाकिस्तान फिर नए सिरे से आतंकियों का पनाहगाह बनेगा, तो उसकी खैर नहीं। प्रधानमंत्री ने भी पाकिस्तानी नागरिकों का आह्वान किया है कि वे आतंकियों के विरुद्ध आवाज उठाएं।

- युगल किशोर राही, छपरा

हिन्दुस्तान 1936

टैरिफ गैर-कानूनी

अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने दुनिया में टैरिफ वार या शुल्क संग्राम छेड़ रखा है, पर वह अपनी अदालतों में ही यह संग्राम हारती दिख रही है। वहां एक संघीय अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने टैरिफ लगाने के फैसले को गैर-कानूनी, लापरवाह और विनाशकारी करार दिया है। अदालत ने कहा है कि टैरिफ लगाने का अधिकार केवल कांग्रेस को है और ट्रंप आपातकालीन स्थिति के नाम पर मनमाने ढंग से टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। ट्रंप ने अपने कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया है। खुद अमेरिका में कई जगह टैरिफ के खिलाफ माहौल है। वहां आर्थिक मंदी के खतरे मंडरा रहे हैं। ऐसे में, अदालत के फैसले से वहां भी लोग राहत महसूस करेंगे। हालांकि, अदालत के फैसले के बाद भी ट्रंप झुकने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि यह ईश्वर का अभियान है और जो होने वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अफसोस, कोर्ट के फैसले और उस पर ट्रंप के तल्ख रुख से स्पष्ट है कि अमेरिका में आंतरिक स्तर पर भी शुल्क संग्राम तेज हो जाएगा।

यह बहुत हास्यास्पद है कि कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ संबंधी अपने फैसले का बचाव करते हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष-विराम का हवाला दिया है। ट्रंप प्रशासन का यह मानना है कि टैरिफ की वजह से ही दोनों देश विराम के लिए सहमत हुए। अदालत ने इस दलील को उचित ही नकार दिया। और तो और, अदालत में ट्रंप के पैरोकारों ने यहां तक दावा कर दिया कि यह युद्ध विराम केवल राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ही हासिल किया गया। उन्होंने यह तक चेतावनी दे डाली कि इस मामले में राष्ट्रपति की शक्ति को बाधित करने वाला कोई प्रतिकूल निर्णय भारत व पाकिस्तान को राष्ट्रपति ट्रंप की पेशकश की बैथता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व लाखों लोगों के जीवन को खतरा हो सकता है। अमेरिकी प्रशासन की यह निहायत कमजोर दलील है कि टैरिफ वास्तव में अमेरिकी विदेश नीति का उपकरण है। यह साफ है कि ट्रंप प्रशासन के पास अपनी नई टैरिफ नीति का बचाव करने के लिए अकाट्य आधार नहीं हैं। ऐसे में, यह समझने में कोई हर्ज नहीं कि ट्रंप द्वारा थोपे गए टैरिफ मनमानी हैं। अमेरिकी अदालत ने तो फैसला सुना दिया, पर सवाल यह है कि क्या ट्रंप प्रशासन पारंपरिक अमेरिकी उदारता की राह पर लौटेगा?

अमेरिका के सजग लोग, जागरूक संस्थाएं और अदालतें भी सचेत हैं कि उनका देश अपनी स्थापित परंपराओं से हटकर मनमानी की राह पर न बढ़े।

वैसे, यह कोई पहली बार नहीं है, जब ट्रंप के फैसले को वहां की अदालत ने नकारा है। वीजा संबंधी मामले के साथ ही विदेशियों को जबरन स्वदेश भेजने की उनकी नीति पर भी अमेरिकी अदालतों ने अपनी प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। वहां के सजग लोग और अदालतें सचेत हैं कि अमेरिका अपनी स्थापित परंपराओं से हटकर मनमानी की राह पर न बढ़े। ट्रंप के साथ समस्या यह भी है कि वह अपने किसी फैसले पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पा रहे हैं। कभी चीन के घोर विरोधी बन जाते हैं, तो कभी उससे समझौता करते दिखते हैं। कभी भारत को मित्र बताते हैं और एप्पल जैसी कंपनी को यह कहते हैं कि वह भारत में निर्माण न करे। यह भी उनकी अस्थिर मानसिकता का प्रमाण है कि दुनिया के सबसे अमीर उद्यमी एलन मस्क भी उनकी टीम से अलग हो गए हैं। मतलब, ट्रंप को पहले अपने विचारों को स्थिर करना चाहिए, उसके बाद ही उनकी नीतियां मजबूत होंगी, जिन पर किसी अदालत को आपत्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 30 मई, 1950

बात कम काम ज्यादा

भारत सरकार के उद्योग और रसद मंत्री का पद श्री हरेकृष्ण मेहताब ने संभाला है। इस पद का दायित्व संभालने के बाद अपने पहले सार्वजनिक भाषण में उन्होंने अपने मौलिक व्यक्तित्व का परिचय दिया है। वह अखिल भारतीय निर्माता संघ के दिल्ली प्रान्तीय बोर्ड के वार्षिक बैठक में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें सार्वजनिक भाषण देने का शौक नहीं है और वह इसके बाद कोई भाषण देने का इरादा नहीं रखते। उन्होंने अपना उड़ीसा का उदाहरण भी पेश किया। उन्होंने कहा कि सन् 1946 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद-ग्रहण किया तो यह घोषणा की कि वह एक साल तक न तो सार्वजनिक सभाओं में भाग लेंगे और न उनमें कोई भाषण ही देंगे। उन्होंने इस प्रतिज्ञा को अक्षरशः निभाया। जनता मंत्रियों के भाषण सुनते-सुनते उकता चुकी है। बहुतों को आश्चर्य होता है कि जब अनेक मंत्रियों को सार्वजनिक समारोहों में भाग लेने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो वे अपने विभागों का काम देखने का अवकाश कैसे निकाल पाते होंगे। मंत्रियों के भाषणों से त्रस्त जनता को श्री मेहताब की घोषणा से संतोष होगा कि वह बात कम और काम ज्यादा करेंगे।

श्री मेहताब काम के लिए नया वातावरण पैदा करना चाहते हैं। आज वातावरण यह है कि हम आपसी आलोचना-प्रत्यालोचना में अधिक समय और शक्ति खर्च करते हैं और काम की ओर उतना ध्यान नहीं देते। उद्योगपति कभी मजदूरों को दोष देते हैं और कभी सरकार को। मजदूर उद्योगपतियों को कोसते हैं और सरकार की उपेक्षा वृत्ति की निन्दा करते हैं। सरकारी प्रवक्ता भी इस दोष दर्शन की वृत्ति से अछूते नहीं रहते। श्री मेहताब चाहते हैं कि दोष दर्शन की यह प्रवृत्ति बन्द होनी चाहिए। उन्होंने ठीक ही कहा कि यदि एक-दूसरे को दोष देते रहेंगे, तो हम कुछ भी सफलता हासिल नहीं कर सकेंगे और भावी इतिहासकार हमको कोसे बिना नहीं रहेगा। मजदूरों को अपने हितों की चिन्ता रहती है और उद्योगपतियों को अपने हितों की और सरकार को दोनों में सौहार्द कायम रखने की कोशिश करनी पड़ती है, ताकि उनके आपसी झगड़े के कारण उत्पादन में बाधा न पड़े और सर्व-साधारण की परेशानियों में वृद्धि न हो। श्री मेहताब ने उद्योगपतियों और मजदूरों से केवल अपने वर्गगत हितों की चिन्ता करने के बजाय सर्वसाधारण के हितों को लक्ष्य में रखने का अनुरोध किया।

शिक्षा में साकार हों सुधार के सब सपने

अनुराग बेहर | सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन

कस्तूरीरंगन हों या जे पी नायक, दोनों दिग्गजों की शिक्षा संबंधी सिफारिशों को लागू करना चाहिए। हमें सुविधाजनक सुधारों से आगे बढ़कर चुनौतीपूर्ण सुधारों से गुजरना होगा।

भारत को बनाने में यूं तो अनगिनत लोगों ने योगदान दिया है, मगर कृष्णस्वामी कस्तूरीरंगन का नाम पहली कतार में हमेशा शामिल रहेगा। इसी अप्रैल में 25 तारीख को वह इस दुनिया से विदा हो गए। अपने छोटे से छोटे योगदान का श्रेय भी वह अपनी टीम, गुरुओं, दोस्तों व परिस्थितियों को देना पसंद करते थे। मैं सोच रहा था, उन्हें कैसे श्रद्धांजलि दी जाए?

मुझे एक समाधान मिल गया। मैं एक किताब के बारे में लिख रहा हूं, जो मैंने अक्तूबर 2017 में उन्हें दी थी, जब हम सबने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी 2020) पर काम करना शुरू किया था। कस्तूरीरंगन ने इस समिति की अध्यक्षता की थी। आइए, आपको 60 साल पीछे लिए चलता हूं।

सन् 1966 में कोठारी आयोग की रिपोर्ट ने देश की शिक्षा-प्रणाली में बदलाव का पहला व्यापक खाका खींचा था। साल 1968 में इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में अपनाया गया। आयोग के सदस्य सचिव जे पी नाइक इसके मुख्य वास्तुकार थे। 1979 में आई उनकी किताब *एजुकेशन कमीशन ऐंड आफ्टर* शिक्षा नीति के शुरुआती एक दशक के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करती है। यह उस दशक के ढांचागत सुधार के असाधारण यत्न और इसे बेपटरी करने वाली स्याह हकीकत, दोनों को उजागर करती है।

आयोग की सोच शिक्षा को एक बड़ी लोकतांत्रिक ताकत के रूप में फिर से परिभाषित करने की थी। उसने कॉमन स्कूल सिस्टम का प्रस्ताव दिया था, ताकि अभिजात वर्ग के निजी संस्थानों और कम संसाधन वाले सरकारी स्कूलों के बीच की गहरी खाई पाटी जा सके। आयोग ने माना कि शैक्षिक समानता लाने के लिए शिक्षा तक पहुंच ही काफी नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक प्रयास करने होंगे। इसके लिए सामाजिक मेलजोल की जरूरत थी, जो तभी होता है, जब सभी पृष्ठभूमि के बच्चे नजदीक के गुणवत्तापूर्ण स्कूलों में एक साथ पढ़ते हैं। मगर इस नजरिये को भारत की गहरी, खंडों में बंटी सामाजिक-व्यवस्था से टकराना पड़ा। राज्य सरकारों में शैक्षिक अलगाव को बनाए रखने वाले मजबूत मतदाता वर्गों से टकराने का राजनीतिक साहस नहीं था। इनमें समाजवादी प्रतिबद्धता का दावा करने वाली हुकूमतें भी शामिल थीं। नतीजतन, एक ऐसे तंत्र का निर्माण हुआ, जिसने समानता के आडंबर को जिया, असलियत में विषमता ओं को ही मजबूत किया।

आयोग के प्रस्तावों को महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले लेने की अनिच्छा ने कमजोर किया। अगर हम वैश्विक मानदंडों और भारत के विकास की जरूरतों का गहराई से अध्ययन करें, तो सकल घरेलू उत्पाद का छह फीसदी हिस्सा शिक्षा को आवंटित करने का प्रस्ताव एक कार्रवाई-योग्य सिफारिश थी। मगर इस लक्ष्य तक उस पहले दशक में भी नहीं पहुंचा गया, बल्कि 1970 के दशक की शुरुआत में खर्च वृद्धिफल 2.8 फीसदी के आसपास किया गया। नाइक बताते हैं कि इसने एक के बाद दूसरी विफलताओं को जन्म दिया- तदर्थ शिक्षकों का वेतन बहुत कम था, प्रशिक्षण के लिए संसाधनों की कमी थी और बुनियादी ढांचे का विकास ज्रासद रूप से पिछड़ गया। व्यावसायिक शिक्षा की भी उपेक्षा हुई, जबकि इसे स्कूली शिक्षा और रोजगार के बीच सेतु के रूप में देखा गया था। 1970 के दशक के मध्य तक देश के माध्यमिक स्कूलों में दाखिले की दर पांच प्रतिशत से कम हो गई, जबकि लक्ष्य 50 फीसदी रखा गया था।

इसी तरह, आयोग की सिफारिशों की एक और बुनियाद- शैक्षणिक सशक्तीकरण भी निराशाजनक स्थिति में पहुंच गई। बेशक, शिक्षकों के नए प्रशिक्षण संस्थान उभरे, लेकिन नियमों और असंगत मानकों के कारण उनका प्रभाव कम हो गया। साल 1973 में एक नियामनी संस्था के रूप में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन जरूर किया गया, लेकिन उसकी सिफारिशों की राज्य सरकारों ने लगातार अनेदेखी की और जल्द ही यह निष्क्रिय हो गई। पेशेवर तरीके से जो पुनर्जागरण होना चाहिए था, वह एक और कागजी फाइल बनकर रह गया; शिक्षकों की स्वायत्तता और रचनात्मकता सख्त प्रशासनिक मानसिकता का शिकार बन गई।

नाइक ने ऐसी कई चूकों की जानकारी दी है, जिनके कारण शिक्षा नीति का क्रियान्वयन नहीं हो सका। पहली वजह, हमारे पास जवाबदेही तय करने वाले तंत्र की कमी थी। आयोग की सिफारिशें अनिवार्य होने के बजाय सलाह भर रहीं, जिसके कारण सरकारों ने चुनौतीपूर्ण सुधारों की अनदेखी करते हुए उन्हीं तत्वों को अपनाया, जो उनके लिए सुविधाजनक थे।

दूसरी, केंद्र की नीयत और राज्यों के क्रियान्वयन के बीच अंतर्निहित तनाव के समाधान के लिए बहुत कम प्रयास किए गए। हमें नीति की मूल भावना को बरकरार रखते हुए उसमें स्थानीय संदर्भों को जोड़ने की जरूरत थी। आयोग ने इसीलिए शैक्षिक मामलों में पर्याप्त स्थानीय स्वायत्तता की वकालत की थी। मगर व्यवहार में यह हरेक स्तर पर केंद्र की नौकरशाही में फंस गई।

नाइक के मुताबिक, शायद सबसे अहम वजह यह थी कि इन सुधारों की मांग करने वाला कोई टिकाऊ जनदबाव न बन सका। भूमि सुधार या भाषायी आंदोलनों के विपरीत, जिनकी आम लोगों के बीच जगह बनी, शिक्षा सुधार काफी हद तक कुलीन वर्ग की चिंता बने रहे। नतीजा यह हुआ कि बाद की सरकारों ने शिक्षा को प्राथमिकता के मामले में दूसरे पायदान पर रखा, जिसके कारण इसको बजटीय कटौती से जूझना पड़ा। चूंकि शिक्षा से आम लोगों के हित सधते हैं, इसलिए आयोग की सोच इसे लेकर व्यापक सामाजिक सहमति बनाने की थी, लेकिन यह सोच कभी साकार न हो सकी। यदि आप भारत में रुचि रखते हैं और निवेश करना चाहते हैं, (केवल भारत की शिक्षा में नहीं) तो नाइक की यह किताब जरूर पढ़ी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जब हमारा काम पूरा हो गया, तो एक दिन डॉ कस्तूरीरंगन ने मुझे बुलाया और कहा, 'तुम 2030 में एजुकेशन कमीशन ऐंड आफ्टर लिखोगे।' यह कोई सवाल नहीं था। उन्होंने शायद ही कभी सीधे तौर पर कुछ पूछा हो, इसलिए मैंने कहा, 'हां सर, जरूर लिखूंगा'। अब यही उनके लिए श्रद्धांजलि हो सकती है, जिसे वह भी ठुकरा नहीं पाएंगे। मगर इसके लिए हमें जे पी नाइक के अनुभव से सीखना होगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करना होगा। अगर इसे पूरी तरह लागू न भी कर सकें, तो एक जायज हद तक जरूर लागू किया जाना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

करोड़ों भारतीयों की मेहनत से चौथे स्थान पर पहुंचा भारत

नवनीत सहगल | चेयरमैन, प्रसार भारती

भारत ने आर्थिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। खास बात यह है कि आर्थिक विकास का यह मॉडल केवल महानगरों या अमीर तबकों तक सीमित नहीं रहा। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के सिद्धांत पर चलते हुए मोदी सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। यही वजह है कि दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 4.186 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत ने जापान जैसे विकसित देश को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह उपलब्धि आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों के संघर्ष, परिश्रम और सपनों की साकार तस्वीर है।

एक दशक पहले भारत कई आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा था, पर आज दुनिया की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। जहां दुनिया के कई देश आज कई मोर्चों पर आशंकाओं से जूझ रहे हैं, वहीं भारत स्थिर नेतृत्व में कीर्तिमान बना रहा है। यह सफर आसान कतई नहीं था। नीतिगत फैसलों ने विकास को रफ्तार दी है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उस समय भारत दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। कई नीतिगत समस्याएं देश की गति को रोक रही थीं। अगले दस वर्ष में भारत ने आर्थिक सुधारों और नीतिगत फैसलों के जरिये अपने विकास की रफ्तार तेज कर दी। नतीजा यह कि साल 2019 में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर पांचवां स्थान प्राप्त किया और अब वह जापान को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर पहुंच गया।

भारत साल 2027 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। दुनिया भारत को अवसर और नवाचार के केंद्र के रूप में देख रही है।

भारत की आर्थिक प्रगति के मूल में सुधारों की सशक्त नींव रही है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने देश को एकीकृत बाजार में बदला, कर प्रणाली को सरल बनाया और राजस्व बढ़ाया। बैंकिंग क्षेत्र को भी मजबूती मिली है और ऋण व्यवस्था में अनुशासन आया है। मेक इन इंडिया अभियान ने विनिर्माण पुनर्जीवित किया और निवेशकों का भरोसा बहाल किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 2014 में 142 से 2020 में 63 पर आ गई। इन बदलावों ने भारत के शासनतंत्र की मानसिकता को भी बदला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया मुहिम ने गांव से लेकर शहर तक, देश के कोने-कोने को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं से जोड़ा है। इससे न सिर्फ सरकारी सेवाएं सुलभ हुईं, बल्कि डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप और तकनीकी नवाचार को जबरदस्त बढ़ावा मिला है। यूपीआई जैसी प्रणालियों ने डिजिटल भुगतान को इतना आसान बना दिया है कि 2024 तक हर महीने 14 अरब रुपये से अधिक के लेन-देन होने लगे। जनधन योजना, आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने करोड़ों लोगों को वित्तीय प्रणाली से जोड़ा व भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है।

बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए। भारतमाला, सागरमाला और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स के तहत सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और शहरी विकास पर अभूतपूर्व निवेश हुआ है। 2014 से 2024 तक भारत में 80,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ।

भारत ने ग्लोबल बिजनेस में भी अपनी पकड़ मजबूत की है। 2023-24 में भारत का कुल निर्यात 824.9 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह आईटी सेवाओं, फार्मा, रत्न-आभूषण, वस्त्र व इंजीनियरिंग उत्पादों में अभूतपूर्व वृद्धि का परिणाम है। दवाओं के सस्ते उत्पादन ने भारत को दुनिया की फार्मेसी बना दिया। कृषि उत्पादों के निर्यात और वैश्विक मांग में निरंतर इजाफा हुआ, जिससे भारत की छवि भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरी।

आज पूरी दुनिया भारत को स्थिरता, अवसर और नवाचार के केंद्र के रूप में देख रही है। भारत 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह यात्रा भारत के करोड़ों नागरिकों की सामूहिक आकांक्षाओं की जीत है, चाहे वह बेंगलुरु के स्टार्टअप हों, सूरत के बुनकर, पंजाब के किसान या हैदराबाद के इंजीनियर। हर एक भारतीय इस सफलता का सहभागी है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

संत और योद्धा, दोनों चाहिए

मनुष्य के बारे में जितना कुछ लोग समझते हैं, उससे कहीं कम पार्थिव सांचे में वह ढला हुआ है। उसमें एक दैवी तत्व होता है, व्यवहारी राजनीतिज्ञ जिसकी उपेक्षा कर जाता है। व्यवहारी राजनीतिज्ञ वर्तमान स्थितियों पर दृष्टि डालता है और कल्पना कर लेता है कि उसने सभी बातों पर विचार कर लिया है। वस्तुतः उसने सतह का और तत्कालीन परिवेश का अध्ययन किया है, किंतु भौतिक दृष्टि से परे जो स्थित है, उसे वह चूक गया है। वह उस तत्व को, जो योजनाकार की सारी गणनाओं को झुठला देता है और कूटनीतिज्ञ की बुद्धिमत्ता को विक्षुब्ध कर देता है, अपने लेखा से बाहर छोड़ गया है।

राष्ट्रवादी कभी इस सत्य को ओझल नहीं होने देता कि कानून आदमी के लिए बना है, न कि आदमी कानून के लिए। उसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय जीवन के विकास को सुरक्षित व पोषित करके शक्तिसंपन्न और स्वस्थ बनाना है। ऐसा कानून, जो इस उद्देश्य में सहायक नहीं होता अथवा जो इस उद्देश्य का विरोध या खंडन करता है, वह चाहे जितनी सख्ती से शांति-व्यवस्था और सुरक्षा कायम करे, पर आदर और अनुपालन का अधिकार खो बैठता है।

राष्ट्रवाद कानून को अंधश्रद्धा का आधार मानने से इनकार करता है। वह हिंसात्मक और सख्त तरीकों को इसलिए प्राथमिकता नहीं देता कि वे हिंसात्मक और सख्त हैं, पर वह नरम व शांतिपूर्ण तरीकों से भी केवल इसलिए बंधा नहीं रहता कि वे नरम और शांतिपूर्ण हैं। किसी भी तरीके से वह यह प्रश्न करता है कि वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम है कि नहीं; अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत एक महान जन-समुदाय की प्रतिष्ठा के योग्य वह है या नहीं; क्या वह राष्ट्रीय शक्ति और क्रियाशीलता की शिक्षा देता है? एक बार ये बातें तय हो जाएं, तो फिर वह आगे और कुछ नहीं पूछता।

मनुष्यों का एक वर्ग आक्रामकता से ऐसे सिकुड़ता है, मानो वह कोई पाप हो। ऐसे लोगों की चित्तवृत्ति संघर्ष का आनंद लेने से उन्हें रोकती है। उसकी ओर ऐसे देखते हैं, जैसे वह पापमय हो। उनकी पुकार है, 'घृणा का उपचार प्रेम से करो, अन्याय को न्याय से भगाओ, पाप को सदाचार से काटो।' प्रेम की चर्चा करना सरल है, प्रेम करना उतना सरल नहीं।...जो युद्ध को पाप समझकर और आक्रामकता को नैतिकता का पतन मानकर उससे सिकुड़ते हैं, उनके लिए *गीता* सबसे उत्तम उत्तर है।

जो युद्ध से भागते हैं, उनके लिए गीता सबसे उत्तम उत्तर है। एक योद्धा की तलवार न्याय और सदाचार की पूर्ति के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी एक संत की धार्मिकता।

वह दर्शन, जो सभी कर्मों पर एक ही मशीनी नियम लागू करता है अथवा एक शब्द लेता है और उसमें सारे मानव जीवन को बैठाने का प्रयास करता है, निरर्थक है। एक योद्धा की तलवार न्याय और सदाचार की पूर्ति के लिए उतनी ही आवश्यक है, जितनी एक संत की धार्मिकता। शिवाजी के बिना रामदास पूर्ण नहीं हैं।

श्री अरविंद

राजनाथ सिंह | केंद्रीय रक्षा मंत्री

आज के समय में किसी राष्ट्र की शक्ति का मूल्यांकन उसके जीडीपी, विदेशी निवेश व निर्यात के आंकड़ों से ही नहीं होता, दुनिया अब यह भी देखने लगी है कि कोई देश अपने नागरिकों और वैश्विक समुदाय में कितना भरोसा जगा सकता है।

विदेश तक पहुंच रही हिंदी पत्रकारिता

आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। साल 1826 में आज के ही दिन, यानी 30 मई को *उदन्त मार्तण्ड* नामक पहला हिंदी समाचारपत्र निकाला गया था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता (अब कोलकाता) से एक साप्ताहिक समाचारपत्र के तौर पर शुरू किया था। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हिंदी पत्रकारिता इस स्तंभ की रीढ़ है। यह केवल सूचना देने का साधन नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और सत्य को उजागर करने का जिम्मा भी है। आज जब सूचना का प्रवाह इतना तीव्र है, तब पत्रकारिता की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। गलत सूचनाओं को रोकना, तथ्यों की परखना और जनता तक सही जानकारी पहुंचाना पत्रकारिता का धर्म है। *उदन्त मार्तण्ड* का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है- पत्रकारिता का उद्देश्य केवल व्यापार नहीं, बल्कि समाज का उत्थान और सशक्तीकरण है।

हिंदी पत्रकारिता दिवस हमें उन ऐतिहासिक क्षणों की याद दिलाता है, जब एक व्यक्ति ने असंभव को संभव करने का साहस दिखाया। पंडित जुगल किशोर शुक्ल का योगदान एक समाचारपत्र तक सीमित नहीं था; यह एक भाषा, एक संस्कृति और एक समाज को आवाज देने का महान प्रयास था। उनकी यह मशाल आज भी जल रही है- हर उस पत्रकार के लेखन में, हर उस संपादकीय में, जो सत्य और न्याय के लिए लिखा जाता है। इस दिन हमें यह संकल्प लेना होगा कि हम इस मशाल को कभी बुझने नहीं देंगे। हमें पत्रकारिता को उसकी मूल भावना- निष्पक्षता, साहस और सामाजिक उत्तरदायित्व- को जीवित रखना होगा।

हिंदी पत्रकारिता की बढ़ती ताकत ही है कि आज यह केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह वैश्विक मंचों पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। हिंदीभाषी प्रवासी समुदायों के बीच, डिजिटल मंचों पर और अंतरराष्ट्रीय चर्चाओं में हिंदी पत्रकारिता की धमक सुनाई देती है। मगर सच यह भी है कि इसकी सार्थकता तभी है, जब यह जनता के हितों को सर्वोपरि रखे, सत्ता से सवाल पूछे और समाज के कमजोर वर्गों की आवाज बने। हिंदी पत्रकारिता दिवस साहस, सच्चाई और संकल्प का एक उत्सव है, लेकिन यह एक जिम्मेदारी भी है, जो हमें याद दिलाता है कि शब्दों में इतिहास बदलने की ताकत है। इसने पूर्व में ऐसा किया भी है। आज हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं, सपनों और संघर्षों की आवाज है। इस दिन हम उन पहले पत्रकारों, संपादक को नमन करें, जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी।

आरके जैन, शिक्षाविद

अनुलोम-विलोम
हिंदी पत्रकारिता दिवस

आज इसके सामने नई चुनौतियां पैदा हुईं

कलम के सिपाही, लोकतंत्र के रक्षक और न जाने क्या-क्या... पत्रकारों पर शायद इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साल 1826 से अब तक काफी समय गुजर चुका है। पत्रकारिता ने अग्नि परीक्षाएं दीं, अपना दायित्व निभाया और कभी-कभी चूक भी गई। पैर आते रहे, जाते रहे, पर पत्रकार वहीं अविचल खड़ा रहा। आजादी की लड़ाई से लेकर अब तक, न जाने कितनी कसौटियों पर उसे कसा गया। मगर आज का दौर सबसे अलग है। शायद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी। सीधा और संगीन आरोप है कि कलम अब निष्पक्ष नहीं रही। मगर सबसे खास बात यह है कि युवा पीढ़ी के मेधावी लोग, जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते थे, उनका मोहभंग हो चुका है। इसी का नतीजा है कि दोयम दर्जे के वे युवा, जिनके पास न भाषा है, न विचार है और न ज्ञान, वे इस क्षेत्र में आने लगे हैं। पत्रकारिता एक बौद्धिक पेशा है। बिन बुद्धि पत्रकारिता जैसे बिना स्याही की कलम। अब क्योंकि विज्ञान और तकनीक का चरम है, इसलिए सोशल मीडिया जैसे माध्यमों पर बुद्धि भ्रष्ट लोग अर्थ का अनर्थ कर दे रहे हैं। इसका खामियाजा गंभीर पत्रकारिता करने वालों को भुगतनी पड़ती है। हिंदी पत्रकारिता को अंग्रेजी से भी लड़ना पड़ता है। कुछ हिंदी अखबार तो अब अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग शुरू कर चुके हैं। आज खबरों के चौथड़े उड़ रहे हैं, साथ में पत्रकारिता भी बुरे हाल में है, शायद अपनी उम्र के सबसे बुरे दौर में। फिर भी, उम्मीद है। कुछ कोंपलें अभी भी उग रही हैं, कुछ बूढ़ी हड्डियां अभी भी जोर मारती दिखती हैं। आइए, इसी उम्मीद के साथ यह पत्रकारिता दिवस मनाते हैं।

अनिल दीक्षित, टिप्पणीकार

जो अगणित लघु दीप हमारे/ तूफानों में एक किनारे/ जल-जलाकर बुझ गए किसी दिन/ मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल/ कलम, आज उनकी जय बोल... राभधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर याद आ रही हैं। आज पत्रकारिता के सामने हिंदी से दूर भागती हिंदी पत्रकारिता की चुनौती है। शब्दकोश समृद्धि के नाम पर हिंदी के मूल शब्दों से सतत दूरी बनाई जा रही है। पत्रकारिता महज खबरों और जानकारियों तक सीमित नहीं की जा सकती। फिर, हिंदी पत्रकारिता तो भाषा ज्ञान का माध्यम भी बनती रही है। बहुत दिन कहां हुए हैं, जब विद्यालय का मुंह तक न देखने वाले भी गांव के साप्ताहिक बाजार में अखबार पढ़ते दिख जाते थे। उन्हें पढ़ना सिखाने का काम तो अखबार ही करते थे। मगर अब ऐसा कहां? समाज की भाषागत समृद्धि बढ़ाने की जिम्मेदारी हिंदी पत्रकारिता को निभानी चाहिए। इसे यह भूल रही है।

संजीव मिश्र, टिप्पणीकार

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 30 मई • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

इच्छाएं ही सब दुखों का मूल कारण हैं।
-भगवान बुद्ध

पेड़ कटाई पर 'सुप्रीम' सख्ती

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को राजधानी के रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटने पर अवमानना का दोषी ठहराया। आदेशों का जानबूझकर पालन न करने को गलत प्रशासनिक निर्णय ठहराते हुए, व्यापक वनरोपण का आदेश दिया। साथ ही अधिकारियों पर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इससे पहले भी पेड़ों की अवैध कटाई को सुप्रीम कोर्ट ने इंसान की हत्या से भी बदतर कहा। पीठ ने संबंधित प्राधिकरण की अनुमति के बगैर पेड़ों की अवैध कटाई और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कोई दया न दिखाने को कहा। माना जा रहा है कि अदालत द्वारा मानक तय कर दिया गया है, ताकि ऐसे मामलों में जुर्माना लगाया

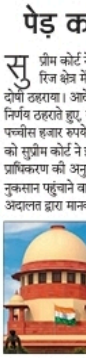

जाए। पीठ ने इतने पेड़ लगाने व हरित क्षेत्र बनाने में सौ साल का वक्त लगने की बात भी की। देश में सरकार की अनुमति के बगैर हरे वृक्षों को काटने पर पाबंदी के बावजूद बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाते हैं। पेड़ काटने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसमें पेड़ का विवरण, उसकी शाखाएं, स्वामित्व का प्रमाण व स्थिति के विषय में विवरण देना होता है। वन क्षेत्र की कमी व तेजी होते शहरीकरण, औद्योगीकरण, वनों के अवैध उपयोग के चलते पेड़ों की कटाई आम समस्या है। वन अधिनियम 1927 की धारा 26 व 379 में मामला दर्ज हो सकता है। 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना का मकसद पर्यावरण संबंधी मामलों को निपटाने के लिहाज से शुरू गया। मगर वह भी अपनी भूमिका निभाने में प्रभावी होता नहीं नजर आ रहा है। हालांकि बढ़ते यातायात को देखते हुए सड़कों को चौड़ा किया जाना भी जरूरी है और विकास के लिए अधिकरण की जाने वाली आवश्यक भूमि की अवहेलना भी नहीं की जा सकती, परंतु नियम/कानून की अवहेलना करने वालों पर सख्ती बेहद जरूरी है। वरना ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में आ चुके पर्यावरण की क्षतिपूर्ति असंभव हो सकती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को वनरोपण से रोका तो नहीं जा सकता मगर कुछ हद तक लगाम जरूर लगाई जा सकती है। पुराने पेड़ों को एक-जगह से दूसरी-जगह स्थानांतरित करने सरीखी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना भी संबंधित विभागों को सीखना चाहिए। क्योंकि हर मामले का निपटान अदालत द्वारा किया जाना भी मुश्किल है। इसलिए तौर-तरीकों में व्यावहारिकता को तरजीह दी जानी उचित होगी।

आखिरी उपाय

सरकार न्यायपालिका के मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में यह साफ दिखाई देता है। उच्चतम न्यायालय की जांच समिति द्वारा वर्मा के आवास से भारी मात्रा में जले नोट मिलने के मामले में दोष लगाने और उनके इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद सरकार आखिरी उपाय के तौर पर उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जस्टिस वर्मा को इस अप्रिय घटना के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजा जा चुका है। वहां वर्मा के पहुंचने से पहले ही बार के सदस्य विरोध में खड़े हो गए थे। अभी उन्हें न्यायिक कार्य से दूर रखा गया है। न्यायमूर्तियों के मामले इतने संवेदनशील होते हैं कि वर्मा पर महाभियोग

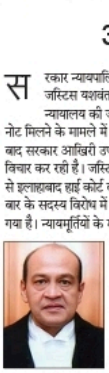

की कार्रवाई की सिफारिश करते समय तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि वर्मा ने खुद को निर्दोष बताया है और अपने आउटहाउस में आग लगने के बाद मिली नकदी से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। महाभियोग की प्रक्रिया आसान नहीं रहने वाली है। इसके लिए को सरकार दलों को विश्वास में लेना होगा क्योंकि राज्य सभा में कम-से-कम 50 सदस्यों को प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने होते हैं और लोक सभा में 100 सदस्यों को इसका समर्थन करना होता है। आज तक तो किसी भी मामले में महाभियोग की प्रक्रिया अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है। कोई न कोई रुकावट आती रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी. रामास्वामी को महाभियोग का सामना करने वाला पहला जज माना जाता है, उनके खिलाफ मई, 1993 में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव लोक सभा में गिर गया था क्योंकि सत्तारूढ़ कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला। 2011 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज सौमित्र सेन ने भी लोक सभा में वोटिंग से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। उसी साल सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनाकरन ने महाभियोग की सुनवाई से पहले ही पद से त्यागपत्र दे दिया था। तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ 2018 में राज्य सभा में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया जिसे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया था।

विमर्श/डॉ. राजेंद्र प्रसाद शर्मा

एमएसपी ठीक, खरीद भी जरूरी

केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा खरीफ की बुवाई से पहले ही करने को किसानों के हित में सकारात्मक पहल के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आगामी खरीफ के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में रामतिल के भावों में सर्वाधिक 820 रु. की बढ़ोतरी करते हुए 9537 रु. प्रति क्विंटल एमएसपी घोषित की गई है। तिल की एमएसपी में 579, सोयाबीन में 436, सूरजमुखी में 441 और मूंगफली की एमएसपी में 480 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। उड़द में 400 तो मूंग की एमएसपी में 86 और अरहर की एमएसपी में 450 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बाजरा, रागी, ज्वार, कपास, धान आदि अन्य खरीफ फसलों की एमएसपी दरों में भी बढ़ोतरी की गई है।

जहां तक एमएसपी दरों की घोषणा की बात है तो सरकार की मंशा पर संदेह नहीं किया जा सकता। सरकार का दावा है कि एमएसपी घोषणा करने से पहले फसल लागत के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। किसान आंदोलनों के दौरान सबसे अहम मुद्दा मुद्दा एमएसपी को लेकर ही रहता आया है। किसान नेताओं का यह भी कहना रहा है कि सरकार एमएसपी दरों की घोषणा के साथ ही एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित करे। बेशक, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की एजेंसियां और सहकारी विपणन संस्थाएं खरीद में प्रमुखता से सहभागी रहती हैं। खरीद की व्यवस्था को भी पारदर्शी और ऑनलाइन कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन से लेकर सीधे खातों में भुगतान तक की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है पर कहीं न कहीं व्यवस्था में झोल अवश्य है। एक समय था तब सरकारी खरीद शुरू होने की घोषणा और लगभग 10-15 प्रतिशत उत्पादन की खरीद होते-होते मंडियों में भाव एमएसपी के आसपास आ जाते थे। परिणाम होता था कि न तो किसानों की नाराजगी रहती थी और न ही अन्य कोई समस्या आती थी। पर आज खरीद व्यवस्था पारदर्शी होने के बावजूद किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। अभी भी तमाम पारदर्शिता के बावजूद विचौलियों को इस व्यवस्था का फायदा उठाते देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों को भी ठोस प्रयास करने होंगे तभी अन्नदाता को उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिल सके। सरकार को खरीद को सीमा में बांधने की बजाय स्थाई हल खोजना होगा ताकि एमएसपी अधिक किसान हितैषी हो सके।

सवाल दर सवाल

पत्रकारिता दिवस

अरविंद कुमार सिंह

30 मई, 1826 को कलकत्ता में अहिन्दीभाषियों के बीच से हिन्दी का पहला अखबार 'उदन्त मार्तण्ड' पं. जुगल किशोर सुकुल के संपादन में साप्ताहिक रूप में निकला तो कोई खास हलचल नहीं हुई। इसके पीछे कोई बड़ी संख्या या पूंजी नहीं थी। पहले अंक की 500 प्रतियां ही छपीं और 79 अंक निकाल कर तंगहाली में 4 दिसम्बर, 1826 को यह अखबार अस्ताचल को चला गया। विपरीत परिस्थितियों में यथासंभव अखबार चला लेकिन इतिहास में यह अखबार और सुकुल जी दोनों अमर हो गए।

आपातकाल के दौरान जब इसके प्रकाशन का 150 साल हो रहे थे, उसी दौरान लखनऊ में विख्यात हिन्दीसेवी ठाकुर प्रसाद सिंह के प्रयासों से हिन्दी पत्रकारों और लेखकों का जमावड़ा हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ कि 30 मई को हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाया जाए। 30 मई, 1977 के बाद से यह दिवस मनाया जाना आरंभ हुआ। आज देश में 350 से ज्यादा न्यूज चैनलों में अधिकतर हिन्दी के हैं। पंजीकृत पत्र-पत्रिकाओं की संख्या 1,44,520 है, जिनमें अधिकतर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के हैं। कोरोना महामारी में अखबारों का प्रसार गिरा, तमाम पत्र-पत्रिकाएं बंद हो गईं। बावजूद हिन्दी मीडिया ताकतवर होती जा रही है।

बीती दो सदी के बीच हिन्दी पत्रकारिता ने लंबा सफर तय किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णु पराड़कर, माधव राव सप्रे, गणेशशंकर विद्यार्थी, मुंशी प्रमेचंद, शिवपूजन सहाय से लेकर इसको शक्ति देने वालों की एक लंबी श्रृंखला है। हिन्दी की तमाम पत्र-पत्रिकाएं भोपाल में सप्रे संग्रहालय में पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर के प्रयासों से संग्रहीत हैं, जो बताती हैं कि विपरीत माहौल में भी हिन्दी कैसे फली-फूली। आज भी हिन्दी पत्रकारिता खास तौर पर प्रिंट की अपनी शक्ति बरकरार है। गांधी जी ने 1945 में हरिजन में लिखा था कि अखबारों में जो कुछ छपता है, उसे लोग ईश्वरीय सत्य मान लेते हैं। इस नाते संपादकों और अन्य पत्रकारों का दायित्व बढ़ जाता है। संचार और सूचना क्रांति के दौर में भी प्रिंट का महत्त्व इस कारण बरकरार है कि सदियों से छपे शब्दों की विश्वसनीयता लोगों के दिलोदिमाग पर मनोवैज्ञानिक रूप से छाई है। शब्दों का सौंदर्य, विचारों का विस्तार, पत्रकारिता की गंभीरता, अभिव्यक्ति की मर्यादा बाकी माध्यमों की तुलना में अखबारों के पन्नों पर कहीं अधिक प्रभावी रूप में दिखती है। खबरों को व्यापकता और सत्यता के लिए वे अगले दिन के अखबार का इंतजार करते हैं। वैसे तो प्रिंट मीडिया का इतिहास भारत में कलकत्ता से 1780 में निकले 'बंगाल गजट' से आरंभ होता

है। वह एशिया का अंग्रेजी का पहला साप्ताहिक अखबार था पर इसके संस्थापक हिक्की दो साल तक इसे चला नहीं सके और अंग्रेजों का कोपभाजन बने। बॉम्बे हेराल्ड 1789 में छपने वाला मुंबई का पहला अखबार था, जिसका नाम बाद में 'बाम्बे टाइम्स' हुआ। बाद में तमाम अखबार छपे। 1821 में 'संवाद कौमुदी' समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने निकाला।

1857 में हमारे पहले स्वाधीनता संग्राम में भी भाषाई अखबार संख्या में कम थे लेकिन बहादुरी से लड़े। उनको दबाने के लिए 13 जून, 1857 को लॉर्ड कैनिंग कुख्यात गैगिंग एक्ट लाए। भारतीय भाषाओं के अखबारों को काबू में लाने के लिए 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बना। कई और कानून बने जिससे अखबारों को सताया गया पर सच लिखना जारी रहा। कई नायकों ने अखबार निकाले और डॉ. अंबेडकर भी उनमें से एक थे। 1943 में रानाडे की 101वीं जयंती पर उन्होंने बेबाकी से कहा था, 'आज पत्रकारिता का मुख्य सिद्धांत है एक नायक चुन कर उसकी पूजा करना। उसकी छत्रछाया में समाचार पत्रों का स्थान सनसनी और विवेक-सम्मत मत का विवेकहीन भावावेश ने ले लिया है...मुझे खुशी है कि कुछ सम्मानजनक अपवाद मौजूद हैं।' आज भी स्थिति वही है। लेकिन सम्मानजनक अपवाद भी मौजूद हैं पर हिन्दी पत्रकारिता पर तमाम सवालों की बौछार हो रही है। हिन्दी पत्रकारिता में आज भी एकमत होकर मानक शब्दों पर सहमति तक नहीं बन सकी है। विश्व के तमाम नगरों और नेताओं के नाम हिन्दी अखबारों में एक जैसे नहीं छपते। हिन्दी में पराड़कर जी ऐसे संपादक रहे हैं, जिन्होंने इसके शब्द संसार को व्यापक बनाया। उन्होंने ही मिस्टर के लिए श्री, प्रेसीडेंट के लिए राष्ट्रपति जैसे शब्द दिए।

महागहिम, मुद्रास्फीति तथा कामचलाऊ सरकार जैसे शब्द उनके ही दिए हैं। सर्वश्री, लोकतंत्र, नौकरशाही, स्वराज्य, सुराज, वातावरण, वायुमंडल, कार्रवाई, अंतरराष्ट्रीय, चालू, अंतरिम जैसे करीब 200 शब्दों में उनका योगदान माना जाता है। आम आदमी की भाषा की पैरोकारी के साथ उन्होंने जो प्रयोग हिन्दी पत्रकारिता में किए वे बंद हो गए पर ऐसा काम सीमित संपादकों ने किया और हाल के सालों में टीवी चैनलों ने अखबारों की भाषा भ्रष्ट करने का काम किया। हिन्दी पत्रकारिता और लेखन बड़े अर्थों में अनुवादजीवी या गूगलजीवी बन गई है। एआई उसमें एक नया आयाम है। मिशन के साथ शुरू हिन्दी पत्रकारिता में खबर और विज्ञापन के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। पेड न्यूज ने भाषाई अखबारों की छवि को आहत किया है। सरकारें पत्रकारों पर जब चाहे शिकंजा इस नाते कसती रहती हैं कि पत्रकारों को नियंत्रित करने के लिए 14 विभिन्न कानूनों का जाल है। हिन्दी भाषी इलाकों में साक्षरता बढ़ने के कारण बड़ा पाठक वर्ग, दर्शक और श्रोता पैदा हुआ है।

हिन्दी इलाका बड़ा बाजार भी है। अंग्रेजी, जिसे अंतरराष्ट्रीय भाषा होने का गौरव है, के मूल शब्द मात्र 10 हजार हैं, लेकिन हिन्दी की शब्द संपदा ढाई लाख से ज्यादा है। तमाम विसंगतियां हैं, फिर भी भरोसेमंद पत्रकारिता हिन्दी में अभी भी हो रही है। हिन्दी पत्रकारिता का सफर करीब 200 सालों का हो गया है। अब सूचना और संचार क्रांति के इस दौर को ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया आयाम देने जा रहा है। इसका सृजनात्मक क्षमता और कल्पनाशीलता पर असर पड़ सकता है। हम मशीन पर निर्भर होते हुए अपनी स्वाभाविक बुद्धि और कौशल न खो दें, इस पर गंभीर चिंतन करने का समय है। तमाम मोरचों पर हिन्दी को काम करने की जरूरत है।

(लेखक में व्यक्त विचार निजी हैं)

मिशन के साथ शुरू हिन्दी पत्रकारिता में खबर और विज्ञापन के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। पेड न्यूज ने भाषाई अखबारों की छवि को आहत किया है। सरकारें पत्रकारों पर जब चाहे शिकंजा इस नाते कसती रहती हैं कि पत्रकारों को नियंत्रित करने के लिए 14 विभिन्न कानूनों का जाल है। हिन्दी पत्रकारिता का सफर करीब 200 सालों का हो गया है।

बस, एक मुट्ठी अंकुरित मूंगफली रखती है दिल और हड्डियों का पूरा ख्याल

- अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन वेबसाइट में प्रकाशित एक शोध लेख के अनुसार मूंगफली और अंकुरित मूंगफली, दोनों ही बेहद फायदेमंद होती हैं।
- अंकुरित मूंगफली में फाइबर के साथ ही पोटैशियम और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है।
- अंकुरित मूंगफली के नियमित सेवन करने से हड्डियां थोड़ी सी मजबूत बनती हैं। इसमें ओमेगा-6 फैटी एसिड होता है, जो मोटापे की समस्या से भी निजात दिलाता है।

(मीडिया इनपुट्स)

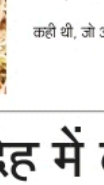

नेहरू, मंडेला और टैगोर में मानवता के प्रति प्रतिबद्धता का समान गुण था। ध्यातव्य है कि देश की आजादी के समय नेहरू ने भारतीयों को 'भारत की सेवा में समर्पित होने का संकल्प लेने को कहा था...और इंसानियत के लिए भी संकल्पबद्ध होने की बात कही थी, जो आज भी महत्त्वपूर्ण संकल्प है।' विश्व इससे सीख ले सकता है।

कौशिक बसु, पत्रकार
@kaushikcbasu

कैब उद्योग | रजनीश कपूर

धत् कर्म से संदेह में कारोबार

भारत का 'कैब' उद्योग, जो कुछ वर्षों पहले तक तकनीकी नवाचार और सुविधा का प्रतीक माना जाता था, आज गंभीर विवादों और वित्तीय अनियमितताओं के कारण चर्चा में है। ल्यूस्मार्ट और ओला जैसी प्रमुख कंपनियों पर लगे धोखाधड़ी और कर चोरी के आरोपों ने न केवल उनके कारोबारी मॉडल पर सवाल उठाए हैं, बल्कि लाखों ग्राहकों के बीच अविश्वास और निराशा की भावना भी पैदा की है। ऐसी कंपनियां अब अपने ग्राहकों को ठगा हुआ महसूस करा रही हैं।

ल्यूस्मार्ट, जो 2019 में इलेक्ट्रिक वाहन-आधारित कैब सेवा के रूप में शुरू हुई थी, ने अपनी पर्यावरण-अनुकूल नीतियों और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के कारण तेजी से लोकप्रियता हासिल की थी। दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों में इसकी सेवाएं शुरू होने के बाद कंपनी ने कई बड़े निवेशकों से भारी फंडिंग प्राप्त की। हालांकि, अप्रैल, 2025 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किए गए खुलासे ने ल्यूस्मार्ट की मूल कंपनी जेनसोल इंजीनियरिंग की वित्तीय प्रथाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। सेबी ने पाया कि जेनसोल के प्रमोटरों, अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी ने कंपनी को दिए गए 977.75 करोड़ रुपये के ऋण का दुरुपयोग किया। यह राशि, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और बेड़े के विस्तार के लिए थी, कथित तौर पर आलीशान फ्लैट, गोल्फ किट, और अन्य व्यक्तिगत खर्चों पर खर्च की गई। सेबी की जांच के अनुसार, कंपनी ने केवल 4,704 वाहन खरीदे, जबकि 6,400 वाहनों का वादा किया था। परिणामस्वरूप 262.13 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई। इस घोटाले का सबसे बड़ा झटका ल्यूस्मार्ट की अचानक सेवा बंदी के रूप में सामने आया जिसने अप्रैल, 2025 में इसके संचालन को ठप कर दिया। इस बंदी का असर हजारों ड्राइवरों, लाखों ग्राहकों व इनसे जुड़े कई लोगों पर पड़ा। ड्राइवरों को बिना पूर्व सूचना बेरोजगार छोड़ दिया गया जबकि ग्राहकों के वॉलेट में जमा राशि, जो लाखों रुपये में थी, फंस गई। दिल्ली के एक नियमित ग्राहक के अनुसार उन्होंने ल्यूस्मार्ट की सुविधा और पर्यावरण-अनुकूल सेवाओं की हमेशा प्रशंसा की थी, लेकिन अब उनके वॉलेट में 4,500 रुपये फंसे हुए हैं, और उन्हें रिफंड की कोई जानकारी नहीं मिल रही है।

ओला कैब्स, जो भारत के कैब बाजार में अग्रणी रही है, भी हाल के वर्षों में कई विवादों में उलझी हुई है। हाल में कंपनी पर कर चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। आयकर विभाग की एक जांच में पता चला कि ओला ने अपने ड्राइवरों के भुगतान और किराए की राशि पर टैक्स की गणना में अनियमितताएं बरतीं। यह भी आरोप है कि ओला ने अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से फंड को गलत तरीके से स्थानांतरित किया ताकि कर देनदारियों को कम किया जा सके। गौरतलब है कि ओला कैब्स की मूल कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. ने भारत में एक अग्रणी इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी 'ओला इलेक्ट्रिक' शुरू की। परंतु आज यह कंपनी अपने ग्राहकों व आपूर्तिकर्ताओं के साथ वित्तीय अनियमितताओं के कारण चर्चा में है। ओला ने अपने सप्लायरों और लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स को समय पर भुगतान करने में देरी की। सो, कई प्रमुख सप्लायरों ने कंपनी के साथ संबंध तोड़ लिए। एक सप्लायर ने तो ओला के खिलाफ दिवालियापन की याचिका भी दायर की जिसे बाद में कंपनी ने सुलझाने का दावा किया। ओला की लागत कम करने की रणनीति, जैसे वाहन पंजीकरण एजेंसियों के साथ अनुबंधों की पुनः बातचीत, ने बिक्री और पंजीकरण के आंकड़ों में भारी विसंगति पैदा की। फरवरी, 2025 में ओला ने 25,000 स्कूटर बेचने का दावा किया लेकिन वाहन पोर्टल पर केवल 8,390 पंजीकृत हुए। वित्तीय और परिचालन चुनौतियों के चलते ओला को बाजार हिस्सेदारी सितम्बर, 2024 में 27% तक गिर गई।

ल्यूस्मार्ट और ओला से जुड़े विवादों ने ऐसे उद्योगों में ग्राहकों का विश्वास कमजोर किया है। इन घोटालों से भारत में ऐसे उद्योगों के लिए सख्त नियामक ढांचे की आवश्यकता को उजागर किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ग्राहकों तथा इनसे जुड़े अन्य लोगों के हितों की रक्षा के लिए कड़े नियम लागू करने चाहिए। आयकर विभाग, सेबी जैसे नियामक निकायों को ऐसी कंपनियों की निगरानी बढ़ानी चाहिए जो बड़े पैमाने पर फंडिंग जुटाती हैं, और लाखों ग्राहकों की निर्भरता का हिस्सा हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को भी और सशक्त करने की आवश्यकता है ताकि ग्राहकों को रिफंड और मुआवजे के लिए लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से न गुजरना पड़े। इस स्थिति को सुधारने के लिए कंपनियों को अपनी वित्तीय प्रथाओं में पारदर्शिता लानी होगी और नियामक निकायों को कड़े कदम उठाने होंगे। जब तक ऐसा नहीं होता, ग्राहकों और ऐसी कंपनियों से जुड़े अन्य लोगों का विश्वास जीतना इन कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना रहेगा।

निराश मत हों | श्रीराम शर्मा आचार्य

तनिक विचार करो। एकलव्य गुरु द्रोण के यहां से निराश होकर धनुर्विद्या का अभ्यास छोड़ देता और भ्रांति के विचारों के संपर्क में होकर क्षुब्ध हो जाता

तो क्या सफलता को प्राप्त कराने वाली वांछनीय मनःस्थिति स्थिर रख पाता। उसने निराशासूचक उनके शब्दों को अपने अन्तःकरण को स्थायी वृत्ति नहीं बनाया। उसके बलवान मन पर भ्रांति का कोई विचार या तिरस्कार प्रभाव न डाल सका। दुर्बल-व्यक्ति चित्त पर ही प्रतिकूल प्रसंग का कुप्रभाव पड़ता है। संसार के मनुष्य, चारों ओर से निकम्मे, संदेहात्मक, दरिद्र विचार लाकर उसके अन्तःकरण में डालते हैं, और उसकी सफलता, प्रसन्नता और उत्साह को छिन्न-भिन्न कर देते हैं। यदि हम दूसरों की निराशोत्पादक बातों पर ध्यान न दें और उधर से हमेशा के लिए पीठ मोड़ कर आशा के प्रकाश की ओर रुख कर लें तो अल्प काल में ही विकसित पुष्प की भांति आनंदित हो सकते हैं। जब तुम निश्चय कर लोगे कि मेरा निराशा भरे जीवन से कोई संबंध नहीं होगा। मुझे नाउम्मीदों से कोई सरोकार नहीं है, मैं वस्त्रभूषा पर शरीर पर, व्यवहार में, अपने कार्यों में निराशा का कोई चिह्न भी न रहने दूंगा, मैं पूर्ण शक्ति और मनोरथ सिद्धि में प्रवृत्त हूंगा, निराशापूर्ण वातावरण से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तो अपनी प्रवृत्ति ही उत्तम पदार्थों की ओर कर दी है। मनोरथ सिद्धि मेरे बाएं हाथ का खेल है। मुझे संसार की कठिनाई अपने ध्येय के मार्ग विचलित नहीं कर सकतीं। तब याद रखो तुम्हारे इरादे एक दिव्य शक्ति-शासनकर्ता शक्ति प्रसन्न होगी। आत्म-श्रद्धा और स्वाभिमान प्रबल लगेंगे और तुम आश्चर्यपूर्वक कहोगे कि यह न जाने क्योंकर हो गया? तब तुम भी यही कहोगे कि मन को आशापूर्ण, प्रकाशित और प्रसन्न रखने से सफलता प्राप्त करते हैं, आशावाद की सफलता प्राप्त कराता है। 'हमारे लिए कुछ न होगा।' ऐसा निराशावादी विचार सफलता का विघातक शत्रु होता है। आशावाद बहुत बड़ी उत्पादक शक्ति है, जीवन की जड़ है, उसके अंदर प्रत्येक वस्तु निवास करती है। यह मानसिक क्षेत्र में प्रविष्ट करते ही बड़ा लाभ पहुंचाती है। अतः जिसे नाउम्मीदी से छुटकारा पाने की आकांक्षा हो उसे उचित है कि अपने मन की स्थिति को उत्पादक, उत्साहपूर्ण, उदार, प्रवर्द्धक और उदात्त रखे।

रीडर्स मेल

संयुक्त परिवार की ताकत

प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। इस सामाजिक ढांचा में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, और जीवन के हर उतार-चढ़ाव का सामना मिल-जुलकर करती हैं, जिसमें आपसी सहयोग, प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे की सहायता करते हैं, और जरूरत पड़ने पर साथ खड़े होते हैं। इसमें बुजुर्गों का अनुभव और युवाओं की ऊर्जा का संगम देखने को मिलता है। आज के समय में तेजी से बदलती जीवनशैली, पश्चिमी सभ्यता का नकल, नौकरी की आवश्यकताएं और स्वतंत्र जीवन जीने की आकांक्षा के कारण संयुक्त परिवारों की संख्या घट रही है। संयुक्त परिवार हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यह केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है, जो आपसी प्रेम, सहयोग और सामूहिक जीवन के सिद्धांतों पर आधारित है। इस परंपरा को जीवंत बनाए रखने की आवश्यकता है। नई पीढ़ी को इसका महत्त्व समझने की जरूरत है, तभी देश का भाग्य बदल सकेगा।

हिमांशु शेखर, गया

'सिंदूर' पर सियासत

पक्ष हो या विपक्ष, वह हमेशा आफत में अवसर की तलाश में रहता है। खबर है कि भाजपा 9 जून से एक माह तक महिलाओं के लिए घर-घर सिंदूर पहुंचाने का अभियान शुरू करेगी। सिंदूर पाकिस्तानी आतंकवादियों को सबक सिखाने में सफल रहने की खुशी में पहुंचाया जाएगा या अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए यह सुनिश्चित नहीं है। इतना अवश्य है कि कोई सिंदूर में अपनी हार देख रहा है और कोई जीत। भारतीय समाज में सिंदूर स्वस्थ एवं समर्पित दांपत्य जीवन का प्रतीक है। दरअसल, सिंदूर आस्था का विषय है, दिखावे का नहीं। सिंदूर से वैवाहिक संबंध की पवित्रता एवं पति के प्रति पूर्ण समर्पण का बोध होता है। ऐसे में सिंदूर को प्रत्येक घर में पहुंचाकर राजनीतिक दल कौन सा सकारात्मक संदेश समाज को देना चाहते हैं; यह आम आदमी तथा प्रबुद्ध समाज की समझ से परे है।

डॉ. सुधाकर आशावादी, मेरठ

सराहनीय फैसला

सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने पर्यावरण को बचाने के लिए बुधवार को सख्त निर्णय सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली के रिज क्षेत्र के पाश इलाके में 185 एकड़ में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर हरे-भरे पड़े को दिल्ली डेवलपमेंट अथार्टी (डीडीए) के अधिकारियों द्वारा काटने पर इसे न्यायालय की अवमानना करार दिया है। और डीडीए के प्रत्येक जिम्मेदार अधिकारियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पूरे 185 एकड़ में अधिकारियों को पेड़ लगाने और उन्हें बड़ा करने का ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। बिना कोर्ट की अनुमति के कोई भी राज्य सरकार हो या एजेंसी; वह किसी भी नाम से पेड़ को काटाई नहीं कर सकती है। यदि कोई इसके विपरीत जाकर पेड़ों की कटाई करता है तो कोर्ट उसे अवमानना की सजा दे सकती है। उक्त प्रकरण भी इसी परिपेक्ष्य में है। पेड़ो के बचाव में आए सुप्रीम कोर्ट की पीठ के इस सख्त फैसले से पर्यावरण प्रेमियों के बीच खुशी का माहौल है। उम्मीद है पर्यावरण और पेड़ों के बचाव में सुप्रीम कोर्ट आगे भी ऐसे ही ऐतिहासिक निर्णय लेगी।

अरविन्द रावल, झाबुआ मप्र
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काज़ी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्यूनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सहयोग लाल, नरमंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
| स्वामीय संपादक : रत्नेश सिन्हा* |
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 283
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी पहलुओं के लिए उत्तरदायी

बेहतर मानसून

आनन्ददायक समाचार

बेहतर मानसून आनन्ददायक समाचार है, हालांकि इससे बाढ़ और बीमारियों का खतरा भी है। भारतीय मौसम विभाग-आईएमडी ने अनुमान लगाया है कि इस मानसून मौसम में औसत से अधिक बरसात होगी। जून में उसने अपनी अद्यतन भविष्यवाणी में कहा है कि दीर्घकालीन औसत-एलपीए के आधार पर 106 प्रतिशत बरसात होगी। यह मौसम संबंधी दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन है जिससे कृषि क्षेत्र को लाभ होगा, भयानक लू से राहत मिलेगी तथा देश के जल संसाधनों के पुनर्भरण की संभावनायें पैदा होंगी। इसके साथ ही इससे शहरों में बाढ़ और बीमारियां फैलने की आशंका पैदा हो सकती है जिसके लिए सार्वजनिक ढांचे को तैयार करना होगा। मानसून की शुरुआत जल्दी हो गई है, उसने केरल से निर्धारित समय से आठ दिन पहले प्रवेश किया है तथा तेजी से पूरे दक्षिण भारत में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, जल्दी शुरुआत और औसत से अधिक बरसात की भविष्यवाणी केवल जून के लिए है, पर भारतीय मौसम विभाग को विश्वास है कि सितंबर तक औसत से अधिक बरसात होगी। इस विकासक्रम से भारत के कृषि क्षेत्रों को काफी राहत मिली है। देश में खेती का बड़ा हिस्सा मानसूनी बरसात पर निर्भर है, इसलिए समय पर और प्रचुर बरसात से बुआई में सुधार हो सकता है जिससे प्रमुख खरीफ फसलों, जैसे चावल, दालों, कपास और मक्का को लाभ होगा। बेहतर बरसात से पसलें स्वस्थ होंगी, महंगी सिंचाई पर निर्भरता घटेगी तथा इनकी उपज बढ़ने की उम्मीद है। इससे किसानों और ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी जिससे कृषक समुदायों में उपभोग बढ़ेगा।

खेती में बेहतरी के साथ ही औसत से अधिक बरसात से भयानक गरमी से राहत मिलने की उम्मीद है जिससे भारत के अनेक हिस्से झुलस रहे हैं। तुलनात्मक रूप से कम गरम जून से बिजली ग्रिडों पर बोझ कम होगा जो एयरकंडीशनिंग तथा पंखों-कूलरों के प्रयोग से बिजली की बढ़ती मांग के रूप में सामने आता है। लेकिन हर अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी होती है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में औसत से अधिक बरसात से लाभ होगा, वहीं शहरी भारत को मानसून-संबंधी कठोर चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार होना होगा। मुंबई, दिल्ली, चेन्नै और बैंगलुरू में भारी बरसात से पुरानी पड़ चुकी जल निकासी व्यवस्थायें ध्वस्त हो सकती हैं जिससे जलभराव, ट्रैफिक अव्यवस्था और निवासियों का विस्थापन तक हो सकता है। स्वास्थ्य भी चिन्ता का एक और क्षेत्र है। मानसून के महीनों में आमतौर से कीट-जनित व जल-जनित रोगों, जैसे डेंगू, मलेरिया, कालरा और लेप्टोस्पोरोसिस में बढ़ोत्तरी होती है। गंदगी, ठहरा हुआ पानी तथा बहुत घनी शहरी बस्तियों में ऐसी बीमारियां फैलने की संभावनायें बढ़ जाती हैं। यदि रोग निवारक कदम जल्दी न उठाए जाएं तो बरसात के मौसम में मौसमी बीमारियों की बढ़ोत्तरी से स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। बरसात का असमान वितरण भी समस्या का कारण बनता है। इस मानसून में भी जहां दक्षिण और मध्य भारत में औसत से अधिक बरसात की उम्मीद जताई गई है, पूर्वोत्तर में बरसात औसत से कम हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग-आईएमडी द्वारा औसत से अधिक बरसात की यह भविष्यवाणी तत्काल सरकार से सक्रियता की मांग करती है। शहरी ढांचागत संरचना को मजबूत करना और खासकर जल निकासी व सीवेज व्यवस्थायें ठीक करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत का मानसून केवल एक मौसमी परिघटना नहीं है, बल्कि इसके व्यापक प्रभाव होते हैं। मानसून में अच्छी बरसात हमारे जनजीवन, अर्थव्यवस्था तथा पूरे देश में सुख-समृद्धि का संकेत देती है। इस साल औसत से अधिक बरसात की भविष्यवाणी खेती में बेहतरी तथा गरमी के कारण होने वाली समस्यायें कम होने का संकेत देती है, वहीं अधिक बरसात की मुसीबतों से निपटने की तैयारी करना भी जरूरी है। लगातार सातवीं बार अच्छे मानसून की उम्मीद पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है जो तेजी से आगे बढ़ रही है। औसत से अधिक बरसात धरती पर तालाबों, झीलों और नदियों को पानी से भर सकती है, वहीं इससे भूमिगत जल स्रोतों को समृद्ध बनाने में उल्लेखनीय योगदान होगा।

आतंकवाद पर राजनयिक हमला

नई दिल्ली ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वस्तर पर व्यापक राजनयिक अभियान छेड़ा है। सभी समुदायों से प्रतिनिधित्व तथा सहयोग के माध्यम से भारत आतंकवाद के खिलाफ एक बहुलतावादी और मुखर विमर्श तैयार कर रहा है।

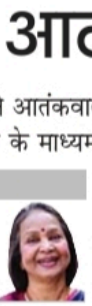

कल्याणी शंकर
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

नई दिल्ली ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वस्तर पर सहायता प्राप्त करने का व्यापक और आक्रामक राजनयिक अभियान छेड़ा है। सभी समुदायों से प्रतिनिधित्व तथा सहयोग के माध्यम से भारत आतंकवाद के खिलाफ एक बहुलतावादी और मुखर विमर्श तैयार कर रहा है। मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनयिक अभियान छेड़ा है जिसका उद्देश्य पूरे विश्व समुदाय से पाक-प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ समर्थन प्राप्त करना है। इस उद्देश्य से सात सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल इस सप्ताह दुनिया के अनेक देशों की राजधानियों में भेजे गए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाक-प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किए गए बर्बर नरसंहार में 26 निरपराध पर्यटक मारे गए थे। इसके बाद भारत ने आतंकियों को सजा देने के लिए 'आपरेशन सिंदूर' शुरू किया है। पहलगाम में मारे गए निरपराध पर्यटकों की संख्या मुंबई के 26-11 आतंकवादी हमलों में मारे गए लोगों की संख्या के बाद सबसे अधिक है।

नई दिल्ली पहलगाम आतंकी हमलेतथा उसके जवाब में किए गए 'आपरेशन सिंदूर' के बारे में राजनयिक अभियान चला रही है। इस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया मिश्रित रही है। जहां अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब अमीरात-यूएई और संयुक्त राष्ट्रसंघ ने संयम और संवाद की पैरवी की है, वहीं इस्राइल ने नई दिल्ली का पूरा समर्थन किया है। चीन ने भी हमलों की निन्दा करते हुए दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

आतंकवाद को प्रोत्साहित करने में पाकिस्तान की भूमिका पर जोर देते हुए नई दिल्ली ने कहा है कि तनाव-घटाने का कदम पाकिस्तान की ओर से उठना चाहिए। पाकिस्तान जहां स्वयं को आतंकवाद से पीड़ित देश के रूप में पेश करता है, वहीं नई दिल्ली आतंकवाद में उसकी संलिप्तता पर अपनी बात प्रभावी रूप से सारी दुनिया के सामने रख रही है। सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के दोहरे मानकों को उजागर करते हुए इसके खिलाफ संघर्ष में एकजुटता की आवश्यकता बता रहे हैं।

आतंकवाद के मुद्दे पर सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडलों को दुनिया भर में भेजना एक अच्छा विचार है जिससे विश्व समुदाय को आतंकवाद के बारे में सूचित करने तथा उसका समर्थन प्राप्त करने का अवसर मिलता है। सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल प्रमुख सांसदों में कांग्रेस के शशि थरूर और आनन्द शर्मा, भाजपा के बैजयंत पांडा और रवि शंकर प्रसाद, जदयू के संजय कुमार झा, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, द्रमुक की कनिमोई, राकांपा की सुप्रिया सुले शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य अपनी यात्रा वाले देशों में विभिन्न लोगों से बातचीत करेंगे जिनमें राजनेता और बुद्धिजीवी शामिल हैं।

सांसदों को अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाने के लिए उपयुक्त सूचनाओं से अच्छी तरह लैस किया गया है और वे अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के 33 देशों में जाने की आशा है। प्रतिनिधिमंडलों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग के 31 सांसद तथा अन्य दलों के 20 सांसद शामिल हैं। उनकी सहायता पूर्व राजनयिक करेंगे। उनके मिशन का संदेश 'एक संदेश, एक राष्ट्र, एक भारत' अभियान है।

इसके पीछे लक्ष्य पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना है। इस संयुक्त प्रयास में भाजपा, विपक्षी तथा मुस्लिम समुदाय एक ही स्वर में बोल रहे हैं कि आतंकवाद के प्रति 'जीरो टालरेंस' रहेगा। इससे न केवल नई दिल्ली की प्रतिबद्धता मजबूत होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि विश्व समुदाय भारत की प्रतिबद्धता पर गौर करे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 मई को राजस्थान में घोषणा की कि 'मोदी का दिमाग ठंडा है, यह ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का खून गरम है और अब मोदी की नसों में खून नहीं, बल्कि सिंदूर बह रहा है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को हर आतंकी हमले का भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ेगा।'

ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सरकार ने विदेश नीति संबंधी मुद्दों पर विपक्ष को एकसाथ लिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव, भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी और डा. मनमोहन सिंह ने पहले भी ऐसे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के विभिन्न देशों में भेजे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव का विश्वास था कि भारतीय प्रतिनिधिमंडलों के नेता के रूप में प्रमुख विपक्षी नेताओं को शामिल करने से भारतीय प्रतिनिधिमंडल अपनी छाप बेहतर ढंग से छोड़ने में सफल होंगे। हालांकि, किसी अन्य लोकतांत्रिक देश की तरह भारत में भी सरकार और विपक्ष के दृष्टिकोण अनेक मुद्दों पर अलग-अलग होते हैं, पर जब सरकार अपनी बात वैश्विक स्तर पर पहुंचाना चाहती है तो वह विपक्ष को ऐसे प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। वैसे भी आमतौर से थोड़े बहुत मतभेद के बावजूद भारत में विदेश नीति संबंधी मुद्दों पर अधिकांश विपक्षी नेता सरकार के साथ रहे हैं ताकि दुनिया के समक्ष भारत का दृष्टिकोण एक राष्ट्र के रूप में पूरी समग्रता के साथ रखा जा सके। इस बार भी सरकार के प्रस्ताव पर विपक्ष की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही है। ऐसे प्रयास के माध्यम सेमोदी सरकार 'आपरेशन सिंदूर' की आलोचना को नियंत्रित रखना चाहती है और इसीलिए उसने विपक्षी सांसदों को अंतरराष्ट्रीय राजनयिक प्रयासों का अंग बनाया है।

इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य सारी दुनिया के समक्ष आतंकवाद के मुद्दे पर एक संयुक्त मोर्चा बनाना है। भाजपा का यह कदम लोकतंत्र में स्वागत योग्य है क्योंकि इससे बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत होगी। भारत के लोकतांत्रिक प्रयासों में विविधतापूर्ण दृष्टिकोणों को समाहित करना एक सकारात्मक कदम है।

'द वायर' के अनुसार, केरल के माकपा सांसद जान ब्रिटास ने कहा था, 'हमारी सहभागिता से स्पष्ट होता है कि विपक्ष हमारे लोकतंत्र में एक समन्वित भूमिका अदा करता है।' आल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन-एआईएमआईएम के अदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, 'हम सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ देश का समर्थन कर रहे हैं।'

एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा द्वारा नीतिगत निर्णयों से मुसलमानों को अलग रखने और भारत में अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति वैश्विक चिन्ताओं के बावजूद मुस्लिम सांसदों का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल करना एक रणनीतिक परिवर्तन है। सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के 59 सदस्यों में दस मुसलमान हैं। इस प्रकार मोदी सरकार विदेश नीति संबंधी पहलों में ज्यादा राजनीतिक लाभ लेने के लिए अब बहुलतावादी विमर्श को प्रोत्साहित कर रही है। निसंदेह विदेश मंत्रालय सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों की दुनिया के अनेक देशों में यात्रा के प्रभाव का मूल्यांकन करेगा। उनकी वापसी के बाद भी नई दिल्ली को ऐसे प्रयास जारी रखने चाहिए तथा प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता में शामिल करना चाहिए। इससे लोकतांत्रिक समर्थन की प्रभावशीलता बढ़ेगी। इससे संदेश ज्यादा लक्षित और स्पष्ट होगा।

कुल मिला कर इस मुद्दे पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजना प्रशंसनीय है। नई दिल्ली आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध है, फिर चाहे वह देश के स्तर पर हो या दुनिया के स्तर पर। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आतंकवाद-विरोध के क्षेत्र में दुनिया भर में भारतीय हितों को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी सरकार दुनिया के दूसरे देशों से सहयोग कर सारी दुनिया में आतंकवाद के प्रति 'जीरो टालरेंस' के दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रही है। इससे आतंकवाद के मूल कारणों को संबोधित करने में सहायता मिलेगी।

बढ़ती जनसंख्या का भारतीय महिलाओं पर प्रभाव

> ऐसे कई उदाहरण और अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि दो बच्चों का मानदंड पितृसत्ता की पारंपरिक संरचनाओं को लाभ पहुंचाता है और उन्हें मज़बूत बनाता है।

स्वप्ना मजूमदार
(लेखिका, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भारत 2023 में चीन को पीछे छोड़कर 1.45 बिलियन की आबादी के साथ, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। फिर भी, विडंबना यह है कि देश में अधिक बच्चे पैदा करने की मांग बढ़ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने दंपतियों से कम से कम तीन बच्चे पैदा करने को कहा है। वह अकेले नहीं हैं। आंध्र प्रदेश (एपी) और तमिलनाडु (टीएन) के मुख्यमंत्री भी अपने राज्यों के लोगों से अपने परिवार का आकार बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं। ऐसी मांगों के लिए दिए गए कारणों में से एक प्रजनन दर में गिरावट है, खासकर एपी और टीएन में। इन दोनों दक्षिणी राज्यों में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) प्रति महिला दो जन्मों के प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है।

दशकों तक दो बच्चों या उससे कम के लिए दबाव डालने के बाद, ज्यादातर महिलाओं को लक्षित करने वाली जबरदस्ती वाली परिवार नियोजन नीतियों के माध्यम से, अब जबकि 29 राज्यों में से 17 में वांछित टीएफआर हासिल करने का लक्ष्य हासिल हो गया है, तो यह अब वांछनीय क्यों नहीं है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए यह संसदीय सीटें और राजनीतिक प्रभाव खोने का डर है।

1976 में, प्रत्येक राज्य की संसदीय सीट हिस्सेदारी उनकी 1971 की जनसंख्या के आधार पर 25 वर्षों के लिए स्थिर कर दी गई थी। यह उन्हें आश्वस्त करने के लिए था कि यदि जनसंख्या कम करने की नीतियों को लागू करने के परिणामस्वरूप उनकी जनसंख्या कम हो जाती है, तो संसदीय सीटों का उनका कोटा नहीं बदलेगा। 2001 में, जब इस सीट शेयर नीति की

समीक्षा की जानी थी, तो राज्य की जनसंख्या के बावजूद सीटों की समान संख्या को अगले 25 वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया था। पिछले साल से, संकेत मिल रहे हैं कि यह अगले साल (2026) में बदलने वाला है, जब इसकी समीक्षा की जानी है। जनसंख्या-आधारित परिसीमन के साथ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की संसदीय सीटें तेजी से घटेंगी।

जनसंख्या वृद्धि को धीमा करने में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले आबादी वाले उत्तरी राज्यों को उन दक्षिणी राज्यों की कीमत पर लाभ होगा, जिन्होंने अपने टीएफआर को कम करने में अच्छा प्रदर्शन किया है। ऐसा कहा गया है कि यह संघवाद की भावना के खिलाफ होगा। इन सभी तर्कों में, एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि इसका महिलाओं पर क्या असर होगा, जबकि जनसंख्या नीति के केंद्र में वही महिलाएं हैं। जब 1992 में दो बच्चों की नीति लागू की गई थी, जिसमें केवल दो या उससे कम बच्चों वाली महिलाओं को ही पंचायत और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी, तब भी महिलाओं के प्रजनन और मानवाधिकारों के बारे में कोई विचार नहीं किया गया था। अगर महिला उम्मीदवार होती और उसके दो से ज्यादा बच्चे होते, तो उसे गर्भपात कराना पड़ता या अपने बच्चे को छोड़ना पड़ता। अगर वे उम्मीदवारों की पत्नी होतीं, तो उन्हें जबरन गर्भपात या त्याग का सामना करना पड़ता। उन्हें दोनों ही स्थितियों में तकलीफ़ उठानी पड़ती। ऐसे कई उदाहरण और अध्ययन हैं जो दिखाते हैं कि दो बच्चों का मानदंड पितृसत्ता की पारंपरिक संरचनाओं को लाभ पहुंचाता है और उन्हें मजबूत बनाता है।

फिर भी, जनसंख्या 'नियंत्रण' के नाम पर यह कई राज्यों में जारी है। अब जबकि कुछ राजनीतिक निर्णयकर्ता जनसंख्या में वृद्धि चाहते हैं, तो कुछ राज्य आंध्र प्रदेश का अनुसरण कर सकते हैं, जिसने हाल ही में दो बच्चों के मानदंड को समाप्त कर दिया है। लेकिन क्या इस निर्णय से महिलाओं को लाभ होगा? कानून के बावजूद कन्या भ्रूण हत्या और बेटे को तरजीह देना एक गंभीर वास्तविकता बनी हुई है।

पिछले महीने हरियाणा सरकार ने लड़कियों के प्रति घटते लिंग अनुपात के जवाब में लिंग-चयनात्मक गर्भपात और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (पीएनडीटी) अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में समर्पित पुलिस सेल स्थापित करने की घोषणा की।

चिंता की बात यह है कि यह केवल हरियाणा में ही नहीं है जहां गर्भ में ही बालिकाओं की हत्या कर दी जाती है। कौन गारंटी दे सकता है कि अधिक बच्चों के जन्म को प्रोत्साहित करने से महिलाओं के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य और अधिकारों का अधिक उल्लंघन नहीं होगा? महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को लेकर बातचीत क्यों होनी चाहिए, जबकि उन्हें ही यह तय करने का अधिकार है कि उन्हें क्यों, कब और कितने बच्चे चाहिए?

आप की बात

तिरंगा यात्रायें

आपरेशन सिंदूर से आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद करने वाली सेना का पूरे ही देश ने खुलकर स्वागत एवं समर्थन किया। पूरे देश में निकली तिरंगा यात्राओं का नेतृत्व नरेन्द्र मोदी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ तथा अनेक भाजपा नेताओं ने किया। जम्मू कश्मीर में अनेक स्थानों पर तिरंगा यात्राओं के आयोज से देश के दुश्मनों को उचित सबक दिया गया है। श्रीनगर, बारामुला, पुंछ, अनतनाग, बडगाम, त्राल व पहलगाम सहित सारा कश्मीर आज तिरंगा हाथ में लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इनसे जम्मू कश्मीर समेत सारे देश की एकजुटता आतंकवाद-विरोध में स्पष्ट रूप से सामने आई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में कैबिनेट बैठक कर संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद से डरने के बजाय उसके विरोध में एकजुट हो गई है। यह भी बहुत खुशी की बात है कि देश भर से पर्यटक पहलगाम समेत जम्मू कश्मीर के अन्य पर्यटन स्थलों पर जाने लगे हैं। जम्मू कश्मीर समेत देश के सभी पर्यटन स्थलों व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने के साथ देशद्रोहियों के खिलाफ जनता का पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए। देशद्रोहियों को अब कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए।

– **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

इस्लाम-दुश्मन पाकिस्तान

1947 में इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का आज तक इस्लाम से कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं दिखता। इस्लाम शांति, न्याय और भाईचारे का धर्म है, लेकिन पाकिस्तान की नीतियाँ और कार्यवाहियाँ इसके ठीक उलट हैं। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान में जिस तरह से जश्न मनाया गया, वह इस्लामी मूल्यों की खुलेआम अवहेलना है। पहलगाम में जिस तरह धर्म पूछ कर लोगों को मारा गया उससे इस्लाम पर कालिख पोतने वालों को और मौका मिल गया है। हालांकि, चंद उलेमा इस्लाम की कट्टरपंथी व्याख्या कर गैर-मुसलमानों का जबरन धर्म परिवर्तन या उनकी हत्या की आतंकी गतिविधियों को उचित ठहराते हैं। लेकिन दुनिया भर के उदारवादी व मध्यमार्गी मुसलमानों ने ऐसे लोगों को गैर-इस्लामी तक घोषित किया है। भारत द्वारा दुनिया भर में भेजे सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, एम.जे. अकबर व सलमान खुर्शीद जैसे विद्वान मुस्लिम नेता शामिल हैं। वे सारी दुनिया को पाकिस्तान की असलियत बता रहे हैं। दिल्ली के शाही इमाम मौलाना बुखारी ने भी कहा था कि आतंकियों की हरकतों से भारतीय मुसलमान भी बदनाम हो रहे हैं।

– **मधु सुभाष बुड़ावन वाला**, रतलाम

चीनी माल का बहिष्कार

देश में चीनी माल का बहिष्कार केवल व्यापारिक नहीं बल्कि राष्ट्रहित में उठाया गया निर्णायक कदम है। यदि जनता और व्यवसाई इस पर सख्ती से अमल करें तो बहुत थोड़े समय में चीन को दिन में तारे दिखाए जा सकते हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री की अपील केवल भावनात्मक नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी रणनीति का हिस्सा है। चीन की आक्रामक नीतियां और पाकिस्तान के साथ उसका गठजोड़ भारत की संप्रभुता के लिए गंभीर चुनौती पैदा करता हैं। प्रधानमंत्री द्वारा पिचकारी, मूर्तियों और सजावटी सामानों का उदाहरण देना यह दर्शाता है कि देश को चीनी उत्पादों का बहिष्कार आत्मनिर्भरता की ओर जाने के लिए हमें रोजमर्रा की छोटी चीजों से शुरुआत करनी होगी। जिस प्रकार पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर और तुर्की की कंपनियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है उससे स्पष्ट है कि भारत अब सिर्फ मौखिक विरोध में विश्वास नहीं करता बल्कि ठोस कार्रवाई भी करता है। भले ही चीनी माल का पूर्ण बहिष्कार तुरंत संभव न हो, लेकिन धीरे-धीरे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर हम आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ सकते हैं। इसके लिए स्पष्ट योजना तथा जन-सहयोग की जरूरत है।

– **अमृतलाल मारू**, इंदौर

राहवीर योजना

देश के किसी न किसी हिस्से में रोज सड़क दुर्घटनायें होती रहती है। सड़क दुर्घटना में घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को साल में 5 बार सम्मानित करने का निर्णय निश्चित हीं सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए वरदान साबित होंगा। इस प्रोत्साहित करने वाली योजना से लोगों में सहायता करने का जस्बा भी आएगा। पहले सड़क दुर्घटना में सहायता करने वाले व्यक्ति भी बेवजह पुलिस कार्यवाही के दायरे में आ जाते थे। इससे ये प्रभावितों की मदद नहीं करते थे। प्रदेश में शुरू की गई राहवीर योजना से सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाई जा सकती है। घायल को अस्पताल तक पहुंचाने में मददगार राहवीरों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जाएगा। 10 सर्वश्रेष्ठ राह वीरों को 1 लाख नगद, ट्राफी और प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाएगा। उम्मीद है कि सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने में कोई भी राहवीर पीछे नहीं हटेगा। पहले भी सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की सहायता के लिए अनेक योजनायें बनी हैं, पर उनका समुचित लाभ नहीं दिखा है। इसलिए इस योजना के प्रति जन-जागरूता अभियान जरूरी होगा।

– **योगेश जोशी**, बड़वाह

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

चिंतन

अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि ठीक, पर आर्थिक सुधार जरूरी

अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नई उपलब्धियों से भारत का आर्थिक आकार और बड़ा हो गया है। केंद्रीय बैंक के आकार में 33 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बही-खाते का आकार बढ़कर 76.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह 31 मार्च, 2024 तक 70.47 लाख करोड़ रुपये था। यह उपलब्धि विदेशी मुद्रा लेनदेन में हुई वृद्धि के चलते हासिल हुई है। अभी कुछ दिन पहले ही रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये का बड़ा लाभांश दिया है। यह बड़ी धनराशि है, जो रिजर्व बैंक की मजबूती को दिखाता है। नीति आयोग के मुताबिक, क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार पहले से ही 15,000 अरब डॉलर है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आधे से भी अधिक है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 29,000 अरब डॉलर पर है। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) का उपयोग विभिन्न देशों के बीच मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य की तुलना करने के लिए किया जाता है। बाजार विनिमय दर का उपयोग करने के बजाय, पीपीपी उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें प्रत्येक देश में मुद्रा की एक निश्चित राशि के साथ खरीदा जा सकता है। नीति आयोग ने अभी आंकड़े जारी कर कहा था कि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इसको लेकर कुछ आलोचना भी हुई, क्योंकि भारत के अधिकांश आर्थिक संकेतक या तो नीचे हैं या सुस्त हैं। इस पर ही नीति आयोग ने एक तरह से सफाई दी है कि बड़ी या छोटी अर्थव्यवस्था बाजार मूल्यों पर आंके जाते हैं, जबकि उत्पादकता को मापने का वास्तविक तरीका क्रय शक्ति समता (पीपीपी) है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में नीति आयोग ने आंकड़ा दिया कि हम बाजार मूल्यों पर 4,000 अरब डॉलर के जीडीपी पर हैं, पर पीपीपी के संदर्भ में, हम 15,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं। आरबीआई ने अपनी 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में भरोसा दिया है कि देश वित्त वर्ष 2025-26 में भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दीर्घकालीन भू-राजनीतिक तनाव और भू-आर्थिक विखंडन के बीच, मजबूत वृहद आर्थिक बुनियादी आंकड़ों और सक्रिय नीतिगत उपायों के समर्थन से 2024-25 में अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। रिजर्व बैंक को महंगाई दर चार फीसदी के लक्ष्य के अनुरूप रहने की पूरी उम्मीद है, इससे कर्ज महंगे होने की संभावना क्षीण दिखाई दे रही है। महंगाई दर में गिरावट के बाद केंद्रीय बैंक ने लगातार दो समीक्षाओं में प्रमुख नीतिगत दर रेपो में कटौती की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि देश में डिजिटल मुद्रा का चलन बढ़ रहा है। मार्च 2025 के अंत तक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) या ई-रुपये का मूल्य बढ़कर 1,016 करोड़ रुपये हो गया, जो इससे एक साल पहले 234 करोड़ रुपये था। अब सीबीडीसी के जरिये सीमापार भुगतान को प्रायोगिक आधार पर शुरू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। यह रिजर्व बैंक का डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का भविष्योन्मुखी प्लान है। अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि और डिजिटल करेंसी की दिशा में प्रगति से भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। जीडीपी सुस्त है, निर्यात घट रहा है, व्यापार घाटा चिंताजनक स्तर पर है, विदेशी निवेश में उत्साह नहीं है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और आठ कोर इंडस्ट्री सेक्टर में गिरावट है। देश को तत्काल आर्थिक सुधार की जरूरत है।

उपलब्धियां
जी. किशन रेड्डी

'शक्ति नीति' में संशोधन कोयला क्षेत्र में सुधारों की एक सतत श्रृंखला में से एक है जिसका उद्देश्य थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) को पारदर्शी तरीके से कोयला आवंटित करना और इसके आसपास की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में कोयला उत्पादन और प्रेषण में 1 बिलियन मीट्रिक टन को पार करने वाली भारत की दोहरी उपलब्धि के बाद आया है, जो सीधे तौर पर खनन से जुड़े लगभग 5 लाख श्रमिकों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। अनेक लोग और भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में योगदान करते हैं। भारत को ये उपलब्धियां एक दशक के अथक प्रयास, कड़े परिश्रम, गहन सुधारों और ऐतिहासिक निर्णयों का परिणाम है।

नवाचार से बढ़ रहा कोयला क्षेत्र

बीते दिनों जब सीमा पर संघर्ष चरम पर था और भारतीय वीर जवान ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमारे निर्दोष लोगों की हत्या और हमारी 'नारी शक्ति' के अपमान का बदला दुश्मन से ले रहे थे, तब आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए 'शक्ति नीति' में संशोधन को मंजूरी दी, जिससे एक बार फिर दिखा कि सरकार की बहु-कार्य क्षमताएं कई मुद्दों पर कई परिणामों को एक साथ प्राथमिकता दे सकती हैं। 'शक्ति नीति' में संशोधन कोयला क्षेत्र में सुधारों की एक सतत श्रृंखला में से एक है जिसका उद्देश्य थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) को पारदर्शी तरीके से कोयला आवंटित करना और इसके आसपास की प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। यह पिछले वित्तीय वर्ष में कोयला उत्पादन और प्रेषण में 1 बिलियन मीट्रिक टन को पार करने वाली भारत की दोहरी उपलब्धि के बाद आया है, जो सीधे तौर पर खनन से जुड़े लगभग 5 लाख श्रमिकों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। इसके अलावा अनेक लोग और भी हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र में योगदान करते हैं।

भारत को ये उपलब्धियां रातों-रात प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि ये परिवर्तन एक दशक के अथक प्रयास, कड़े परिश्रम, अटूट विश्वास, गहन सुधारों और ऐतिहासिक निर्णयों का परिणाम है। 2014 में कोयला क्षेत्र पूरी तरह अव्यवस्थित था। तेजी से बढ़ती मांग की तुलना में कोयले के उत्पादन में गंभीर घाटा था। कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में 2009-2010 में 566 मिलियन टन से 2013-2014 में 610 मिलियन टन की एक मामूली वृद्धि देखी गई। एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में हमारी जरूरतों के लिए 1.5% की संचयी वार्षिक वृद्धि दर पर्याप्त नहीं थी। 2014 में इसे नव निर्वाचित नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जा रहा था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 204 कोयला ब्लॉकों को रद करने से सरकार को परिवर्तनकारी बदलाव की तलाश करने का अवसर मिला। ग्यारह साल बाद मार्च-2025 तक, लगभग 150 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है।

जून, 2020 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वाणिज्यिक कोयला खनन के शुभारंभ के बाद से, 11 दौर पूरे हो चुके हैं और वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 12वां दौर जो हाल ही में मार्च, 2025 में शुरू किया गया था, प्रगति पर है। परिणाम खुद ही बोलते हैं : पिछले एक दशक में भारत के कोयला उत्पादन में 70% की वृद्धि देखी गई है। ये पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता के साथ एक बड़ी वृद्धि भी है और एक बड़ी उपलब्धि भी, जिसमें राज्य सरकारें सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक रही हैं, जिन्होंने पूरे खनन क्षेत्र के लिए लगभग 4.4 लाख करोड़ रुपये और विशेष रूप से कोयला क्षेत्र के लिए 1.6 लाख करोड़ रुपये, केवल नीलामी प्रीमियम और विभिन्न राज्य सरकार के खजाने में प्राप्त रॉयल्टी के माध्यम से प्राप्त किए हैं। स्वतंत्रता के बाद, कोयला उत्पादन को बढ़ाने और विकास के एक नए युग की शुरुआत करने का एक बड़ा अवसर था। मगर निजी क्षेत्र का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए रणनीतिक समझ की कमी नुकसानदेह थी। माल ढुलाई समानीकरण नीति जैसी नीतियों ने खनन क्षेत्रों के करीब उद्योग स्थापित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि कारखानों को दूर स्थापित

करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। 17 मई 1957 को तत्कालीन इस्पात, खान और ईंधन मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह ने कोयला खनन उद्योग पर अधिक सार्वजनिक नियंत्रण प्राप्त करने के इरादे से लोकसभा में "कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) विधेयक" पेश किया। 1951 से 1956 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत का कोयला उत्पादन 38 मिलियन टन था। चर्चा निजी क्षेत्र के अंतर्निहित अविश्वास के इर्द-गिर्द केंद्रित थी। निजी क्षेत्र की नवाचार और जोखिम लेने की क्षमताओं और भारतीय युवाओं की उद्यमशीलता की भावना में इस अविश्वास के परिणामस्वरूप 1990 में कोयला उत्पादन लगभग 200 मिलियन मीट्रिक टन तक ही पहुंच पाया। 2020 से शुरू की गई वाणिज्यिक नीलामी व्यवस्था अतीत से एक महत्वपूर्ण बदलाव है। दशकों से कोयला और खदान क्षेत्र में पर्याप्तरण संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज किया जाता रहा है। मगर पिछले एक दशक में सस्टेनेबिलिटी सबसे आगे आ गई है। वर्तमान में चल रही सौर और पवन परियोजनाओं, पंप स्टोरेज प्लांट और कोल इंडिया के पहले गैर-कोयला महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक अधिग्रहण के साथ विविधीकरण ने गति पकड़ी है। इसके अलावा, कैबिनेट ने 8500 करोड़ रुपये के कोयला गैसीकरण कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी है और निवेश को और बढ़ाने की योजना बनाई है।

अगले कुछ वर्षों में, खदान बंद करना एक मुख्य प्राथमिकता बनी रहेगी और निर्बाध, प्रगतिशील और टिकाऊ खदान बंद करने की गतिविधियों को सक्षम करने के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया जा रहा है। भूमिगत खनन के पर्यावरणीय लाभों को पहचानते हुए हमने 2029-30 तक 100 मीट्रिक टन तक पहुंचने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप निर्धारित किया है और इसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, मंत्रालय फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि 90 प्रतिशत कोयले को कन्वेयर बेल्ट जैसे मशीनीकृत और पर्यावरण के अनुकूल प्रणालियों के माध्यम से लोड किया जाएगा। रिकॉर्ड कोयला उत्पादन के बावजूद, भारत का प्रति व्यक्ति कोयला ऊर्जा उपयोग चीन, अमेरिका और यूरोप से बहुत कम है।

पिछले एक दशक में, बिजली की समग्र स्थापित क्षमता में कोयले का योगदान कम होता गया है। 2014-2015 में स्थापित क्षमता में 60 प्रतिशत योगदान देने से यह अब घटकर 47 प्रतिशत हो गया है, जबकि सौर और अन्य नवीकरणीय स्रोतों में तेजी आई है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और 2047 तक पूरी तरह से विकसित 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में तब्दील हो जाएंगे, हमारी ऊर्जा की जरूरतें बढ़ती रहेंगी और कोयला हमारे ऊर्जा मिश्रण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना रहेगा। भारत का कोयला क्षेत्र न केवल भारत के विकास को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि यह आधुनिक खनन अर्थव्यवस्था के नियमों को भी पुनः लिख रहा है। कोयला व्यापार विनिमय (कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज) जैसे नवाचारों और भविष्य की पहलों के साथ, अब कोयला क्षेत्र में सुरक्षा, दक्षता और डिजिटल जुड़ाव के साथ-साथ एआई, ई3जी और जीपीएस ट्रैकिंग को तैनात कर रही है। एक समय भ्रष्टाचार से ग्रस्त, असंतुलित और अकुशल कोयला और खनन क्षेत्र में पिछले दशक में एक बड़ा बदलाव आया है। जब हम आधुनिकीकरण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और टिकाऊ प्रथाओं पर निरंतर ध्यान केंद्रित करते हुए भविष्य की ओर देखते हैं, तो और भी अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां सामने आएंगी, जो वैश्विक खनन और संसाधन अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करेंगी।

(लेखक केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

प्रेरणा
सोनम लववंशी

देश को मिजोरम शिक्षा मॉडल की ज़रूरत!

जब भारत के कई राज्य अब भी शिक्षा के बुनियादी लक्ष्यों को छूने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे समय में मिजोरम ने इतिहास रच दिया है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं, बल्कि वह मशाल है, जो देश के लिए दिशा और प्रेरणा दोनों बन सकती है। आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2023-24 के अनुसार, मिजोरम ने 98.2 प्रतिशत की साक्षरता दर के साथ 'पूर्ण साक्षरता' का गौरव प्राप्त कर लिया है और इसी के साथ यह भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर दस में लगभग दस व्यक्ति पढ़ना-लिखना जानते हैं। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उस सामाजिक चेतना, प्रतिबद्ध प्रशासन और शिक्षकों की निःस्वार्थ भागीदारी की गाथा है, जिसने शिक्षा को अधिकार नहीं, जिम्मेदारी माना। अक्सर हाशिए पर रखे जाने वाले उत्तर-पूर्वी राज्यों में से एक, मिजोरम ने दिखा दिया है कि विकास केवल संसाधनों पर नहीं, संकल्प और सहभागिता पर निर्भर करता है। शिक्षा को लेकर यह राज्य जिस प्रकार आगे बढ़ा है, वह भारत की समग्र शिक्षा नीति पर एक मौन प्रश्नचिन्ह भी है कि जो छोटे और संसाधन वंचित राज्य कर सकते हैं, वह बड़े और अपेक्षाकृत समृद्ध राज्य क्यों नहीं? 2023 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए 'उल्लास' नव-साक्षरता अभियान को मिजोरम ने केवल सरकारी योजना की तरह नहीं लिया, बल्कि उसे एक सामाजिक आंदोलन में तब्दील कर दिया। समग्र शिक्षा और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को जोड़ते हुए इसे मिशन मोड में उतारा गया। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन हुआ और एससीईआरटी के अंतर्गत एक 'राज्य साक्षरता केंद्र' की स्थापना की गई। यहां मिजो भाषा में 'वर्टिंवन' नामक अध्ययन सामग्री तैयार की गई, स्वयंसेवी शिक्षकों के लिए 'मार्गदर्शक' पुस्तिका बनाई गई और छात्रों के लिए 'रीमी' जैसे संसाधन विकसित किए गए। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर समन्वयकों ने अगस्त-सितंबर 2023 में घर-घर जाकर 15 वर्ष से अधिक आयु के 3,026 अशिक्षित लोगों की पहचान की। यह अभियान किसी नियम का पालन मात्र नहीं था, यह उस भावना का प्रकटीकरण था जो समाज को पूर्ण ज्ञान से जोड़ना चाहता है। इनमें से 1,692 लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा जताई। यह आंकड़े नहीं, बल्कि बदलती चेतना और सामाजिक परिवर्तन के प्रमाण हैं। यही वजह है कि मिजोरम की यह उपलब्धि महज केरल को पीछे छोड़ने की बात नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि शिक्षा जब जीवन के ताने-बाने में बसी हो, तो वह संख्याओं से आगे जाकर एक संस्कृति बन जाती है। जब देश की औसत साक्षरता दर अब भी 85 प्रतिशत के आसपास है, तब मिजोरम का 98.2 प्रतिशत तक पहुंचना यह सिद्ध करता है कि संसाधनों की बहुलता नहीं, दिशा और नीयत महत्वपूर्ण है। यह राज्य, जो भौगोलिक रूप से दूरस्थ और आर्थिक रूप से सीमित है, उसने यह कर दिखाया। भारत के बाकी राज्यों के लिए यह मात्र एक मिसाल नहीं, एक चेतावनी भी है कि अगर शिक्षा अब भी प्राथमिकता नहीं बनी, तो हम अपने सबसे मूल्यवान संसाधन, यानी युवा पीढ़ी को खो बैठेंगे। शिक्षा को लेकर मिजोरम की यह प्रतिबद्धता एक और बात सिद्ध करती है कि कोई भी नीति, चाहे वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो, तब तक निष्फल है जब तक समाज उसे अपने मूल्य की तरह नहीं अपनाता। मिजोरम की सफलता का रहस्य केवल सरकारी योजनाओं या आंकड़ों में नहीं छिपा, बल्कि समाज के उस गहरे भाव में है जिसने शिक्षा को आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और नागरिक चेतना का औजार बना लिया है। वहां शिक्षा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी मात्र नहीं है, न ही डिग्री प्राप्ति की दौड़। गाँवों में भी विद्यालय महज सरकारी उपस्थिति का प्रमाण नहीं हैं, बल्कि वहाँ शिक्षक समय पर आते हैं, छात्र पूरे समर्पण से पढ़ते हैं और अभिभावक शिक्षा को जीवन का अविभाज्य हिस्सा मानते हैं। हमें ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जहां शिक्षा केवल मंत्रालयों का विषय न होकर हर नागरिक की साझी जिम्मेदारी बने। ऐसे शिक्षक चाहिए जो केवल पढ़ाएं नहीं, बल्कि प्रेरणा बनें; ऐसे पाठ्यक्रम चाहिए जो स्थानीयता से जुड़े हों और ऐसी व्यवस्थाएं चाहिए जो विद्यालयों को किसी कोने की फाइल नहीं, व्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ बनाएं। मिजोरम ने हमें यह दिखाया है कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ सामाजिक चेतना, आत्मनिर्भरता और नागरिक जिम्मेदारी में है। अब समय आ गया है कि देश इस मॉडल को केवल सराहे नहीं, बल्कि इसे अपनाए। जब तक हम शब्दों से निकलकर ज़मीन पर नहीं उतरेंगे, तब तक 'ज्ञान की महाशक्ति' बनने का सपना अधूरा ही रहेगा।

(लेखिका स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

असंयम लक्ष्य विमुख कर देता हैं

संकलित
दर्शन

भगवान श्रीराम हर पल आत्मस्थिति में रहे। वे तनिक भी असंयमित नहीं हुए। असंयम लक्ष्य विमुख कर देता है। जब हम किसी से प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, तब उस व्यक्ति के गुण और उसके कार्यों को हम किसी और ढंग से देखते हैं। उसी व्यक्ति से जब हमारा राग होता है, तो हम उसके हर कार्य में श्रेष्ठता ही देखते हैं। द्वेष होने पर हम न्यूनता और दोषों को ही खोजते हैं। आसक्ति होने पर उसके प्रति हम अपना सर्वस्व न्योछावर करने में भी तनिक संकोच नहीं करते हैं। हमारी यह इंद्रधनुषीय दृष्टि और वृत्ति जब किसी पद और अधिकार प्राप्त व्यक्ति के साथ जुड़ जाती हैं, तब वह व्यक्ति विकार को और भी विकृत कर उसे व्यापक बना देता है, तब उस मनःस्थिति में निर्णय देने, सामाजिक व्यवहार करने में वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता हुआ स्वयं और समाज को गर्त में डाल देता है। श्रीराम चरित मानस में गुरु वशिष्ठ ने श्रीभरत के अंदर तब इस त्रिपुटी की प्रधानता स्वीकारी, जब श्रीभरत भगवान की पादुकाओं को अपने सिर पर लेकर आए और गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि यदि आपका मंगलाशासन हो तो मैं पादुका रूप प्रभु को नंदीग्राम जाकर सिंहासनासीन कर वहीं से राज्य का कार्य संभाल लूंगा? तब गुरुदेव ने मानो भरत से यही कहा कि समुद्रत्व (समझ) के रूप में तुम्हारे अंदर विचारिका के गुण हैं, कहब (कथन) के रूप में न्यायपालिका के गुण हैं और करब (करनी) के रूप में कार्यपालिका के गुण हैं। भरत ऐसे भक्त हैं, जिन्होंने अपनी समझ, कथन, और करनी का योग भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया।

कर्म महत्वपूर्ण है

संकलित
प्रेरणा

एक निकम्मे आदमी की पत्नी ने उसे घर से निकलते हुए कहा आज कुछ न कुछ कमा कर ही लौटना नहीं तो घर में नहीं घुसने दूगीं। आदमी दिन भर इधर-उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ काम नहीं मिला। निराश मन से वह जा रहा था कि उसकी नजर एक मरे हुए सांप पर पड़ी। उसने एक लाठी पर सांप को लटकाया और घर की ओर जाते हुए सोचने लगा, इसे देखकर पत्नी डर जाएगी और आगे से काम पर जाने के लिए नहीं कहेगीं। घर जाकर उसने सांप को पत्नी को दिखाते हुए कहा, ये कमाकर लाया हूं। पत्नी ने लाठी को पकड़ा और सांप को घर की छत पर फैंक दिया।वह सोचने लगी कि मेरे पति की पहली कमाई जो कि एक मरे हुए सांप के रूप में मिली, ईश्वर जरुर इसका फल हमें देगें क्योंकि मैंने सुना हैं कि कर्म का महत्व होता हैं। वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। तभी एक बाज़ उधर से उड़ते हुए निकला जिसने चोंच में एक कीमती हार दबा रखा था। बाज़ की नजर छत पर पड़े हुए सांप पर पड़ी उसने हार को वहीं छोड़ा और सांप को लेकर उड़ गया। पत्नी ने हार को पति को दिखाते हुए सारी बात बताई। पति अब कर्म के महत्व को समझ चुका था, उसने हार को बेचकर अपना व्यवसाय शुरू किया। कल का एक गरीब इन्सान आज का सफल व्यवसायी बनकर इज्जत की जिंदगी जी रहा है। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा पीछे रहता हैं, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल रहता हैं। पैर मिले हैं चलने को तो, पांव पसारे मत बैठो, आगे-आगे चलना हैं तो, हिम्मत हारे मत बैठो।

राफ्टिंग का आनंद

पर्यटक तुलुप जिले में तुरुवार को नवाली के पास खास नदी में रिवर राफ्टिंग का आनंद लेते हुए।

आज की पाती

क्यों थम गए पाकिस्तान के परमाणु धमकी के बोल?

बहुत सारे बड़बोले पाकिस्तानी नेता, उग्रवादी व सेना के लोग अक्सर भारत को परमाणु बम की खोखली धमकियां देते रहे हैं। जवाब में भारत भी तुरंत कह देता है कि अगर पाकिस्तान हमारे विरुद्ध परमाणु अस्त्रों का प्रयोग करने का दु साहस करेगा, तो हम पाकिस्तान को तबाह करते हुए समूल ही नष्ट कर देंगे। आश्चर्यजनक रूप से पिछले लगभग एक महीने से हालात और भारत के बयान बिल्कुल ही बदल गए हैं। भारत सरकार के अधिकारी यही कहते हैं कि हम पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। ऐसा लगता है कि भारत सरकार और सेना की ओर से कुछ ठोस उपाय किए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब पाकिस्तान से आने वाली ऐसी धमकियों पर कुछ हद तक रोक लगी है। भारतीय लोगों को एकजुट रहकर, संयम बनाए रखने की जरूरत है। - प्रदीप आर्य, भिलाई

ट्रेंड

घरेलू प्रणालियां मजबूत

आज हम विकिरणयुक्त विज्ञान या तिहाल स्थिरता नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम नये युग की युद्ध तकनीक के लिए भी तैयार हो रहे हैं। हमारी घरेलू प्रणालियों ने यह साबित किया है कि हम दुश्मन के किसी भी कदम को भेदने की ताकत रखते हैं।
- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

मल्चिंग पेपर तकनीक

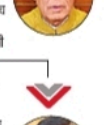

नागपुर के धापेवाड़ा स्थित हमारे नवीन पार्क में मेरी पत्नी सावन ने छह अनूठा प्रयोग करते हुए, मल्चिंग पेपर तकनीक का इस्तेमाल कर छह किलो तक वजन वाले ऑर्गेनिक प्याज का सफल उत्पादन किया है। इससे खरपतवार नहीं उगती है।
-नितिन गडकरी, केंद्रीय राजमार्ग मंत्री

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और अब योग हमारी जीवनशैली का अविभाज्य अंग बन चुका है। हरियाणा भी 21 जून को 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्साहित है।
- नायब सिंह सैनी, सीएम, हरियाणा

पुंछ को पुनर्वास पैकेज मिले

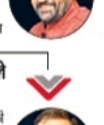

पुंछ का दर्द वहां जाकर ही महसूस होता है। अखबार नहीं, सरकार को जिलेवारी की याद दिला रहा हूं कि पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित इलाकों के लिए ठोस, उदार और तात्कालिक राहत व पुनर्वास पैकेज तैयार किया जाए।
- राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

करंट अफेयर

अमेरिका में कोविड टीका बच्चों को अनिवार्य नहीं

अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा (एचएचएस) मंत्री रॉबर्ट एफ. कैनेडी जूनियर ने 27 मई, 2025 को घोषणा की कि रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीएस)अब स्वस्थ बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित टीकाकरण की सूची में कोविड-19 के टीके को शामिल नहीं करेगा। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा एक वीडियो में की गई यह घोषणा 20 मई को की गई एक अन्य घोषणा की पृष्ठभूमि में आई है, जिसमें खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खुलासा किया था कि वह केवल 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वयस्कों और गंभीर कोविड-19 के सबसे अधिक जोखिम वाले लोगों के लिए ही टीके के नए संस्करणों को मंजूरी देगा। एफडीए ने टीके निर्माताओं से यह अपेक्षा की है कि वे विकिरसीय परीक्षण करें, ताकि यह साबित किया जा सके कि टीका कम जोखिम वाले समूहों के लिए लाभकारी है। द कन्वर्सेशन की अमेरिकी इकाई ने जन स्वास्थ्य संवर्धन से जुड़ी पहुंच विश्वविद्यालय की नर्सिंग प्रोफेसर लिबी रिचर्ड्स से पूछा कि वे बताएं कि आम जनता के लिए इन घोषणाओं का क्या अभिप्राय है। क्यों एचएचएस और एफडीए पूर्व की व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं ?

ऑफ बीट

चिर तनाव है मनोभ्रंश जोखिम का कारक

किसी भी अमेरिकी व्यक्ति के अपने जीवनकाल में मनोभ्रंश से ग्रस्त हो जाने की संभावना पहले की अपेक्षा कहीं अधिक हो सकती है। एक अध्ययन में पाया गया कि 55 से 95 वर्ष तक की आयु के लोगों में मनोभ्रंश विकसित होने की औसत संभावना 42 प्रतिशत थी। चिर तनाव संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से लोगों की उम्र बढ़ने में क्या भूमिका निभा सकता है तथा उनमें मनोभ्रंश का जोखिम भी कितना बढ़ा सकता है। हालिया शोध से पता चलता है कि वर्तमान में मध्यम आयु वर्ग या उससे अधिक उम्र के अमेरिकी लोग पिछली पीढ़ियों की तुलना में अधिक बार तनावपूर्ण घटनाओं का अनुभव करते हैं। शोध के एक मजबूत निष्कर्ष ने कम से कम 14 विभिन्न कारकों के महत्व पर प्रकाश डाला है जो अल्जाइमर रोग- मनोभ्रंश का एक सामान्य और विनाशकारी रूप - और मनोभ्रंश के अन्य रूपों के आपके जोखिम से संबंधित है। हालांकि इनमें से कुछ कारक आपके नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, जैसे कि मधुमेह या अवसाद। इनमें से कई कारक उन चीजों से संबंधित हैं जो लोग करते हैं, जैसे कि शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ भोजन और सामाजिक जुड़ाव।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 88

प्रत्यक्ष प्रभाव

वर्ष 2024-25 के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के आंकड़ों ने जनता और नीति-निर्माता, दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वर्ष के दौरान जहां सकल स्तर पर एफडीआई से भारत ने 81 अरब डॉलर की राशि जुटाई वहीं विशुद्ध स्तर पर केवल 0.35 अरब डॉलर हासिल हुए जो बीते दो दशक का सबसे निचला स्तर है। विशुद्ध एफडीआई का स्तर इतना कम इसलिए रहा क्योंकि विदेशी कंपनियों ने जमकर विनिवेश किया और प्रत्यावर्तन किया।

यहां प्रत्यावर्तन से तात्पर्य अपने मूल देश में धन वापस भेजना है। इसके अलावा भारतीय कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर विदेश में निवेश करना भी एक वजह रही। विगत वित्त वर्ष में विदेशी कंपनियों ने करीब 51 अरब डॉलर की राशि अपने देश भेजी जो बीते दो दशक से भी अधिक समय का उच्चतम स्तर है। इस बीच भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में किया जाने वाला निवेश पिछले साल की तुलना में करीब 75 फीसदी बढ़कर 29.2 अरब डॉलर हो गया। इसके परिणामस्वरूप विशुद्ध स्तर पर बहुत कम राशि बची। सामान्य समय में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्वदेश धन भेजना या भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में निवेश करना भारत जैसी बड़ी और खुली अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। कुछ विदेशी कंपनियां अपनी खास वजहों से मुनाफा अपने देश भेजती हैं, दूसरी तरफ बढ़ती भारतीय कंपनियां विदेशों में मिल रहे अवसरों का लाभ लेना चाहती हैं। बहरहाल जो बात ध्यान आकर्षित कर रही है और चिंता की वजह बनी है, वह है बाहर जाने वाली राशि का पैमाना। वर्ष 2023-24 में सकल एफडीआई महज 71 अरब डॉलर था लेकिन उस साल भारत के पास विशुद्ध एफडीआई के रूप में 10 अरब डॉलर बचे थे। यह भी ध्यान देने लायक बात है कि विदेशी कंपनियों द्वारा जहां धन वापस भेजने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वहीं दूसरे देशों में भारतीय कंपनियों की एफडीआई में भी गत वर्ष उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। वित्त मंत्रालय की ताजा मासिक समीक्षा में भी इस घटनाक्रम पर गौर किया गया और कहा गया, 'भारतीयों द्वारा विदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्त वर्ष 25 में करीब 12.5 अरब डॉलर तक बढ़ा। यह तब हुआ जबकि विश्व स्तर पर अनिश्चितता का माहौल था। ऐसे में घरेलू निवेश को लेकर उनकी सतर्कता के चलते इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।'

यह समूचा घटनाक्रम यकीनन जांच करने लायक है। इस संदर्भ में नीति-निर्माता विदेशी और भारतीय कंपनियों के लिए मामले से अलग तरह से निपट सकते हैं। विदेशी कंपनियां प्राथमिक तौर पर भारत इसलिए आईं ताकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा कर सकें। चूंकि भारत दुनिया का सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है और खबरों के मुताबिक वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है तो फिर विदेशी कंपनियां अपना अधिशेष यहीं भारत में क्यों नहीं निवेश कर रही हैं? इस बात की संभावना नहीं है कि धन का प्रत्यावर्तन केवल शेयरधारकों को रकम लौटाने के लिए हो रहा है। कुछ कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी कम कर रही हैं क्योंकि उन्हें बेहतर मूल्यांकन की उम्मीद है। परंतु इससे भी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। इसकी गहन जांच आवश्यक है कि कहीं वे कारोबारी माहौल के कारण या मांग की हालत के चलते तो नहीं जा रहीं? भारतीय कंपनियों की स्थिति तो और रहस्यमय है। वे भारत में निवेश की इच्छुक नहीं हैं लेकिन उन्हें इस अनिश्चित समय में भी विदेश में अवसर मिल रहे हैं। बहरहाल बाहर जाने वाले एफडीआई में इजाफा एकबारगी घटना हो सकती है। वर्ष 2018-19 और 2023-24 में क्रमशः 12 अरब डॉलर और 18 अरब डॉलर की राशि बाहर गई जो 2024-25 में करीब 29.2 अरब डॉलर हो गई। इस मसले की गहन जांच आवश्यक है। परंतु इसके चलते सरकार और नियामकों को विदेशी या घरेलू कंपनियों के विदेश फंड स्थानांतरित करने पर रोक नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इससे निवेश का माहौल प्रभावित होगा।

भारत को लगातार उच्च वृद्धि के लिए उच्च निवेश की आवश्यकता है। इसमें एफडीआई की अहम भूमिका होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ तकनीक और बेहतरीन कार्य व्यवहार भी लाती हैं। यह बचत-निवेश के अंतर को पाटने का भी बेहतर तरीका है क्योंकि एफडीआई विदेशी पूंजी का सबसे स्थिर स्वरूप है। ऐसे में यह अहम है कि इस तरह के निवेश गणित को समझा जाए और नीतिगत खामियों को दूर किया जाए।

भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेश से उठे सवाल

भारतीय कंपनियों द्वारा तेजी से विदेशी निवेश किया जाना यह सवाल पैदा करता है कि क्या वे घरेलू परियोजनाओं में और अधिक निवेश की इच्छुक नहीं हैं? इस पर रोशनी डाल रहे हैं ए के भट्टाचार्य

गत वित्त वर्ष में भारत में विशुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की आवक में 96 फीसदी की गिरावट क्यों आई? वर्ष 2024-25 में यह करीब 0.35 अरब डॉलर रहा जो इसके पिछले वर्ष 10.13 अरब डॉलर था। यह केवल एक साल में रिकार्ड गिरावट नहीं थी बल्कि विगत दो दशकों में देश में विशुद्ध एफडीआई की आवक का भी सबसे निचला स्तर था।

आंकड़ों का विश्लेषण बताता है कि इस तेज गिरावट के लिए दो कारक जिम्मेदार थे: पहला, मौजूदा कंपनियों में विदेशी निवेशकों द्वारा प्रत्यावर्तन (धन को अपने मूल देश भेजना) और विनिवेश में 16 फीसदी का इजाफा हुआ और ये 51.5 अरब डॉलर हो गया। दूसरा, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में किए जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 75 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 29 अरब डॉलर हो गया। ध्यान रहे कि 2024-25 में सकल एफडीआई आवक करीब 81 अरब डॉलर थी जो उससे पिछले वर्ष की तुलना में 14 फीसदी अधिक थी। परंतु भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में एफडीआई और प्रत्यावर्तन में इजाफे के कारण सकल एफडीआई से हुए लाभ निष्फल हो गए।

महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भारत में आने वाले एफडीआई और देश से बाहर जाने वाले एफडीआई में एक उल्लेखनीय समानता देखी गई। भारत में आने वाले एफडीआई का करीब 60 फीसदी सिंगापुर, मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड और अमेरिका से आता है।

वहीं 2024-25 में भारत से बाहर जाने वाले एफडीआई में करीब 50 फीसदी इन्हीं पांच देशों में गया। हालांकि, एफडीआई की आवक और उसके बहिर्गमन से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में उतनी समानता नहीं है। देश में आने वाला सकल एफडीआई विनिर्माण, वित्तीय सेवा, ऊर्जा, संचार सेवाओं में केंद्रित रहा और ऐसी आवक का 60 फीसदी इन्हीं क्षेत्रों में गया। इसके विपरीत बाहर जाने वाले एफडीआई में 90 फीसदी से अधिक वित्तीय सेवा क्षेत्र जिसमें बैंकिंग और बीमा शामिल हैं, विनिर्माण, थोक एवं खुदरा व्यापार, रेस्तरां और होटल आदि में गया।

अपने ताजा मासिक बुलेटिन में रिजर्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि बढ़ता प्रत्यावर्तन और बाहर जाने वाली एफडीआई चिंता का विषय नहीं है। इसके विपरीत उसका तर्क है कि विशुद्ध बहिर्मुखी एफडीआई और प्रत्यावर्तन दोनों में इजाफा एक परिपक्व बाजार का संकेत है जहां विदेशी निवेशक सहजता से आ और जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी सकारात्मक है। यह एक वाजिब आकलन हो सकता है। परंतु क्या यह रुझान वास्तव में चिंता का विषय नहीं है? इस सवाल को हल करने के लिए देश में आने वाले और बाहर जाने वाले एफडीआई के दीर्घकालिक रुझान का आकलन करना होगा।

बीते दो दशकों में देश में सकल एफडीआई की आवक वैश्विक आर्थिक माहौल की प्रकृति को दर्शाती है। 2000 के दशक के आरंभ में इन्होंने जोर पकड़ा। यह वह दौर था जब पूरी दुनिया में उच्च वृद्धि के हालात थे। उसके बाद उत्तर अटलांटिक वित्तीय संकट के तत्काल बाद के वर्षों में इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली। उसके बाद के वर्षों में सकल एफडीआई आवक में सुधार हुआ लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बॉन्ड खरीद कम करने की घोषणा के बाद इसे झटका लगा। हालांकि 2014-15 के बाद एफडीआई की आवक में तेज वृद्धि होती रही। संयोगवश यह वही समय था जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला। सकल एफडीआई आवक में वृद्धि कोविड महामारी के वर्षों में भी कम नहीं हुई। महामारी के बाद 2022-23 और 2023-24 में जरूर इसमें गिरावट आई लेकिन पिछले साल यह रुझान भी पलट गया।

परंतु अर्थव्यवस्था के अधिकांश पर्यवेक्षकों ने इस तथ्य की अनदेखी कर दी कि प्रत्यावर्तन और बाहर जाने वाले एफडीआई में भी कोविड के बाद के वर्षों में तेजी से इजाफा हुआ। 2020-21 और 2021-22 में सकल एफडीआई की आवक पर प्रत्यावर्तन और बाहर जाने वाले निवेश ने क्रमशः 46 फीसदी और 54 फीसदी का विपरीत असर डाला। अगले तीन साल के दौरान इसका असर बढ़ा। 2022-23 में इससे 61 फीसदी, 2023-24 में 86 फीसदी और 2024-25 में 99 फीसदी का विपरीत असर हुआ। दूसरे शब्दों में इससे विशुद्ध एफडीआई आवक में कमी आने लगी।

यह समस्या कुछ समय पहले तक इतनी गंभीर नहीं थी। जैसा कि करीब एक साल पहले इन्हीं पन्नों पर लिखा गया था, 2019-20 में प्रत्यावर्तन और विनिवेश की राशि करीब 18 अरब डॉलर थी यानी सकल एफडीआई आवक का करीब 25 फीसदी। परंतु कोविड के बाद के दो साल में प्रत्यावर्तन और विनिवेश बढ़कर सकल एफडीआई आवक के 33-34 फीसदी तक पहुंच गया। वर्ष 2023-24 में तो यह चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया जब सकल एफडीआई में प्रत्यावर्तन और विनिवेश का हिस्सा 62 फीसदी हो गया। 2024-25 में यह और बढ़कर 63 फीसदी तक पहुंच गया।

भारतीय कंपनियों में निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों ने यहां होने वाले लाभ को वापस अन्य बाजारों में निवेश करने की प्राथमिकता दिखाई है। ध्यान देने लायक बात यह है कि यह रुझान बीते दो साल से बरकरार है। स्पष्ट है कि वे ऐसे निवेश से होने वाली आय को अपनी मौजूदा परियोजनाओं में निवेश करने या भारत में नई पहलों में लगाना पसंद नहीं कर रहे।

यकीनन मौजूदा विदेशी निवेशकों द्वारा अपनी आय को दोबारा निवेश किए जाने का स्तर सकल एफडीआई आवक के एक तिहाई से भी कम रहा है। उनकी ओर से ऐसी कोई इच्छा भी नहीं नजर आई है कि वे पुनर्निवेशित आय में इजाफा करें। एफडीआई से होने वाला लाभ उस समय अधिक होता जबकि पुनर्निवेशित आय उच्च दर से बढ़ती और प्रत्यावर्तन की गति धीमी होती।

विशुद्ध एफडीआई आवक के मोर्चे पर ऐसी निराशाजनक अनुमान में पिछले वर्ष के आंकड़े बढ़त करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे भारतीय कंपनियां देश से बाहर के अपने निवेश में इजाफा कर रही हैं। भारतीय कंपनियों ने कोविड के बाद बाहर एफडीआई बढ़ाया है। वर्ष 2022-23 के 14 अरब डॉलर से बढ़कर 2023-24 में यह 16.6 अरब डॉलर और 2024-25 में 29 अरब डॉलर हो गया। यह ऐसे समय पर हुआ जब भारत का उद्योग जगत देश में निवेश करने को लेकर ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहा।

यह देखना सुखद है कि भारत का उद्यम जगत विभिन्न देशों में निवेश करके वैश्विक छाप छोड़ रहा है। यकीनन बीते कुछ सालों में विदेशी कंपनियों के अधिग्रहण या बड़ी मात्रा में भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में निवेश की खबरें भी आई हैं। इनमें डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, जायडस लाइफसाइंसेज, सन फार्मा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, कोफोर्ज, एवरटेल, टाटा स्टील, टाटा ग्राउप्स, सीना, एचईजी और पीआई इंडस्ट्रीज शामिल हैं। कई अन्य कंपनियां विदेश में निवेश या अधिग्रहण की योजना बना रही हैं।

परंतु इसके साथ ही चिंता की बात यह भी है कि भारतीय उद्यमी जगत घरेलू निवेश को लेकर ऐसा उत्साह नहीं दिखा रहा है। सरकार को पता लगाना चाहिए कि उन्हें घरेलू बाजार में निवेश करने में क्या समस्याएं आ रही हैं। अगर कारोबारी सुगमता में दिक्कत है या फिर अगर बहुचर्चित कारक बाजार सुधार की अनुपस्थिति समस्या की वजह है तो इन दिक्कतों को दूर किया जाना चाहिए।

जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा कितना फायदेमंद?

हम सभी जानते हैं कि देश में विभिन्न बैंक शाखाओं पर बीमा एवं म्युचुअल फंड योजनाएं कैसे गलत तरीके से और ग्राहकों को पूरी बात बताए बिना बेची जाती हैं। मगर यह कहानी का केवल एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू यह है कि इसमें पीड़ित व्यक्ति ज्यादातर वे लोग होते हैं जो सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं।

इस संदर्भ में दो बीमा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का जिक्र करना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को यह नहीं मालूम होता है कि वे बीमा पॉलिसियों के रूप में क्या खरीद रहे हैं और क्यों।

पीएमजेजेबीवाई एक जीवन बीमा योजना है जिसमें एक साल का टर्म (सावधि) जीवन बीमा का लाभ मिलता है। इसका हरेक साल नवीकरण होता है और बीमित व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं। इस योजना के लिए सालाना 436 रुपये प्रीमियम का भुगतान करना होता है। शुरू में इसका प्रीमियम 330 रुपये ही था मगर जून 2022 में इसे बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया गया।

पीएमएसबीवाई सरकार समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है जिसके तहत दुर्घटनावश होने वाली मौत एवं विकलांगता पर कवर मिलता है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए है और प्रीमियम राशि 20 रुपये सालाना है। इसमें दुर्घटना में मौत या दोनों आंखों या हाथों/पांवों के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बीमित व्यक्ति को 2 लाख लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये दिए जाने के प्रावधान हैं।

पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई, दोनों ही पिछले एक दशक से भी अधिक समय से प्रभाव में हैं। वर्ष 2015 के केंद्रीय बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकी घोषणा की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में इनकी शुरुआत की थी।

सभी बचत बैंक खाताधारक (18-50 वर्ष) इन दोनों ही योजनाओं के लिए योग्य हैं। प्रीमियम उनके खाते से स्वतः ही कट जाते हैं। यहीं से समस्या शुरू होती है मगर इस पर बाद में चर्चा होगी। दोनों ही बीमा योजनाओं के खरीदार या लाभार्थी मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाता धारक हैं। सभी सरकारी लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से इन खातों के जरिये भेजे जाते हैं।

मई 2023 में पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई की आठवीं वर्षगांठ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 26 अप्रैल 2023 तक पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 16.2 करोड़ और 34.2 करोड़ थी। पीएमजेजेबीवाई योजना ने 6,64,000 लोगों को महत्त्वपूर्ण आर्थिक मदद पहुंचाई है जिन्हें उनके दावे के मद में 13,290 करोड़ रुपये भुगतान हो चुके हैं। पीएमएसबीवाई योजना के अंतर्गत कम से कम 1,15,000 परिवारों को 2,302 करोड़ रुपये के दावे निपटाए जा चुके हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 34.48 करोड़ खाताधारक पीएमजेजेबीवाई के लाभार्थी थे। सरकार पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत अतिरिक्त 4.07 करोड़ और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत अतिरिक्त 6.34 करोड़ और लोगों को लाना चाहती है।

फरवरी के अंत तक पीएमजेजेबीवाई में कुल 9,27,980 दावे प्राप्त हुए थे। उनमें 8,95,477 दावे निपटाए जा चुके हैं और 17,910 करोड़ रुपये भुगतान किए जा चुके हैं। पीएमएसबीवाई के मामले में 2,03,697 दावे आए जिनमें 1,53,108 दावे निपटाए जा चुके हैं।

यानी दावा-निपटान अनुपात काफी अधिक है। मगर ये आंकड़े वास्तविक कहानी बयां नहीं करते हैं। बैंक अधिकारी तो दोनों योजनाओं की सफलता को बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं मगर जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। लाखों लोग तो दावे ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वे किसी ऐसी योजना के लाभार्थी हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उनके खातों से रकम क्यों कट जाती है।

बैंकिंग साख

तमाल बंद्योपाध्याय

इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बुनियादी खामियां हैं। अलग से देखें तो इन योजनाओं से जुड़े आंकड़े न तो इन तक लोगों की पहुंच और न ही इनके प्रभाव को दर्शाते हैं। मगर सरकार की तरफ से लक्ष्य हासिल करने के दबाव में आकर बैंक अपने ग्राहकों को पूरी बात समझाए या बिना बताए ही इन योजनाओं की बिक्री कर रहे हैं।

ज्यादातर पॉलिसीधारकों को यह पता ही नहीं होता है कि वे बीमा लाभ के दायरे में हैं। बैंक ग्राहकों की जानकारियां बैंक-एंड टीम को भेज देते हैं और प्रीमियम स्वतः कटते जाते हैं और मगर इसकी जानकारी पॉलिसीधारक को नहीं दी जाती है।

ज्यादातर बीमित व्यक्तियों या उनके परिवारों को बीमा कवर के बारे में मालूम नहीं होता है इसलिए वे कोई दावे भी नहीं करते हैं। जिन लोगों के एक से अधिक खाते होते हैं उनके खातों से एक ही पॉलिसी के लिए कई बार अलग-अलग प्रीमियम कट जाते हैं। कई बार तो शहरी क्षेत्रों में अमीर लोगों की जमा (डिपॉजिट) से भी पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के प्रीमियम काट लिए जाते हैं!

यही नहीं, जो लोग दावा करना चाहते हैं उनके लिए पूरी प्रक्रिया काफी जटिल है। मामूली कागजी मसलों की आड़ में दावे अक्सर अस्वीकार कर दिए जाते हैं। ग्रामीण शाखाएं कम पढ़े-लिखे लोगों का साथ देने के बजाय उन्हें अकेले ही कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए छोड़ देती हैं।

ये दोनों ही योजनाएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उदाहरण का अनुसरण क्यों नहीं करती हैं? जब कभी भी किसी क्षेत्र में बाढ़ या सूखे की नौबत आती है तो बैंक स्वतः ही किसानों को फसल बीमा का लाभ दे देते हैं। इसी तर्ज पर किसी व्यक्ति की मौत या उसके साथ दुर्घटना होने की खबर पाकर बैंक खुद ही प्रभावित परिवार के खातों में रकम भेज सकते हैं।

जहां वाजिब दावाकर्ताओं को मशक्कत झेलनी पड़ती है, वहीं फर्जीवाड़ा करने वाले लोग इस पूरी प्रणाली में खामियों का बेजा फायदा उठा ले जाते हैं। ऐसी कई खबरें आई हैं जिनमें दावे करने के लिए मृतक लोगों के नाम पर बीमा कराए गए हैं।

बड़ा सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं वाकई लोगों को फायदा पहुंचाती हैं या सरकारी रिपोर्ट में महज खानापूर्ति करने वाले आंकड़े होते हैं? ये दोनों ही योजनाएं निम्न आय वाले परिवारों की वित्तीय संकट से सुरक्षा के लिए शुरू की गई थीं। मगर उनके बीच जागरूकता कम रहने, फर्जीवाड़ा होने और वाजिब दावे खारिज होने से सारे प्रयास बेकार हो जाएंगे।

कुछ ठोस तरीके अपनाकर इन योजनाओं से जुड़ी समस्याएं दूर की जा सकती हैं। सबसे पहले तो बैंकों एवं उनके बीमा साझेदारों को लाभ और दावे करने की प्रक्रिया के बारे में पॉलिसीधारकों एवं उनके परिवारों को पूरी बात बतानी चाहिए। दावा निपटान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनाई जानी चाहिए। इसके साथ फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सत्यापन एवं तथ्यों की जांच के लिए एआई आधारित तकनीक अपनाई जानी चाहिए। इन योजनाओं में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए निजी बीमा कंपनियों को आगे आने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। एआई की मदद से बैंक कोई घटना होने पर दावों के स्वतः निपटारे और लाभार्थी के खाते में रकम भेजने की प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं।

अगर बैंक प्रीमियम काटने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर तकनीक की मदद से लाभार्थियों को यह क्यों नहीं बता सकते कि उनके खाते से रकम क्यों कट रही है? वे जरूरत के समय लाभार्थियों को बीमा लाभ क्यों सुनिश्चित नहीं कर सकते?

(लेखक जन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार हैं)

आपका पक्ष

कोविड से निपटने के लिए बीमा व्यवस्था में बदलाव हो

इस समाचार में प्रकाशित रिपोर्ट 'क्या कोविड से निपटने को तैयार हैं आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी?' बहुत महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा करता है जो सामान्य जनमानस और जन-जीवन को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां बीमारियों के मामले में इतनी शर्तें लगाती हैं कि रोगी के पास कुछ विशेष बीमारियों के ही विकल्प हैं और उनके साइड इफेक्ट वाली बीमारियां बीमा से कवर नहीं होती। कोविड महामारी के इतने वेरिएंट और शरीर पर इतने साइड इफेक्ट हैं कि उनको समझना और बीमा पॉलिसी में सम्मिलित करना कठिन है। तो क्या बीमा पॉलिसियां स्वयं बीमार हैं और क्या यह लोगों की विवशता पर लाभ अर्जित करने वाले व्यापारिक उपक्रम हैं? बीमा पॉलिसियों को जनहित में व्यापक करने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को बड़े सुधार करने चाहिए। बेहतर है कि राज्य और केंद्र सरकारें आयुष्मान बीमा योजना को अधिक व्यापक करें भले ही 70 वर्ष से कम आयु की जनता को कुछ अधिक प्रीमियम देना पड़े। दूसरा विकल्प यह है कि सभी निजी अस्पताल अपने नियमित व्यापक पैकेज बनाने के लिए बाध्य हों जो बीमा पॉलिसियों से मुक्त हों और सभी बीमारियों पर लागू हों, जिससे रोगी को अपने सामर्थ्य और आर्थिक सीमा का पता हो। हर व्यक्ति बीमा पॉलिसी नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास इतनी आर्थिक सामर्थ्य नहीं होती और ग्रामीण क्षेत्रों में यह संभव भी नहीं है। बीमा क्षेत्र बड़े सुधारों की बाट जोह रहा है।

विनोद जौहरी, दिल्ली

कोविड महामारी के इतने वेरिएंट और साइड इफेक्ट हैं कि उनको समझना और बीमा पॉलिसी में सम्मिलित करना कठिन है

बीज उत्पादन में किसानों की भागीदारी बढ़े

सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को प्रमाणित व ब्रांडेड बीज प्रदान करने एवं बीज गुणवत्तायुक्त हो, इसके लिए किसानों का पंजीयन करके उन्हें प्रशिक्षण देने की पहल करनी जरूरी है। दरअसल, आज भी करोड़ों किसान गुणवत्ता युक्त बीजों की कमी, समय पर बीजों का नहीं मिलना और उचित दाम नहीं मिलने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। बोआई के समय अगर उन्हें सही बीज नहीं मिलते हैं तो उनकी मेहनत और उम्मीद दोनों पर पानी फिर जाता है। इसका सीधा असर न केवल किसान की आमदनी पर, बल्कि देश की कुल कृषि उत्पादकता पर भी पड़ता है। बीज उत्पादन में किसानों की भागीदारी बहुत कम है। इसकी मुख्य वजह संसाधनों की कमी, तकनीकी जानकारी का अभाव और बाजार तक सीधी पहुंच न होना है। कई किसान आज भी परंपरागत बीजों और पद्धतियों पर निर्भर हैं, क्योंकि वे बीज क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली नवीनतम तकनीकों से अज्ञान हैं। उन्नत किस्मों के बीजों की जानकारी और उपलब्धता तक उनकी पहुंच सीमित है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है और आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। अतः सहकारी समितियों को न केवल एक बीज उत्पादक और विपणन संस्था के रूप में काम करना होगा बल्कि इन्हें किसानों की आत्मनिर्भरता का भी माध्यम बनना होगा। सहकारी समितियों के सहयोग से बीज उत्पादन का एक सशक्त ढांचा तैयार किया जाना चाहिए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

स्पेन का युद्धपोत ईएसपीएस रीना सोफिया (एफ84) गुरुवार को मुंबई पहुंचा। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हवें डेलिफन ने इसका स्वागत किया और उन्होंने रियर एडमिरल डेविड दा पोजो से मुलाकात की।